रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-73

REGISTERED No D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 1976/फाल्गुन 23, 1897

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 1976/PHALGUNA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भागII—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रीमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1976

का० आ० 1012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० जी० सामन्त, अधिवक्ता, बम्बई को, बम्बई उच्च न्यायालय में श्री एम० एम० मनसुखानी के विरुद्ध राज्य द्वारा दायर की गई अपराधीय अपील तथा आर० सी० नं० 59/71-विशेष पुलिस स्थापना बम्बई में अभियुक्तों द्वारा दायर की गई अपीलों का कार्य संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजनक नियुक्त करती है ।

[संख्या 225/9/76-ए०वी०डी-II]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 25th February, 1976

S.O. 1012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri S. G. Samant, Advocate, Bombay, as a Special Public Prosecutor to conduct the criminal appeal filed by the State against Shri M. M. Mansukhani and the appeals filed by the accused persons in R. C. No. 59/71-SPE-Bombay, in the High Court of Bombay.

[No. 225/9/76-AVD. II]

आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

का० आ० 1013.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केरल राज्य की सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का पुरावस्तु (निर्यात-नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 31) की धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराधों, और उक्त अपराधों के बारे में या सम्बन्ध में प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यन्त्रों और 6 जुलाई, 1974 को 32 और 16 पुरावस्तुओं की शिपिंग-बिल नम्बर क्रमश : 555 और 556 दिनांक 6 जुलाई, 1974 के जरिए कोचीन से पश्चिम जर्मनी को निर्यात करने के प्रयत्नों एवं उसी संव्यवहार के

अनुक्रम में किये गये किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिये, समस्त केरल राज्य में विस्तार करती है ।

[संख्या 228/23/75-ए०वी०डी०-II]

बी०सी०वंजानी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of the State of Kerala, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Esablishment to the whole of the State of Kerala for the investigation of offences punishable under section 5 of the Antiquities (Export Control) Act, 1947 (31 of 1947), and attempts, abetments, and conspiracies in relation to, or in connection with, the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction, in regard to the attempts to export from Cochin to West Germany of 32 and 16 items of antiquties on the 6th July, 1974 covered by Shipping Bill Nos. 555 and 556 dated the 6th July, 1974, respectively.

[No. 228/23/75-AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

का० आ० 1014—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 124-बालासिनोर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव वाले उम्मीदवार श्री महेन्द्रकुमार जयन्तीलाल शाह, पटवाशेरी, बालसिनोर, जिला कैरा (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अनेक निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेन्द्रकुमार जयन्तीलाल शाह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० गुज०/वि०स०/124/75(19)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1976

S.O. 1014.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahendrakumar Jayantilal Shah, Patvasheri, Balasinor, District Kaira (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 124-Balasinor constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahendrakumar Jayantilal Shah to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ/LA/124/75(19)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

आयकर

का० आ० 1015—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, अनुमोदित किया गया है :—

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम : रोग लक्षण—भेषजगुण विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र पर विशेष बल देते हुए, नए औषधि द्रव्यों का अनुसंधान और विकास

(क) प्रायोजक :

(1) वेदराज भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट, चुरू, राजस्थान

(2) ईस्ट इण्डिया कमर्शियल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, 38, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।

(3) कटलर हैमर इण्डिया लिमिटेड, 38, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।

(4) ईस्ट इण्डियन काटन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 38, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।

(5) फायबर प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, 38, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।

(ख) प्रायोजन का स्थान :

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110016

अनुसंधान कार्यक्रम की अवधि : 24-12-1975 से पांच वर्ष

प्राक्कलित व्यय : 35 लाख रु०

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, नई दिल्ली को, जहां उपर्युक्त कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(2) के अधीन, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1174—फा० सं० 203/183/75-आई० टी० ए०-II, 24 दिसम्बर, 1975 के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है।

[सं० 1182—फा०सं० 203/183/73-आई०टी०ए०-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 31st December, 1975

INCOME-TAX

S.O. 1015.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 by the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi :

Scientific Research Programme:	Research and Development of New Drugs with emphasis on Clinical Pharmacology and Therapeutics.
Sponsored (a) by :	(i) Dedraj Bhartia Charitable Trust, Churu, Rajasthan.
	(ii) East India Commercial Company Pvt. Ltd., 38, Netaji Subhash Road, Calcutta.
	(iii) Cutler Hammer India Limited, 38, Netaji Subhash Road, Calcutta.
	(iv) East India Cotton Manufacturing Co. Ltd., 38, Netaji Subhash Road, Calcutta.
	(v) Fibre Processors Pvt. Limited, 38, Netaji Subhash Road, Calcutta.
Sponsored (b) at :	All-India Instiiute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi-110016.
Duration of Research Programme :	Five years w.e.f. 24-12-1975.
Estimated expenditure:	Rs. 35 lakhs.

All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where the above programme has been sponsored has been approved under section 35(1) (ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance Notification No. 1174—F. No. 203/183/75-ITA-II dated the 24th December, 1975.

[No. 1182—F. No. 203/183/75-ITA-II]

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1976

का०आ० 1016.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर, अधिसूचना संख्या 52(फा०सं०-10/3/67-आई०टी०ए०II) तारीख 10 जून, 1968 द्वारा एन० एम० वाडिया इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलोजी, पूणे के, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (I) (II) के अधीन 1 अप्रैल 1968 से दिया गया अनुमोदन 31 जनवरी, 1976 से वापिस लिया जाता है ।

[सं० 1208—फा०सं० 203/8/76-आई०टी०ए०-II]

New Delhi, the 19th January, 1976

S.O. 1016.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to N. M. Wadia Institute of Cardiology, Poona by notification No. 52 (F. No. 10/3/67-ITA. II) dated the 10th June, 1968 with effect from 1st April, 1968 is withdrawn with effect from 31st January, 1976 on the recommendation of the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

[No. 1208—F. No. 203/8/76-ITA.II]

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1976

का०आ० 1017.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (I) के खण्ड (iii) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया है ।

(1) कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा, इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों के पृथक लेखे रखेगा ;

(2) कि ऐसी निधियों का उपयोग केवल, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान उन्नयन के लिए किया जाएगा ; और

(3) कि यह संस्थान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी जिसमें इस छूट के अधीन संगृहीत निधियां और वह रीति जिसमें उन निधियों का उपयोग किया गया दिखाई जाएगी ।

संस्था

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1209—फा०सं० 203/151/75/आ०क०अ०-II]

New Delhi, the 20th January, 1976

S.O. 1017.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following three conditions :—

(1) That the Indian Institute of Foreign Trade shall maintain separate accounts of the funds collected by them under the exemption;

(2) That such funds shall be utilized exclusively for promotion of research in social sciences; and

(3) That the institute shall send an Annual Report to the Indian Council of Social Science Research showing the funds collected under the exemption and the manner in which the funds were utilized.

INSTITUTION

INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE, NEW DELHI

This notification will be effective from 1st April, 1975.

[No. 1209—F. No. 203/151/75-ITA. I]

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1976

का०आ० 1018.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) (iii) के प्रयोजनार्थ प्रबन्ध विकास संस्थान, उ० प्र० लखनऊ को अनुमोदित करने वाली अधिसूचना सं० 1095(फा०सं० 203/42/75-आई० टी० ए० II) तारीख 25-9-1975, 1-4-1975 से 31-3-1978 के स्थान पर 24-3-1975 से 23-3-1978 तक प्रभावी रहेगी ।

[सं० 1217—फा०सं० 203/42/75-आई०टी०ए०-II]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप-सचिव

New Delhi, the 3rd February, 1976

S.O. 1018.—It is hereby notified for general information that the Notification No. 1095 (F. No. 203/42/75-I.T.A. II) dated 25-9-1975, approving the Institute of Management Development, U. P., Lucknow, for the purposes of section 35(1)(iii) of the Income-tax Act, 1961 will be effective from 24-3-1975 to 23-3-1978 instead of 1-4-1975 to 31-3-1978.

[No. 1217/F. No. 203/42/75-I.T.A. II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1976

का० आ० 1019.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ज की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री वेंगीश्वरर अलगप्पेरुमल और नागथम्मन मन्दिर, कोदम्बक्कम्, मद्रास-26 को, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र, विख्यात लोकपूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 1199—फा०सं० 176/99क/75-आई०टी०ए०-I]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

New Delhi, the 6th January, 1976

S.O. 1019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Shri Vengeeswarar Alagapperumal and Nagathamman Temple, Kodambakkam, Madras-26 to be a place of public worship of renown throughout the State Tamil Nadu for the purposes of the said Section.

[No. 1199—F. No. 176/99A/75-ITA.A-I]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1976

(आय-कर और धनकर)

का० आ० 1020.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठ की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इण्डस्ट्रियल रीकन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 1 अगस्त, 1975 और 31 मार्च, 1977 के बीच, निर्गमित 6 प्रतिशत 10 वर्षीय बन्धपत्र 1985—तृतीय आवलि को, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० 1210—फा०सं० 178/64/75-आई०टी०ए०-I]

सी० सी० गणपति, अपर सचिव

New Delhi, the 21st January, 1976

INCOME-TAX & WEALTH-TAX

S.O. 1020.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-section (1) of Section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the 6 per cent 10 years Bonds 1985—Third Series—issued by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. between the 1 August, 1975 and the 31 March 1977 for the purposes of the said clause.

[No. 1210—F. No. 178/64/75-I.T.A-I]

C. C. GANAPATHY, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976

बीमा

का०आ० 1021.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 552, तारीख 16 फरवरी, 1974 के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी हैं और जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है । उक्त सम्पदा अधिकारी, उक्त निगम की, या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई सम्पत्तियों के संबन्ध में, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट, अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

क्रम सं०	अधिकारी का पदाभिधान	अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2	3
1.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड (जो भी खंड का भारसाधक हो), "जीवन प्रकाश", 25, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र (नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम की सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर) और हरियाणा राज्य का गुड़गांव जिला ।
2.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबन्धक (जो भी खंड का भारसाधक हो) जालन्धर खंड कार्यालय पोस्ट बाक्स सं० 82, "जीवन प्रकाश", माडल टाउन रोड, जालन्धर ।	जम्मू-कश्मीर राज्य, पंजाब राज्य के अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर गुरदासपुर, होशियारपुर, जालन्धर और कपूरथला जिले और रोपड़ जिले की आनन्दपुर तहसील तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिले ।
3.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबन्धक (जो भी खंड का भारसाधक हो) चंडीगढ़ खंड, पोस्ट बाक्स संख्या 42, "जीवन प्रकाश," सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़- 17 ।	हरियाणा राज्य के अम्बाला, भिवानी हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, रोहतक, और सोनीपत जिले, पंजाब राज्य के भटिण्डा, लुधियाना, पटियाला, रोपड़ और संगरूर जिले और हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहोल-स्पिति, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ।
4.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो) अजमेर खंड, पोस्ट बाक्स संख्या 2, "जीवन प्रकाश," रानाडे मार्ग, अजमेर ।	राजस्थान राज्य के अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, पाली, सिरोही और उदयपुर जिले ।

1	2	3
5.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबन्धक (जो भी खंड का भारसाधक हो) जयपुर खंड पोस्ट बाक्स सं० 65, एल-5, पृथ्वीराज रोड, जयपुर ।	राजस्थान राज्य के अलवर, भरतपुर बीकानेर, चुरू, गंगानगर, जयपुर झुंझुनु, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर और टौक जिले ।
6.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबन्धक (जो भी खंड का भारसाधक हो) लखनऊ खंड, "जीवन प्रकाश" 30 हजरत गंज, लखनऊ ।	उत्तर प्रदेश राज्य के अल्मोड़ा, बहराइच, बाराबांकी, बरेली, बदायूं, फैजाबाद गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, नैनीताल, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहानपुर, सीतापुर, सुलतानपुर और उन्नाव जिले ।
7.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबन्धक (जो भी खंड का भारसाधक हो) कानपुर खंड पोस्ट बाक्स सं० 170, एल० आई० सी० बिल्डिंग, 16/98, एम जी रोड, कानपुर ।	उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन और कानपुर (नगर महापालिका कानपुर और छावनी बोर्ड कानपुर के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर) जिले ।
8.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो) मेरठ खंड, पोस्ट बाक्स सं० 69 "जीवन प्रकाश", प्रभात नगर मेरठ ।	उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर, चमोली, देहरादून, गढ़वाल, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, रामपुर, सहारनपुर, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिले ।
9.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो), आगरा खंड, लक्ष्मी मिल्स हाल, जौधमी मंडी, आगरा ।	उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और मथुरा जिले ।
10.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो), वाराणसी खंड पोस्ट बाक्स सं० 56, "जीवन प्रकाश" बी०-12/120, गौरी गंज, वाराणसी ।	उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, और वाराणसी जिले ।
11.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो) इंदौर खंड, पोस्ट बाक्स सं० 130, "जीवन प्रकाश," 19, एम०जी०रोड, इंदौर ।	मध्य प्रदेश राज्य के भिण्ड, भोपाल, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, खंडवा (पूर्वनिमाड़) खरगोन (पश्चिम निमाड़), मंदसौर, मुरैना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, और विदिशा जिले ।
12.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो), जबलपुर खंड, पोस्ट बाक्स सं० 17, 46, नैपियर नगर, जबलपुर ।	मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट, बेतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मांडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, और टीकमगढ़ जिले ।
13.	ज्येष्ठ खंड प्रबंधक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो), रायपुर खंड, रायपुर आइस फैक्ट्री बिल्डिंग फाफाडिह नोका, जगदम्बा पेट्रोल पम्प के सामने, रायपुर-492001 ।	मध्य प्रदेश राज्य के बस्तर, बिलासपुर दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनान्दगांव और सरगुजा जिले ।
14.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो), कलकत्ता खंड, रैलिस हाउस, 16, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता-1 ।	पश्चिमी बंगाल राज्य के कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिले, कलकत्ता, हावड़ा, बारनागोर (24 परगना), हुगली-चिनसुरा, पनिहाटी, बैरकपुर (24 परगना), बेहला (24 परगना), और जिला नादिया और जिला मिदनापुर की नगर पालिक सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ।
15.	ज्येष्ठ खंड प्रबंधक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाधक हो), जलपाईगुड़ी खंड पोस्ट बाक्स सं० 71, मर्चेन्ट रोड की क्रासिंग, डाकघर और जिला जलपाईगुड़ी ।	पश्चिमी बंगाल राज्य के कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, माल्दा और पश्चिमी दिनाजपुर जिले ।
16.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खंड का भारसाधक हो), आसनशोल खंड एल० आई० सी० बिल्डिंग, वैस्टएंड जी० टी० रोड, आसनसोल, जिला वर्दवाहैन (पश्चिमी बंगाल) ।	पश्चिमी बंगाल राज्य के बंकुरा, बीरभूम, वर्दवान, मिदनापुर और पुरुलिया जिले ।
17.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक (जो भी खंड का भारसाक हो), गोहाटी खंड, पोस्ट बाक्स सं० 6, ओरियन्टल बिल्डिंगस, स्ट्रेण्ड रोड, गोहाटी ।	असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, और त्रिपुरा राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र ।
18.	ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबन्धक (जो भी खंड का भारसाधक हो), पटना खंड, पोस्ट बाक्स सं० 135 "जीवन प्रकाश," मझरुलहक पथ, पटना ।	बिहार राज्य के औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, गिरिडीह, हजारीबाग, मुंगेर, पटना, नालन्दा, नवादा, रोहतास, संथाल परगना और शाहबाद जिले ।
19.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), मुजफ्फरपुर खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 33, एल० आई० सी० बिल्डिंग, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर (बिहार) ।	बिहार राज्य के चम्पारन पूर्व, चम्पारन पश्चिम, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सारन, सीतामढ़ी, सिवान, और वैशाली जिले ।
20.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), जमशेदपुर खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 31, हिन्दुस्तान बिल्डिंग्स, बौलेवार्ड रोड, जमशेदपुर ।	बिहार राज्य के धनबाद पलामू, रांची, सिंहभूम जले) ।

1	2	3
21.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), कटक खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 36, एल० आई०सी० बिल्डिंग, सर्किट • हाउस कम्पाउण्ड, नौपटना, कटक-1।	उड़ीसा राज्य।
22.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्ध या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), बंगलौर खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 694, "जीवन प्रकाश," जयचामराज रोड, बंगलौर।	कर्नाटक राज्य के बंगलौर, हसन, कोलार, माण्डूआ, मैसूर और टुमकू जिले।
23.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), उदीपी, खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 8 "जीवन कृष्ण", अज्जरकाड उदीपी।	कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, कुर्ग, शिमोगा और दक्षिण कनारा जिले।
24.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), धारवाड़ खण्ड, ए०पी०एम० सी० बिल्डिंग, मृत्युंजय मार्केट थर्ड पोस्ट बाक्स सं० 16, धारवाड़-1।	कर्नाटक राज्य के बेलगांव, बेल्लारी, बीजापुर, धारवाड़ और उत्तरी कनारा जिले।
25.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), हैदराबाद खण्ड, "जीवन प्रकाश," सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-4।	आंध्र प्रदेश राज्य के आदिलाबाद, अनन्तपुर, कडप्पा, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, करमूल महबूबनगर मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद, वारंगल, जिले और प्रकाशम जिले के गिद्दलूर और मरकापुर तालक और कर्नाटक राज्य के बीदर, गूलबर्गा, और रायचूर जिले।
26.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड भारसाधक हो), विशाखापत्तनम खण्ड, डी०एन० ओ० 50-15-4 राजेन्द्रनगर, विशाखापत्तनम-530004।	आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी जिले और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का येनम।
27.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), मछलीपत्तनम खण्ड, "जीवन प्रकाश", कैनेडी रोड, मछलीपत्तनम।	आन्ध्र प्रदेश राज्य के गुण्टूर, कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी और नेल्लोर जिले तथा प्रकाशम, जिले के अद्दांकी तालुक।
28.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), खण्ड कार्यालय 40, जी एन चेट्टी रोड, थियोगराया नगर मद्रास-17।	तमिलनाडु राज्य के चिंगलेपुट, मद्रास (मद्रास सिटी म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1919 (1919 का तमिलनाडु अधिनियम 4) की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर) उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काट जिले [तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1920 (1920 का तमिलनाडु अधिनियम 5) की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर] और आन्ध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर और नेलौर जिले के प्रकाशम जिले के पोडिली, डारसी, काण्डुकूर और कानिगिरी तालुक तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की पाण्डिचेरी यूनिट।
29.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), थंजावुर खण्ड, पोस्ट बाक्स, सं० 39, "जीवन प्रकाश" गांधीजी रोड, थंजावुर।	तमिलनाडु राज्य के थंजावुर, पुडुकेटाई, तिरुचिरापल्ली जिले गौर रामनाथपुरम जिले के तिरुपाथुर तालुक के इलायाथानकुडी, नेरुकुप्पई और वरप्पुर फिरके तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का केराईकल।
30.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो)। मदुराई खण्ड, पोस्ट बाक्स, सं० 16, पाण्ड्यन हाउस 118-बी, वेस्ट पेरुमल मैस्ट्री स्ट्रीट, मदुराई-1।	तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी, मदुराई, रामनाथपुरम, (तिरुपाथुर तालुक के इलायाथानकुडी, नेरुकुप्पई और वरप्पुर फिरकों को छोड़कर) और तिरुनेलवेली जिले।
31.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हों), कोयम्बत्तूर खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 1487, यूनाइटेड इंडिया बिल्डिंग, अविनाशी रोड और इंडिया लाइफ बिल्डिंग त्रिची रोड कोयम्बत्तूर-18।	तमिलनाडु राज्य के कोयम्बत्तूर, धर्मपुरी, नीलगिरि और सेलम जिले।
32.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), कोझीकोड खण्ड, ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डिंग स्वीट मीट बाजार स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स सं० 177, कोझीकोड।	केरल राज्य के कन्नानौर, कोझीकोड जिले और पालघाट तथा मलप्पुरम जिलों के भाग और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे।

1	2	3
33.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), त्रिवेन्द्रम खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 76, "जीवन प्रकाश," पोट्टम, मेन रोड, त्रिवेन्द्रम ।	केरल राज्य के एलेप्पी, एर्नाकुलम, कोट्टायम, क्विलोन, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम तथा मलप्पुरम और पालघाट जिलों के भाग ।
34.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), राजकोट खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 208, "जीवन प्रकाश", टैगोर मार्ग, राजकोट–1 ।	गुजरात राज्य के अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्र नगर जिले तथा गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का दीव ।
35.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), अहमदाबाद खण्ड, "जीवन प्रभा", तिलक रोड, अहमदाबाद–1 ।	गुजरात राज्य के अहमदाबाद, बनासकांठा, गांधी नगर, कैरा, मेहसाना, पंचमहल और साबर-कांठा जिले ।
36.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), सूरतखण्ड, जीवन प्रकाश, मुगलीसरा, सूरत ।	गुजरात राज्य के बड़ौदा, भड़ौंच, बलसर, डांगस और सूरत जिले तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का दमण ।
37.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), मुम्बई खण्ड, "योगक्षेम", जीवन बीमा मार्ग, मुम्बई-400021 ।	महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई, कोलाबा और ठाणा जिले [मुम्बई नगर निगम अधिनियम, (1888 का मुम्बई अधिनियम 3) की धारा 3 के खण्ड (1) में यथा परिभाषित बृहत्तर मुम्बई के क्षेत्रों को छोड़कर] और गोवा, दमण दीव संघ राज्य क्षेत्र का गोवा ।
38.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), सतारा खण्ड, वेस्टर्न इंडिया बिल्डिंग, 151, पैलेस स्ट्रीट, सतारा ।	महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर उस्मानाबाद, रत्नगिरि, सांगली, सतारा और शोलापुर जिले ।
39.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), पुणे खण्ड, "जीवन प्रकाश", युनिवर्सिटी रोड, शिवाजी नगर, पुणे–5 ।	महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर, औरंगाबाद, बीर, नान्देड, परभनी और पुणे जिले ।
40.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), नासिक खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 110, सह्याद्रि बिल्डिंग, आगरा रोड, नासिक–2 ।	महाराष्ट्र राज्य के धूलिया, जलगांव, और नासिक जिले ।
41.	ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड प्रबन्धक (जो भी खण्ड का भारसाधक हो), नागपुर खण्ड, पोस्ट बाक्स सं० 63, ओरियन्टल बिल्डिंग, स्टेशन रोड, नागपुर ।	महाराष्ट्र राज्य के अकोला, अमरावती, भण्डारा, बुलढाना, चन्द्रपुर, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिले ।

[फा० सं० 88(58)-बीमा-4/75]

आर० डी० खानवलकर, अवर सचिव

New Delhi, the 24th February, 1976

INSURANCE

S.O. 1021.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. S. O. 552, dated 16th February, 1974, the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Table below, being officers of the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), and being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act and the said estate officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction, specified in column (3) of the said Table, in respect of the properties belonging to, or taken on lease by or on behalf of the said Corporation.

TABLE

Sl. No.	Designation of Officer	Local limits of jurisdiction
1	2	3
1.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), "Jeevan Prakash", 25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.	Union Territory of Delhi (excluding the areas within the limits of the New Delhi Municipal Committee and the Municipal Corporation of Delhi) and Gurgaon District of Haryana State.
2.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division) Jullundur Divisional Office, Post Box No. 82, "Jeevan Prakash", Model Town Road, Jullundur.	Jammu and Kashmir State, Districts of Amritsar, Faridkot, Ferozepur, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jullundur and Kapurthala and Tehsil Anandpur of Rupar District of Punjab State, Chamba, Hamirpur, Kangra and Una Districts of Himachal Pradesh State.
3.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division) Chandigarh Division, Post Box No. 42, "Jeevan Prakash", Sector, 17-B, Chandigarh-17.	Ambala, Bhivani, Hissar, Jind, Karnal, Kurukshetra, Mahindergarh, Rohtak and Sonepat Districts of Haryana State, Bhatinda, Ludhiana, Patiala, Rupar and Sangrur Districts of Punjab State and Bilaspur.

1	2	3
		Kinnaur, Kulu, Lahul and Spiti, Mandi, Simla, Sirmour and Solan Districts of Himachal Pradesh State and Union Territory of Chandigarh.
4.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Ajmer Division, Post Box No. 2, "Jeevan Prakash", Ranade Marg, Ajmer.	Districts of Ajmer, Banswara, Barmer, Bihlwara, Bundi, Chittaurgarh, Dungarpur, Jaisalmer, Jalor, Jhalawar, Jodhpur, Kota, Pali, Sirohi and Udaipur of Rajasthan State.
5.	Senior Divisional Manager of Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Jaipur Division, Post Box No. 65, L-5, Prithviraj Road, Jaipur.	Districts of Alwar, Bharatpur, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jaipur, Jhunjhunu, Nagaur, Sawaimadhopur, Sikar and Tonk of Rajasthan State.
6.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Lucknow Division "Jeevan Prakash", 30, Hazrat Ganj, Lucknow.	Districts of Almora, Bahraich, Barabanki, Bareilly, Budaun, Faizabad, Gonda, Hardoi, Lakhimpur-Kheri, Lucknow, Nainital, Pithoragarh, Pratapgarh, Rae-Barelli, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur and Unnao of Uttar Pradesh State.
7.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Kanpur Division, Post Box No. 170, LIC Building, 16/98, M.G. Road, Kanpur.	Districts of Allahabad, Banda, Fatehpur, Himirpur, Jalaun, Jhansi and Kanpur of Uttar Pradesh State (excluding the areas within the Nagar Mahapalika, Kanpur and the Cantonment Board, Kanpur).
8.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Meerut Division, Post Box No. 69, Jeevan Prakash, Prabhat Nagar, Meerut.	Districts of Bijnor, Chamoli, Dehradun, Garhwal, Meerut, Moradabad, Muzaffarnargar, Rampur, Saharanpur, Tehri-Garhwal and Uttar Kashi of Uttar Pradesh State.
9.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Agra Division, Laxmi Mills Hall, Jeoni Mandi, Agra.	Districts of Agra, Aligarh, Bulandshar, Etah, Etawah, Farrukhabad, Mainpuri and Mathura of Uttar Pradesh State.
10.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Varnasi Division, Post Box No. 56, "Jeevan Prakash", B-12/120, Gauriganj, Varanasi.	Districts of Azamgarh, Ballia, Basti, Deoria, Gorakhpur, Gazipur, Jaunpur, Mirzapur and Varanasi of Uttar Pradesh State.
11.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Indore Division, Post Box No. 130, "Jeevan Prakash", 19, M.G. Road, Indore.	Districts of Bhind, Bhopal, Datia, Dewas, Dhar, Guna, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Jhabua, Khandwa (East Nimar), Khargone (West Nimar), Mandsaur, Morena, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Sehore, Shahjapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha of Madhya Pradesh State.
12.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Jabalpur Division, Post Box No. 17, 46, Napier Town, Jabalpur.	Districts of Balaghat, Betul, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Jabalpur, Mandla, Narsimhapur, Panna, Rewa, Sagar, Satna, Seoni, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh of Madhya Pradesh State.
13.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Raipur Division, Raipur Ice-Factory Building near Fafadih Naka, opposite Jagdamba Petrol Pump, Raipur-492001.	Districts of Bastar, Bilaspur, Durg, Raigarh, Raipur, Rajnandgaon and Surguja of Madhya Pradesh State.
14.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Calcutta Division, "Rallis House", 16, Hare Street, Calcutta-1.	Districts of Calcutta, Hooghly, Howrah, Murshidabad and 24-Parganas of West Bengal State [Except the areas within the municipal limits of Calcutta, Howrah, Baranagore (24-Parganas), Hooghly-Chinsurah, Panihati, Barrackpur (24-Parganas), Behala (24-Parganas) and District Nadia and District Midnapur] and Andaman and Nicobar Islands.
15.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Jalpaiguri Division, Post Box No. 71, Crossing of Merchant Road, P.O. & Distt. Jalpaiguri.	Districts of Cooch Behar, Darjeeling, Jalpaiguri, Malda and West Dinajpur of West Bengal State.
16.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Asansol Division, LIC Building, West End, G.T. Road, Asansol, Distt. Burdwan (West Bengal).	Districts of Bankura, Birbhum, Burdwan, Midnapur and Purulia of West Bengal State.
17.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Gauhati Division, Post Box No. 6, Oriental Building, Strand Road, Gauhati.	States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura and Union territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.
18.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Patna Division, Post Box No. 135, "Jeevan Prakash", Mazherul Haque Path, Patna.	Districts of Aurangabad, Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur, Gaya, Girdih, Hazaribagh, Monghyr, Patna, Nalanda, Nawadah, Rohtas, Santhal Parganas and Shahabad of Bihar State.
19.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Muzaffarpur Division, Post Box No. 33, LIC Building, Club Road, Muzaffarpur (Bihar).	Districts of Champaran East, Champaran West, Darbhanga, Madhubani, Muzaffarpur, Purnea, Saharsa, Saran, Sitamarhi, Siwan and Vaishali of Bihar State.
20.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Jamshedpur Division, Post Box No. 41, Hindusthan Buildings, Boulevard Road, Jamshedpur.	Districts of Dhanbad, Palamau, Ranchi and Singhbhum of Bihar State
21.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Cuttack Division, Post Box No. 36, LIC Building, Circuit House Compound, Naupatna, Cuttack-1.	State of Orissa.

1	2	3
22.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Bangalore Division, Post Box No. 694, "Jeevan Prakash" Jayachamaraja Road, Bangalore.	Districts of Bangalore, Hassan, Kolar, Mandya, Mysore and Tumkur of Karnataka State.
23.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Udipi Division, Post Box No. 8, "Jeevan Krishna" Ajjarkad, Udipi.	Districts of Chikmagalur, Chitradurga. Coorg, Shimoga and South Kanara of Karnataka State.
24.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), A.P.M.C. Building, Marithyunjya Market Yard, Post Box No. 16, Dharwar-1.	District of Belgum, Bellary, Bijapur, Dharwar and North Kanara of Karnataka State.
25.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Hyderabad Division, "Jeevan Prakash" Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-4.	Districts of Adilabad, Anantapur, Cuddapah, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Kurnool, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Warangal and Giddalur and Markapur Taluks of Prakasam District of Andhra Pradesh State and Bidar, Gulbarga and Raichur Districts of Karnataka State.
26.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Visakhapatnam Division, D.N.O. 50-15-4, Rajendranagar, Vishakhapatnam-530004.	Districts of Vishakhapatnam, Srikakulam and East Godavari of Andhra Pradesh State and Yanam of Union territory of Pondicherry.
27.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Machilipatnam Division "Jeevan Prakash", Kennedy Road, Machilipatnam.	Districts of Guntur, Krishna, West Godavari and Ongole, Chirala and Addanki Taluks of Prakasam District of Andhra Pradesh State.
28.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Divisional Office, 40, G.N. Chetty Road, Thyagaraja Nagar, Madras-17.	Districts of Chingaleput, Madras [excluding the areas within the jurisdiction of the Madras City Municipal Corporation Act 1919 (Tamil Nadu Act 4 of 1919)], North Arcot and South Arcot of Tamil Nadu State [excluding the areas within the jurisdiction of the Tamil Nadu District Municipalities Act, 1920 (Tamil Nadu Act 5 of 1920)] and Chitoor and Nellore Districts and Podili, Darsi, Kandukur and Kanigiri Taluks of Prakasam District of Andhra Pradesh State and Pondicherry Unit of Union territory of Pondichery.
29.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Thanjavur Division, Post Box No. 39, "Jeevan Prakash", Gandhiji Road, Thanjavur.	Districts of Thanjavur Pudukettai, Tiruchirapalli and Firkas of Ilayathankudi, Nerkuppai and Warappur of Tirupathur Taluk of Ramanathapuram District of Tamil Nadu State and Keraikal of Union territory of Pondicherry.
30.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Madurai Division, Post Box No. 16, "Pandyan House", 118-B, West Perumal Maistry Street, Madurai-1.	Districts of Kanyakumari, Madurai, Ramanathapuram (excluding Firkas of Ilayathankudy, Nerkuppai and Warappur of Tirupathur Taluk) and Tirunelveli of Tamil Nadu State.
31.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Coimbatore Division, Post Box No. 1487, United India Building Avanashi Road and India Life Building, Trichy Road, Coimbatore-18.	Districts of Coimbatore, Dharmapuri, Nilgiris and Salem of Tamil Nadu State.
32.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Kozikode Division, Old Collectorate Building, Sweet Meat Bazar Street, Post Box No. 177, Kozhikode.	Districts of Cannanore, Kozhikode and portions of Palghat and Mulappuram Districts of Kerala State and Union territory of Lakshadweep and Mahe of Union territory of Pondicherry.
33.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Trivandrum Division, Post Box No. 76, "Jeevan Prakash" Pottam, Main Road, Trivandrum.	Districts of Alleppey, Ernakulam, Kottayam, Quilon, Trichur and Trivandrum and portions of Mulappuram and Palghat Districts of Kerala State.
34.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Rajkot Division, Post Box No. 208, "Jeevan Prakash", Tagore Marg, Rajkot-1.	Districts of Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Kutch, Rajkot and Surendranagar of Gujarat State and Diu of Union territory of Goa, Daman and Diu.
35.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Divsion), Ahmedabad Division,"Jeevan Prabha", Tilak Road, Ahmedabad-1	Districts of Ahmedabad, Banaskantha, Gandhi Nagar, Kaira, Mehsana, Panchmahals and Sabarkantha of Gujarat State.
36.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division) Surat Division, "Jeevan Prakash", Muglisara, Surat.	Districts of Baroda, Broach, Bulsar Dangs and Surat of Gujarat State and Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman of Union territory of Goa, Daman and Diu.
37.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Bombay Divsion, "Yogakshema", Jeevan Bima Marg,Bombay-400021.	Districts of Bombay, Kolaba and Thana of Maharashtra State [excluding the areas comprising Greater Bombay as defined in clause (a) of section 3 of the Bombay Municipal Corporation Act (Bombay Act 3 of 1888] and Goa of Union territory of Goa, Daman and Diu.
38.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager(whoever is in charge of the Division), Satara Division, Western India Building, 151, Palace Street, Satara.	Districts of Kolhapuri, Osmanabad, Ratnagiri Sangli Satara and Sholapur of Maharashtra State.
39.	Senior Divisional Manager or Divsional Manager (whoever is in charge of the Division), Poona Division, "Jeevan Prakash", University Road, Shivajinagar, Poona-5	Districts of Ahmednagar, Aurangabad, Bhir, Nanded, Parbhani and Poona of Maharashtra State.

1	2	3
40.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Nasik Division, Post Box No. 110, Sahyadri Building, Agra Road, Nasik-2	Districts of Dhulia, Jalgaon and Nasik of Maharashtra State.
41.	Senior Divisional Manager or Divisional Manager (whoever is in charge of the Division), Nagpur Division, Post Box No. 63, Oriental Building, Station Road, Nagpur.	Districts of Akola, Amravati, Bhandara, Buldana, Chandrapur, Nagpur, Wardha and Yeotmal of Maharashtra State.

[F. No. 88(58)-Ins. IV/75]

R. D. KHANWALKAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1976

स्टाम्प

का. आ. 1022.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, बंगलौर द्वारा जारी किए जाने वाले बयासी लाख पचास हजार रुपये मूल्य के वचन-पत्रों के रूप में बन्ध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य, हैं, छूट देती है ।

[सं. 14/76/स्टाम्प-फा. सं. 471/2/76-सीमाशुल्क-7]

डी. के. आचार्य, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 1976

STAMPS

S.O. 1022.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of eighty two lakhs and fifty thousand rupees, to be issued by the Karnataka State Finance Corporation, Bangalore, are chargeable under the said Act.

[No. 14/76-Stamps—F. No. 471/2/76-Cus. VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1976

का० आ० 1023.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध इस अधिसूचना की निर्गम तिथि से दो वर्ष की अवधि तक के लिए 'यूनियन बैंक आफ इंडिया' पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उनका सम्बन्ध 'बनारस स्टेट बैंक लि०, वाराणसी' की शेयर-धारिता से है ।

[सं० 15(8)-बी०ओ०III/76]

(Department of Banking)

New Delhi, the 13th February, 1976

S.O. 1023.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to Union Bank of India for a period of two years from the date of issue of this notification in so far as they relate to its holdings in the shares of Benares State Bank Ltd., Varanasi.

[No. 15(8)-B.O. III/76]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1976

का० आ० 1024.—दिनांक 27 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 (ii) में प्रकाशित, दिनांक पहली दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना सं० 15 (1)-बी०ओ०III/75 के हिन्दी रूपान्तर में उल्लिखित तिथि "6 जनवरी, 1975" को "6 जनवरी, 1976" पढ़ा जाये ।

[सं० 15(1)-बी०ओ०III/75]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th February, 1976

S.O. 1024.—In the notification No. 15(1)-B. O. III/75 of 1st December, 1975 published in the Gazette of India-Part II Section 3 (ii) dated 27th December, 1975, the date "6th January, 1975" appearing in the Hindi version may be read as "6th January, 1976".

[No. 15(1)-B.O. III/75]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का० आ० 1025.—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा II की उपधारा (i) के उपबन्ध 1 मार्च, 1974 से 29 फरवरी, 1976 तक की अवधि के दौरान सेफ कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई पर लागू नहीं होंगे ।

[सं० एफ०8-11/76-ए०सी०]

हृषीकेश गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd February, 1976

S.O. 1025.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Safe Co-operative Bank Ltd., Bombay for the period from 1 March, 1974 to 29 February, 1976.

[No. R. 8-11/76-AC]

H. K. GUHA, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 19th February, 1976

S.O. 1026.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

(1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Fourth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, the second proviso to sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.

[No. F. 13(4)-EV(B)/76-GPF]

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976

का० आ० 1027.—राष्ट्रपति जी ने एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं; अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1976 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (जिसका इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लेख किया गया है), के नियम 18 में उपनियम 2 में खण्ड (क) के लिये, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) किसी सेवा या पद पर स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी जैसाकि उपनियम (1) में उल्लिखित है, इस प्रकार के आदेश के साथ सरकारी कर्मचारी से उक्त उपनियम के अधीन, इस प्रकार के आदेश जारी किये जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर अथवा यदि उस दिन वह छुट्टी पर हो तो उसके छुट्टी से लौटने के तीन महीने के भीतर, इसमें से जो भी बाद में हो, लिखित रूप में विकल्प दिये जाने की अपेक्षा करेगा तथा खण्ड (ख) के उपबंधों को भी उसकी जानकारी में लायेगा।"

3. उक्त नियमावली के नियम 19 में, उपनियम (2) में खण्ड (क) के लिये, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) सिविल सेवा अथवा पद पर स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी जैसाकि उपनियम (1) में उल्लिखित है, इस प्रकार के आदेश के साथ सरकारी कर्मचारी से उक्त उपनियम के अधीन, इस प्रकार के आदेश जारी किये जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर अथवा यदि उस दिन वह छुट्टी पर हो तो, उसके छुट्टी से लौटने के तीन महीने के भीतर, इसमें जो भी बाद में हो, लिखित रूप में विकल्प दिये जाने की अपेक्षा करेगा तथा खण्ड (ख) के उपबन्धों को भी उसकी जानकारी में लायेगा।"

[सं० फ० 3(6)-स्थापना 5(क)/75]

एस० एस० एल० मलहोत्रा, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 24th February, 1976

S.O. 1027.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and, after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1.(1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 18 of the Central Services (Pension) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) The authority issuing the order of substantive appointment to a service or post as is referred to in sub-rule (1) shall along with such order require in writing the Government servant to exercise the option under that sub-rule within three months of the date of issue of such order, or if he is on leave on that day, within three months of his return from leave, whichever is later and also bring to his notice the provisions of clause (b)."

3. In rule 19 of the said rules, in sub-rule (2) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) The authority issuing the order of substantive appointment to a civil service or post as is referred to in sub-rule (1) shall along with such order require in writing the Government servant to exercise the option under that sub-rule within three months of date of issue of such order, if he is on leave on that day, within three months of his return from leave, whichever is later and also bring to his notice the provisions of clause (b)."

[No. F 3(6)-EV(A)/75]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

कलकत्ता 17 दिसम्बर, 1975

का० आ० 1028.—सर्वश्री कार्बेक एंड कं०, पी-15, न्यू सी०ई०टी० रोड़ इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-12 को निम्नलिखित अनुसार अप्रैल-मार्च, 1974 की अवधि के लिये लाइसेंस प्रदान किया गया था :—

लाइसेंस सं० और तिथि	माल का विवरण	मूल्य
पी/ई/0241670/सी/एक्स-एक्स/51सी/38-39, दिनांक 14-8-74.	आयात नीति पुस्तक अप्रैल-मार्च, 1975 (भा०-1) के अनुबन्ध 19 के अनुसार सामान्य भेषज और औषधियां ।	3128 रुपये (तीन हजार एक सौ अट्ठाइस रुपये मात्र)।

पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा, विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियों के लिये यह बतलाते हुए आवेदन किया है कि वे किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत कराये बिना ही खो गई है और उनका बिलकुल उपयोग नहीं हुआ है। अब लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां पूरे मूल्य 3128 रुपये के उपयोग के लिये चाहियें।

इस तर्क के समर्थन में फर्म ने स्टाम्प कागज पर महानगरीय मजिस्ट्रेट कलकत्ता द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित शपथपत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस संख्या : पी०/ई/0241670 (सी) एक्स-एक्स/51/सी/38-39, दिनांक 14-8-74 की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिना रद्द किये हुए, रहन रखे हुए, किसी अन्य पार्टी को किसी भी उद्देश्य के लिये हस्तांतरित किये हुए या सौंपे बिना ही खो गई/अस्थानस्त हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को पूरे मूल्य 3128 रुपये के लिये उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां जारी की जायें।

[सं० ई-1/15658/5/ए एम-75]

बी० के० विश्वास, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Calcutta, the 17th December, 1975

S.O. 1028.—M/s. Karbac & Company, P-15, New C.I.T. Road, India Exchange Place, Calcutta-12 was granted Licence for the period April-March, 1974 as under :—

Licence No. & Date.	Description of goods.	Value.
P/E/0241670/C/XX/51/C/38-39 dt. 14.8.74	General Drugs & Medicines as per App. 19 of Import Policy Book for AM/75 (Vol. I)	Rs.3128/— (Rupees— Three thd. one hd. & twentyeight only).

The party has applied for duplicate Customs Purpose & Exchange Control Copy of the above licence stating that the same have been lost without having been registered with any Customs Authority & not utilised at all. The duplicate Customs Purposes Copy & Exchange Control Copy are now required for utilisation of the full amount of Rs. 3128.

In support of this contention the firm have filed an affidavit on a stamped paper duly attested by the Matropolitan Magistrate, Calcutta.

I am saisfied that the Customs Purposes Copy & Exchange Control Copy of import licence No. P/E/0241670/C/XX/51/C/38-39, dated : 14-8-1974 have been lost/misplaced without having been cancelled pledged, transferred or handed over to any other party for any purpose & direct to Issue duplicate Customs Purposes Copy & Exchange Control Copy of the aforesaid licence to the applicant for the full value of Rs. 3128.

[No. EI/15658/5/AM-75]

B. K. BISWAS, Dy. Chief Controller

For Jt. Chief Controller

पैट्रोलियम मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

का० आ० 1028.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1236, तारीख 31-3-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० 188 से जी जी एस-5 तक

राज्य : गुजरात	जिला : बरोच		तालुका : अंकलेश्वर
गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ऐरे	सेण्टीयर
सेरथान	122	0	09	75

[सं० 12016/5/25-एल०एण्ड एल०]

MINISTRY OF PETROLEUM

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 21st February, 1976

S.O. 1029.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 1236 dated 21-3-75 under sub-section (i) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Rihgt of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And Whereas the Competent Authority has under sub section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report. decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in excercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notfication hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

From well No. 188 to GGS-V.

State : Gujarat	District : Broach	Taluka : Anklesh-var.	
Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Sarthan	122	0	09	75

[No. 12016/5/75-L&L]

का०आ० 1030—यतः पेट्रोलियम, पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 1235 तारीख 31-3-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० 187 से जी जी एस-II तक

राज्य : गुजरात	जिला : बरोच		तालुका : अंकलेश्वर
गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ऐरे	सेण्टीयर
तेलवा	9	0	27	69

[सं० 12016/5/75-एल०एण्ड०एल०]

S.O. 1030.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 1235 dated 31-3-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquistion of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the the Government;

And further wheareas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in th schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

From well No. 187 TO GGS-II.

State: Gujarat District : Broach Taluka: Ankleshvar.

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
TELWA	9	0	27	69

[No. 12016/5/75-L&L/I]

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का० आ० 1031.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर कुप नं० 21,51,48,62,56,66 से रुद्रसागर जी० जी० एस नं० 4 तक के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये अक्षेप अवर प्रमंडल पदाधिकारी शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

रुद्रसागर कुप नम्बर 21,51,48,62,56,66 से रुद्रसागर जी०जी० एस 4 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुक : कोवरपुर

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टी एरे
फाकुन कमार फदिया	16ख	0	13	78
	80ख	0	4	15
	86ख	0	2	14
	614ख	0	1	61
	130ख	0	1	61

[सं० 12020/1/76-एल० एण्ड एल०/II]

New Delhi, the 23th February 1976

S. O. 1031.—whereas it appears to be Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from RDS, Well Nos. 21, 51, 48, 62, 56 and 66 to RDS. GGS. No. 4 in Sibsagar Dist., Assam., Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And Whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines, (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government, hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Feeder line from RDS. Well Nos. 21, 51, 48, 62, 56 and 66 to Rudrasagar CGS No. 4

STA TE-ASSAM Dist-Sibsagar: Taluk: Konwarpur

Village	Survey	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
FAKUM KOMARFODIA	16 Kha	0	13	78
	80 Kha	0	4	15
	86 Kha	0	2	14
	1614 Kha	0	1	61
	130 Kha	0	1	61

[No. 12020/1/76-L&L/II]

का० आ० 1032.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर जी० जी० एस० नं० 4 से रुद्रसागर जी० जी० एस० नं० 1 तक के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्पाबद्ध अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पैट्रोलियम पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये अक्षेप अवर प्रमंडल पदाधिकारी शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर जी०जी० एस नम्बर 4 से रुद्रसागर जी०जी० एस नवम्बर 1 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुक : मेतेका बनगांव

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्तर	ऐरे	सेन्तीऐरे
1	2	3	4	5
पथलियाल	129ख	0	12	31
	281ख	0	4	41
	290ख	0	1	47
	301ख	0	3	21
	302ख	0	3	48
	363ख	0	3	61
	362ख	0	1	87
	364ख	0	0	67
	464ख	0	9	63
	465ख	0	3	75
	466ख	0	1	61
	485ख	0	1	34
	487ख	0	6	02
	486ख	0	4	15

[सं० 12020/1/76-एल०एण्ड एल०]

S.O. **1032**.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar GGS. No. 4 to Rudrasagar GGS No. 1 in Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Feederline from Rudrasagar CCS No. 4 to Rudrasagar CGS No. 1

State : Assam Dist. Sibsagar Taluk : Metcka Bongaon

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
PATHALIAL	129 Kha	0	12	21
	281 Kha	0	4	41
	290 Kha	0	1	47
	301 Kha	0	3	21
	302 Kha	0	3	48
	363 Kha	0	3	61
	362 Kha	0	1	87
	364 Kha	0	0	67
	464 Kha	0	9	63
	465 Kha	0	3	75
	466 Kha	0	1	61
	485 Kha	0	1	34
	487 Kha	0	6	02
	486 Kha	0	4	15

[No. 12020/1/76-L&L/III]

का० आ० 1033.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर कूप नम्बर 21, 51, 48,62,56,66 से जी०जी०एस० नं० 4 तक के बीच पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप अवर प्रभंडल पदाधिकारी शिवसागर असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नवम्बर 21,51,48,62,56,66 से जी०जी० एस नम्बर 4 तक पाइप लाइन

राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुक : कोथरपुर

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्तर	ऐरे	सेन्तीऐरे
1	2	3	4	5
बलियाघाट	932ख		3	75
	931ख		1	87
	930ख		4	82
	929ख		1	87
	935ख		2	01
	936ख		1	74
	937ख		1	61
	927ख		0	27
	1078ख		1	34
	1078ग		0	54

1	2	3	4	5
	864ख		9	23
	928ख		9	63
	926ख		7	76
	938ख		0	27
	940ख		1	34
	924ख		0	40
	783ख		0	40
	768ख		0	94
	925क		2	14
बलियाघाट	921ख		0	27
	941ख		4	55
	942ख		5	35
	920ख		10	03
	1375ख		1	61
	1064ख		9	36
	1060ख		0	54
	748ख		7	63
	1099ख		21	67
	766ख		7	49
	743ख		1	20
	765ख		6	56
	767ख		2	68
	741ख		6	96
	742ख		7	89
	717ख		3	34
	718ख		7	49
	637ख		2	01
	610ख		4	41
	609ख		4	41
	638ख		4	82
	639ख		12	71
	608ख		4	41
	586ख		0	67
	749ख		0	54
	764ख		6	56
	1079ख		12	04
	1556क		2	54

[सं० 12020/1/76-एल एण्ड एल/I]

S.O. 1033.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from RDS, well NOs. 21, 51, 48, 62 156 & 66 to RDS. CGS. No. 4 in Sibsagar Dist., Assam, Pipeline should be laid by the oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipline from Rudrasagar Well Nos. 21, 51, 48, 62, 56 and 66 to RDS. GGS. NO. 4.

State—Assam Dist. Sibsagar. Taluk—— Korwarpur

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Boliaghat	932 Kha		3	75
	931 Kha		1	87
	930 Kha		4	82
	929 Kha		1	87
	935 Kha		2	01
	936 Kha		1	74
	937 Kha		1	61
	927 Kha		0	27
	1078 Kha		1	34
	1078 Ga		0	54
	864 Kha		9	23
	928 Kha		9	63
	926 Kha		7	76
	938 Kha		0	27
	940 Kha		1	34
	924 Kha		0	40
	783 Kha		0	40
	768 Kha		0	94
	925 Kha		2	14
	921 Kga		0	27
	941 Kha		4	55
	942 Kha		5	35
	920 Kha		10	03
	1375 Kha		1	61
	1064 Kha		9	36
	1060 Kha		0	34
	748 Kha		7	63
	1099 Kha		21	67
	766 Kha		7	49
	743 Kha		1	20
	765 Kha		6	56
	767 Kha		2	68
	741 Kha		6	96
	742 Kha		7	89
	717 Kha		3	34
	718 Kha		7	49
	637 Kha		2	01
	610 Kha		4	41
	609 Kha		4	41
	638 Kha		4	82
	639 Kha		12	71
	608 Kha		4	41
	586 Kha		0	67
	749 Kha		0	54
	764 Kha		6	56
	1079 Kha		12	04
	1556 Kha		2	54

[No. 12020/1/76—L&L/I]

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976

का०आ० 1034.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 620 (ई०) तारीख

29-10-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बंधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप सं० 15 से एस आई पी (आनन्द जी जी एस) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए उपभोग का अधिकार

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कालोल

गांव	सर्वेक्षण सं०	हैक्टेयर	एआर ई	सेन्टीयर
जाजलाज	573/5	0	02	70
	कार्ट ट्रेक	0	01	05
	372	0	19	20
	364/1	0	14	00
	364/2	0	00	70
	371	0	00	04
	361/1	0	00	35
	361/2	0	10	00
	359/2/सी	0	07	05
	358/1	0	02	10
	357/1	0	10	10
	474	0	04	05
	कार्ट ट्रेक	0	01	65
	475	0	10	50
	476	0	07	75
	477/3	0	01	80
	477/1	0	07	95
	494	0	01	50
	478/1/सी	0	06	98
	478/1/ए	0	01	50
	478/1/बी	0	09	60
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	480/2	0	04	35
	480/1	0	05	00
	487	0	01	50
	486	0	14	25
	483	0	00	60
	484	0	12	60
	कार्ट.ट्रेक	0	01	50
	550/2	0	12	00
	550/1	0	14	70
	545	0	03	15
	1/पी	0	09	00
	7	0	06	00
	9/1	0	03	00
	9/2	0	02	70
	10/पी	0	05	40
	10/पी	0	03	60
	11	0	07	92
	1/पी	0	01	98
	24/1	0	14	55
	29	0	01	20
	30/1	0	04	95
	25	0	00	60
	31	0	24	75
	32	0	25	65
	44	0	01	20
	कार्ट ट्रेक	0	00	98
	162/2	0	07	20
	162/2	0	04	87
	148	0	11	10
	147	0	01	60
	149	0	13	50
	146	0	05	70
	98	0	17	70
	99	0	06	15
	91/2	0	26	10
	89	0	01	60
	91/1	0	01	70
	92/2	0	07	50
	92/1	0	08	70
	61	0	10	12
	93	0	05	25
	60	0	10	50
	58	0	06	75
	56	0	12	45
	कार्ट ट्रेक	0	01	20
	37	0	11	10
हाजीपुर	615/1	0	33	55
	जिला : मेहसाना		तालुका :	कावी
थोल	1423	1	65	00

[सं० 12016/18/75-एल०एण्ड एल०]

टी०पी० सुब्रह्मनियन, अवर सचिव

New Delhi, the 24th February, 1976

S.O. 1034.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S. O. No. 620 (E) Dated 29-10-75 under sub-section (I) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquired the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encoumbrances.

SCHEDULE

R.O.U. FOR LAYING PIPELINE FROM WELL NO. 15 TO SIP (SANAND GGS)

State : Gujarat District : Mehsana
Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Jathlaj	373/5	0	02	70
	Cart-track	0	01	05
	372	0	19	20
	364/1	0	14	00
	364/2	0	00	70
	371	0	00	04
	361/1	0	00	35
	361/2	0	10	00
	359/2/C	0	07	05
	358/1	0	02	10
	357/1	0	10	20
	474	0	04	05
	Cart-track	0	01	65
	475	0	10	50
	476	0	07	75
	477/3	0	01	80
	477/1	0	07	95
	494	0	01	50
	478/1/C	0	06	98
	478/1/A	0	01	50
	478/1/B	0	09	60
	Cart-track	0	00	60
	480/2	0	04	35
	480/1	0	05	00
	487	0	01	50
	486	0	14	25
	483	0	00	60
	484	0	12	60
	Cart-track	0	01	50
	550/2	0	12	00
	550/1	0	14	70
	545	0	03	15
	1/P	0	09	00
	7	0	06	00
	9/1	0	03	00
	9/2	0	02	70
	10/P	0	05	40
	10/P	0	03	60
	11	0	07	92
	1/P	0	01	98
	24/1	0	14	55
	29	0	01	20
	30/1	0	04	95
	25	0	00	60
	31	0	24	75
	32	0	25	65
	44	0	01	20
	Cart-track	0	00	98
	162/2	0	07	20
	162/1	0	04	87
	148	0	11	10
	147	0	01	60
	149	0	13	50
	146	0	05	70
	98	0	17	70
	99	0	06	15
	91/2	0	26	10
	89	0	01	60
	91/1	0	01	70
	92/2	0	07	50
	92/1	0	08	70
	61	0	10	12
	93	0	05	25
	60	0	10	50
	58	0	06	75
	56	0	12	45
	Cart-track	0	01	20
	57	0	11	10
Hajipur	615/1	0	33	55
	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Thol	1423	1	65	00

[No. 12016/18/75-L&L]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली 17 फरवरी, 1976

का०आ० 1035.—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (उर्वरक और रसायन विभाग) की अधिसूचना संख्या 24(11)/74-सी०एच० II, तारीख 31-10-75 के साथ प्रकाशित, शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के खण्ड 11 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त खण्ड के उपखण्ड (1) के उपबन्ध उड़ीसा राज्य में इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[सं० एल०-15021(5)/76-सी एच II]

के० पी० श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

New Delhi, the 17th February, 1976

S.O. 1035.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of Clause 11 of the Molasses Control Order, 1961, as amended by the Molasses Control (Amendment) Order, 1975, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Deptt. of Fertilizers and Chemicals) No. 24(11)/74-Ch. II dated the 31st October, 1975, the Central Government hereby directs that the provisions of sub-clause (1) of the said clause, shall come into force in the State of Orissa with effect from the date of publicaion of this notification in the Gazette of India.

[No. L-15021(5)/76-Ch. II]

K. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1976

का०आ० 1036.—साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार टायर और ट्यूब (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1974 को तुरन्त प्रभावी रूप से विखण्डित करती है, किन्तु यह विखण्डन उन बातों को लागू नहीं होगा, जो ऐसे विखण्डन से पूर्व उक्त आदेश के अधीन की गई हो या किए जाने से छोड़ दी गई हो।

[सं० 1(19)/74-एल आर जी]

एस०बी० सुब्रमण्यन, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 5th February, 1976

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1976

S.O. 1036.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds with immediate effect, the Tyres and Tubes (Movement Control) Order, 1974 except as respects things done or omitted to be done under the Order before such rescission.

[No. 1(19)/74-LRG]

S. B. SUBRAMANIAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

का० आ० 1037.—केन्द्रीय सरकार, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेन्ट नियम, 1972 में कतिपय संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 159 की उपधारा (3) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास की अवधि के पश्चात विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. (1) इन नयमों का नाम पेटेन्ट (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेन्ट नियम, 1972 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखि उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(3) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में पेटेन्ट धारी को या किसी आवेदक या विरोधी के नाम भेजी गई सभी सूचनाएं और सभी लिखित संसूचनाएं तथा पेटेन्ट धारी को या उक्त आवेदक या विरोधी को भेजे गए सभी दस्तावेज, तब के सिवाय, जब वे विशेष संदेश-वाहक द्वारा भेजे जाते हैं, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे जाएंगे।"

3. उक्त नियमों के नियम 92 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"परन्तु इस नियम के अधीन वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से किसी व्यक्ति को हटाए जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।"

[फा० सं० 18(32)/74/पी० एण्ड सी०]

एन० के० बरवा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st February, 1976

S.O. 1037.—The following draft of certain rules to amend the Patents Rules, 1972, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), is hereby published as required by sub-section (3) of section 159 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the date so specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1.(1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Patents Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) All notices and all written communications addressed to a Patentee, or to any applicant or opponent in any proceedings under the Act or these rules, and all documents forwarded to the patentee or to the said applicant or opponent shall, except when they are sent by special messenger be sent by registered post acknowledgement due".

3. To rule 92 of the said rules, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that before removing any person from the roll of Scientific Advisers under this rule such person shall be given a reasonable opportunity of being heard".

[F. No. 18(32)/74/P&C]

N. K. BERWA, Under Secy.

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

का०आ० 1038.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन बड़ोंच द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार

करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 16 अप्रैल, 1976 से 15 अप्रैल, 1977 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) को एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन निर्देशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[संख्या 12(1) आई०टी०/76]

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1038.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Sec. 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Central Gujarat Cotton Dealers' Association, Broach and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 16th April, 1976 to the 15th April, 1977 (both days inclusive), in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/76]

का०आ० 1039.—केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हैसन एक्सचेंज लिमिटेड, 43 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्यों और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्रों में कच्चे जूट (जिसमें मेस्टा सम्मिलित है) में अग्रिम संविदाओं की बाबत 29 मार्च, 1976 से 28 मार्च, 1977 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की और कालावधि के लिए एतद्द्वारा मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जाएं।

[फा० सं० 12(2)-आई०टी०/76]

S.O. 1039.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), by the East India Jute and Hessian Exchange Limited, 43, Netaji Subhas Road, Calcutta and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public inerest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from 29th March 1976 to 28th March, 1977 (both days inclusive) in respect of forward contracts in raw jute (including mesta) in the States of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya, Orissa and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time, be given by the Forward Markets Commssion.

[F. No. 12(2)-IT/76]

का०आ० 1040.—केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हैसन एक्सचेंज लिमिटेड, 43 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन किये गये, मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को कलकत्ता नगर में जूट माल (किसी भी प्रकार की किसी मिल या किसी अन्य विनिर्माता, द्वारा जूट से, बनाए गए हैसन और बोरियां बनाने के कपड़े या बोरे या दोनों, दुआइन या सूत या दोनों) में अग्रिम संविदाओं की बाबत 29 मार्च, 1976 से 28 मार्च, 1977 की एक वर्ष की और कालावधि के लिए एतद्द्वारा मान्यता प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में, 'कलकत्ता नगर' पद से अभिप्रेत है—

(1) कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम, 1951 (पश्चिम बंगाल अधिनियम 1951 का 33) की धारा 5 के खण्ड (ii) में यथा परिभाषित कलकत्ता तथा उसके साथ हैरिंग्टन स्ट्रीट या कलाइव रो का साउथ सिरा और नदी तट तक स्ट्रैंड रोड और वे क्षेत्र जो एतत्पूर्व अब समाप्त टालीगंज नगरपालिका के अंतर्गत थे ;

(2) कलकत्ता पत्तन, और

(3) 24 परगना, नदिया, हावड़ा और हुगली जिले।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें।

[फा०सं० 12(2)-आई०टी०/76]

बी०एन० लाल, अवर सचिव

S.O. 1040.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), by the East India Jute & Hessian Exchange Limited, 43, Netaji Subhas Road, Calcutta, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the

public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from 29th March, 1976 to 28th March, 1977, in respect of forward contracts in jute goods (hessian and sacking cloth or bag or both, twines or yarns or both manufactured by any of the mills or any other manufactures of whatever nature made from jute) in the city of Calcutta.

Explanation—In this notification, the expression "city of Calcutta" means :—

(1) Calcutta as defined in Clause (ii) of Section 5 of the Calcutta Municipal Act, 1951, (West Bengal Act, 33 of 1951), together with part of Hastings North or South edge of Clyde Row and Strand Road to the river bank and the areas which were previously under the now defunct Tollygunge Municipality.

(2) The port of Calcutta; and

(3) The Districts of 24 Parganas, Nadia, Howrah and Hoogly.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)-IT/76]

B. N. LALL, Under Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1976

का०आ० 1041.—सांख्यिकी विभाग की दिनांक 30 सितम्बर, 1975 की अधिसूचना सं० एम०-12011/3/75-रा०प्रति०सर्वे-1 में आंशिक परिवर्तन करते हुए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 की धारा 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1976-77 के लिए नियुक्त की गई समिति को 17 फरवरी, 1976 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने का समय दे दिया गया है।

[सं० एम-12011/5/75-भा०सांख्यि० सं०]

हरीश चन्द्रा, उप-सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 25th February, 1976

S.O. 1041.—In partial modification of the Department of Statistics Notification No. M-12011/5/75-NSS. I dated the 30th September 1975, the Committee appointed in exercise of the powers conferred by section 8(1) of the Indian Statistical Institute Act, 1959, for the year 1976-77 has been given time upto the 17th February 1976 for submission of its Report to Government.

[No. M-12011/5/75-ISI]

HARISH CHANDRA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1976

का०आ० 1042.—यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम 1948 (1948 का 16) की धारा 306 के खण्ड (च) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 1 अगस्त 1975 से मेजर जनरल एम०डी० मेहरा को भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य मनोनीत कर दिया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2/62-चि० II में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के खण्ड (च) के अधीन मनोनीत" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए :

"मेजर जनरल एम०डी० मेहरा,
निदेशक, दन्त चिकित्सा सेवाएं,
चिकित्सा निदेशालय सशस्त्र सेना, मुख्यालय,
नई दिल्ली।"

[सं० वी० 12013/3/72-एम०पी०टी०]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 4th February, 1976

S.O. 1042.—Whereas the Central Government, in pursuance of the provisions of clause (f) of Section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) nominated Major General M. D. Mehra, to be a member of the Dental Council of India with effect from the 1st August, 1975;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 3-2/62-MII, dated the 17th October, 1962, namely :—

"Major General M. D. Mehra, Director,
Dental Services,
Medical Directorate Army HQ,
New Delhi".

[No. V. 12013/3/72-MPT]

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का०आ० 1043.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) खण्ड (ख) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं० 5-13/59-चि० 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात

उक्त अधिसूचना में, "भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 45 के समक्ष, "निर्वाचन क्षेत्र" शीर्षक के नीचे

लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी; नामतः

"गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर"

[सं०बी० 11015/43/75-एम०पी०टी०]

विवेक कुमार अग्निहोत्री, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd February, 1976

S.O. 1043.—In pursuance of clause (b) sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading 'Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956', against serial No. 45, under the heading 'Constituency', for the entry, the following entry shall be substituted; namely :—

'Guru Nanak Dev University, Amritsar'.

[No. V. 11015/43/75-MPT]

V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

(चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो)

केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5(1) के अंतर्गत सेवा समाप्त करने का नोटिस

मद्रास, 31 अक्तूबर, 1975

का० आ० 1044.—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसरण में मैं एतद्द्वारा राजकीय चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, मद्रास के अस्थायी सफाई कर्मचारी श्री जी० कोंडिया को नोटिस देता हूं कि उनके द्वारा इस नोटिस के प्राप्त होने अथवा यह नोटिस उन्हें दिये जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के पश्चात् उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी।

[सं० विज/146/74/50]

के० गंगैया, उप-सहायक महानिदेशक

(Medical Store Depot)

NOTICE OF TERMINATION OF SERVICE UNDER RULES 5(i) OF THE CENTRAL CIVIL SERVICES (TEMPORARY SERVICE) RULES, 1965

Madras, the 31st October, 1975

S.O. 1044.—In pursuance of sub-rule (i) of rule 5 of the Central Civil Services (Ty. Service) Rules 1965 I hereby give notice to Shri G. Kondish, Temporary Sweeper, Govt. Medical Store Depot, Madras that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on or as the case may be, tendered to him.

[No. Vig/146/74/50]

K. GANGAYYA, Dy. Asstt. Director General (MS).

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976

का०आ० 1045.—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से परामर्श करके गुजरात राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण को उक्त संघ राज्य क्षेत्र के लिए तथा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रमाणन अभिकरण नियुक्त करती है।

[सं० 7(58)/69-एस०डी०]

टी०बालारामन, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 9th February, 1976

S.O. 1045.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, in consultation with Administration of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, hereby appoints the Gujarat State Seed Certification Agency as a certification agency for the said Union territory and for the purposes of the said Act.

[No. 7(58)/69-SD]

T. BALARAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1976

का० आ० 1046.—वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) की धारा 3 के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के० विश्वानाथन को वन्य प्राणि संरक्षण के सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

[संख्या जे०-13011/7/75-एफ० डी० (डब्ल्यू० एल० एफ०)]

एस० ए० शाह, निदेशक

New Delhi, the 11th February, 1976

S.O. 1046.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints Shri K. Viswanathan as Assistant Director of Wildlife preservation.

[No. J. 13011/7/75-FD(WLF)]

S. A. SHAH, Director.

विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976

का० आ० 1047.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील), नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना सं० 18-25/72-सर्वे० I, तारीख 30 नवम्बर, 1972 को अधिक्रांत करते हुए, निदेश करते हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट भारतीय सर्वेक्षण की साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग और समूह घ में के पदों की बाबत, स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में, स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा और स्तम्भ (3) और (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और ऐसी शास्तियां, जो वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 में की मद संख्याओं के संदर्भ में)		अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5
भाग—I साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग, भारतीय सर्वेक्षण				
1. अधीक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय	भारत का महासर्वेक्षक	(i) भारत का महा सर्वेक्षक	सभी	विभाग/मंत्रालय में सचिव
		(ii) उप महा सर्वेक्षक	(i) से (iv) तक	भारत का महा सर्वेक्षक
2. सभी पद (अधीक्षक, कार्यालय, महा सर्वेक्षक भिन्न)	सर्किल/निदेशालय/शाखा/संस्थान/केन्द्र/प्लांट का प्रधान/उप महा सर्वेक्षक	(i) सर्किल/निदेशालय/शाखा/संस्थान केन्द्र/प्लांट का प्रधान/उप महा सर्वेक्षक	सभी	भारत का महा सर्वेक्षक
		(ii) उप निदेशक/कार्यालय-अध्यक्ष /जो भार साधक अधिकारी सर्वेक्षक/ उप भंडार अधिकारी/भारसाधक अधिकारी, मानचित्र अभिलेख और निर्गम कार्यालय की पंक्ति से नीचे का न हो)	(i) से (iv) तक	सर्किल, निदेशालय/शाखा/संस्थान केन्द्र/प्लांट का प्रधान/उपमहा सर्वेक्षक
भाग-II साधारण केन्द्रीय सेवा समूह घ, भारतीय सर्वेक्षण				
1. महासर्वेक्षक के कार्यालय में के पद	सहायक महा सर्वेक्षक	(i) सहायक महा सर्वेक्षक	सभी	उप महा निर्देशक ।
		(ii) कार्यालय प्रधान/रजिस्ट्रार (महा सर्वेक्षक का कार्यालय) बजट और लेखा अधिकारी (महा सर्वेक्षक का कार्यालय)	(i) से (iv) तक	सहायक महा सर्वेक्षक ।
2. महा सर्वेक्षक के कार्यालय में के पदों से भिन्न पद	(i) उप निदेशक/कार्यालय-प्रधान (भारसाधक अधिकारी सर्वेक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो)/उप भंडार अधिकारी/भार साधक अधिकारी, मानचित्र अभिलेख और निर्गम कार्यालय ।	(i) उप निदेशक/कार्यालय प्रधान (जो भारसाधक अधिकारी सर्वेक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो) उप भंडार अधिकारी/भार साधक अधिकारी, मानचित्र अभिलेख और निर्गम कार्यालय	सभी	सर्किल/निदेशालय/शाखा/संस्थान/ केन्द्र/प्लांट का प्रधान। उप महा सर्वेक्षक ।
		(ii) स्थापन और लेखा अधिकारी	(i) से (iv) तक	संबद्ध सर्किल कार्यालय/संस्थान/ निदेशालय/शाखा/केन्द्र/प्लांट का उप निदेशक और मानचित्र अभिलेख तथा निर्गम कार्यालय की दशा में भार-साधक अधिकारी ।

[सं० 18-107/75-सर्वे० I]

टी०एल०विश्वनाथन, अवर सचिव

Department of Science & Technology

ORDER

New Delhi, the 24th February, 1976

S. O. 1047.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Central and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Science & Technology No. 18-50/72-Sur. I., dated the 30th November, 1972 the President hereby directs that, in respect of the posts in the General Central Service, Group C and Group D of the Survey of India specified in column (1) of the Schedule hereto attached, the authority specified in column (2) shall be the appointing authority, and the authorities specified in columns (3) and (5) shall be the disciplinary authority and the appellate authority, respectively, in regard to the penalties specified in column (4).

SCHEDULE

Description of post	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
PART-I GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP C SURVEY OF INDIA				
1. Superintendent, Surveyor General's Office.	Surveyor General of India	(i) Surveyor General of India	All	Secretary in Department/ Ministry.
		(ii) Deputy Surveyor General	(i) to (iv)	Surveyor General of India.
2. All post (other than Superintendent Surveyor General's office).	Head of Circle/Directorate Branch / Institute/Centre/ Plant/Deputy Surveyor General.	(i) Head of Circle/Directorate Branch /Institute / Centre/ Plant/Deputy Surveyor General.	All	Surveyor General of India.
		(ii) Deputy Director/Head of office (not below the rank of officer Surveyor-in-Charge)/ Deputy stores officer/officer-incharge, Map Record and Issue office).	(i) to (iv)	Head of Circle /Directorate/ Branch/Institute/Centre/Plant/ Deputy Surveyor General.
PART-II GENERAL CENTRAL SERVICE-GROUP D. SURVEY OF INDIA				
1. Posts in the Surveyor General's Office	Assistant Surveyor General	(i) Assistant Surveyor General	All	Deputy Surveyor General.
		(ii) Head of Office/Registrars (Surveyor General's office) Budget & Accounts Officer (Surveyor General's office).	(i) to (iv)	Assistant Surveyor General.
2. Posts other than posts in the Surveyor General's office.	Deputy Director/Head office (not below the rank of officer Surveyor-in-Charge)/ Deputy Stores Officer/Officer-in-charge, Map Record & issue Office.	(i) Deputy Director/Head of Office (not below the rank of officer Surveyor-in-Charge)/ Deputy Stores Officer/ officer-in-Charge, Map Record & issue Office.	All	Head of Circle/Directorate/ Branch/Institute/Centre/Plant/ Deputy Surveyor-General.
		(ii) Establishment and Accounts Officer.	(i) to (iv)	Deputy Director of the Circle Office/Institute/Directorate/ Branch/Centre/Plant Concerned and officer-in-charge in the case of Map Record and Issue Office.

[No. 18-107/75-Sur-I]

T. L. VISWANATHAN, Under Secy.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1976

पुरातत्व

का० आ० 1048.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात दो मास के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आक्षेप पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	संस्मारक का नाम	राजस्व भूखण्ड सं० जिसे संरक्षणाधीन किया जाना है
1	2	3	4	5	6
राजस्थान	जयपुर	आमेर	आमेर	नीचे दिए गए रेखांक में तथा दर्शित, जयगढ़ दुर्ग, किलाबन्दी की दीवारों, संसक्त दीवार के भाग और पार्श्वस्थ क्षेत्र सहित।	खसरा सं० 874 (भाग) खसरा सं० 875 खसरा सं० 881 खसरा सं० 882 (भाग) खसरा सं० 919 (भाग) खसरा सं० 885 (भाग) खसरा सं० 884 खसरा सं० 883 खसरा सं० 897 (भाग) खसरा सं० 894 (भाग) खसरा सं० 895 (भाग) खसरा सं० 896 (भाग)

क्षेत्र		सीमाएं		स्वामित्व	टिप्पणियां
बीघा	बिस्वा				
7		8		9	10
49	4	उत्तर—	खसरा सं० 872	वन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।	
64	0		खसरा सं० 873		
64	0		खसरा सं० 874 (भाग)		
59	5		और		
20	17		खसरा सं० 885 (भाग)		
16	0	पूर्व—	खसरा सं० 874 (भाग)		
48	0		खसरा सं० 882 (भाग)		
64	0		खसरा सं० 919 (भाग)		
28	7		खसरा सं० 917		
13	13		खसरा सं० 914 और		
55	11		खसरा सं० 998		
55	11	दक्षिण—	खसरा सं० 897 (भाग)		
538	8		खसरा सं० 896 (भाग)		
			खसरा सं० 895 (भाग)		
			खसरा सं० 894 (भाग)		
		पश्चिम—	खसरा सं० 894 (भाग)		
			खसरा सं० 885 (भाग)		
			खसरा सं० 880 और		
			खसरा सं० 876		

[सं० 2/24/75-एम०]

एम० एन० देशपाण्डे, महानिदेशक, पदेन संयुक्त सचिव

जयगढ़ किले का स्थल मानचित्र

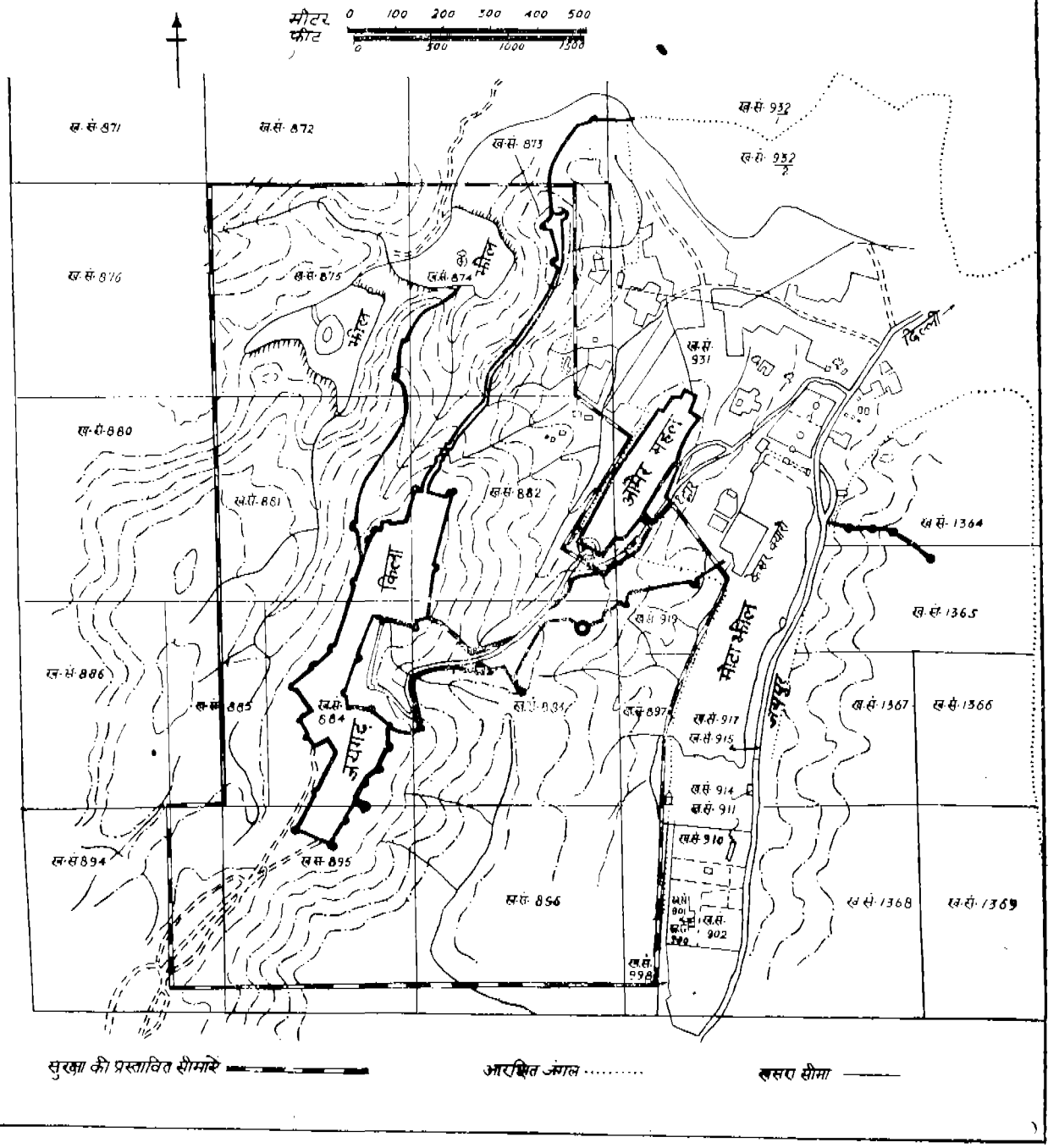

MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE

Archaeological Survey of India

New Delhi, the 25th February, 1976

ARCHAEOLOGY

S.O. 1048.—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Schedule attached hereto is of national importance ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Arechaeological sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection made within two months after the issue of this notification by any person interested in the said ancient monument will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers to be included under protection	Area Bigha	Area Biswa	Boundaries	owner-ship	Remarks
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Rajasthan	Jaipur	Amer	Amer	Jaigarh Fort with fortification walls portion of connected wall and adjacent area as shown in the site plan reproduced below	Kh.No.874 (Part) Kh.No.875 Kh.No.881 Kh.No.882 (Part) Kh.No.919 (Part) Kh.No.885 (Part) Kh.No.884 (Part) Kh.No.883 Kh.No.897 Kh.No.894 (Part) Kh.No.895 (Part) Kh.No.896 (Part)	49 64 64 59 20 16 48 64 28 13 55 55 538-8	4 0 0 5 17 0 0 0 7 13 11 11	North.— Kh.No.872 Kh.No.873 Kh.No.874 (Part) and Kh.No.885 (Part) East.— Kh.No.874 (Part) Kh.No. 882 (Part) Kh.No.919 (Part) Kh.No.917 Kh.No.914 and Kh.No.998 South.— Kh.No. 897 (Part) Kh.No.896 (Part) Kh.No. 895 (Part) and Kh.No.894 (Part) West.— Kh.No. 885 (Part) Kh.No 880 and Kh.No. 876	Forest Department Rajasthan Government Jaipur	

[No. 2/24/75-M]

M. N. DESHPANDE, Dir. Gen,

Ex-officio Joint Sec.

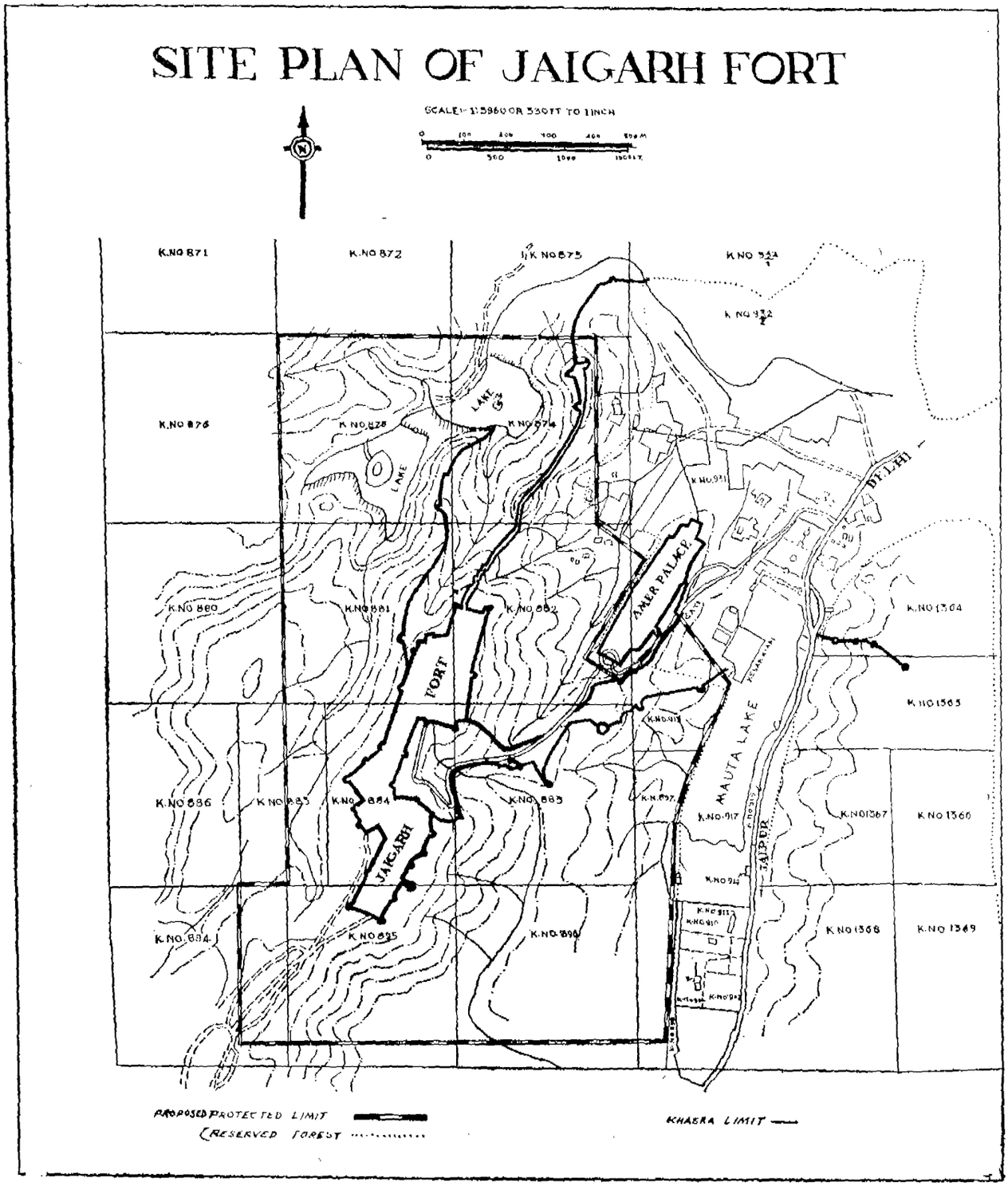

SITE PLAN OF JAIGARH FORT

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का० आ० 1049.—विद्युत् प्रदाय अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की समय समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या बिजली-दी-28(8)/72, दिनांक 13 जून, 1973 के प्रतिस्थापन में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, जिसमें निम्न सदस्य, नामशः

1. श्री वाई० टी० शाह,
   सचिव, भारत सरकार,
   ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत् विभाग,
   नई दिल्ली ।

2. श्री एच० आर० कुलकर्णी,
   सदस्य (ताप विद्युत्)
   केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ।

3. श्री एस० एस० मूर्ति,
   सदस्य (विद्युत् प्रणाली),
   केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ।

4. श्री के० एस० सुब्रह्मण्यम,
   सदस्य (जल विद्युत्),
   केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ।

5. श्री एम० बी० राव,
   संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार,
   विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय,
   विधि कार्य विभाग,
   नई दिल्ली ।

होंगे, का आगामी आदेशों तक गठन करती है और श्री वाई० टी० शाह को उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या बिजली-2-28 (8)/72]
सुरेन्द्र प्रकाश जैन, उप-निदेशक ।

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 23rd February, 1976

S.O. 1049.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) and in supersession of the erstwhile Ministry of Irrigation and Power Notification No. EL. II-28(8)/72 dated the 13th June, 1973, as amended from time to time, the Central Government hereby constitutes, until further orders, the Central Electricity Authority consisting of the following members namely :—

1. Shri Y. T. Shah, Secretary to the Govt. of India, Ministry of Energy, Department of Power, New Delhi.

2. Shri H. R. Kulkarni, Member (Thermal), C.E.A.

3. Shri S. S. Murthy, Member (Power Systems), C.E.A.

4. Shri K. S. Subrahmanyam, Member (HE), C.E.A.

5. Shri M. B. Rao, Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs, New Delhi.

and

appoints Shri Y. T. Shah, as Chairman of the said Authority.

[No. EL. II-28(8)/72]
S. P. JAIN, Dy. Dir.

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976

का० आ० 1050.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 (1950 का 64) की धारा 44 की उपधारा 2 के खण्ड (च) के साथ पठित उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (सलाहकार समिति) नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम दिल्ली परिवहन निगम (सलाहकार समिति) (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली परिवहन निगम (सलाहकार समिति) नियम 1974 में, नियम 3 में खण्ड (ङ) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि" ।

[सं. 15-टी ए जी (15)/72]
एन० ए० ए० नारायणन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 24th February, 1976

S.O. 1050.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of section 44 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Transport Corporation (Advisory Council) Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Transport Corporation (Advisory Council) (Amendment) ules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Transport Corporation (Advisory Council) Rules, 1973, in rule 3, for clause (m), the following clause shall be substituted, namely :—

"(m) Two representatives of the Central Government employees".

[No. 15-TAG (15)/72]
N. A. A. NARAYANAN, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976

का० आ० 1051.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 3 फरवरी, 1973 में प्रकाशित भारत सरकार के

निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 299, तारीख 23 जनवरी, 1973 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
(i) प्रबन्धक कार्मिक सेवाएं, मुम्बई क्षेत्र, इण्डियन एयरलाइन्स, मुम्बई ।	इंडियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे ऐसे परिसर इंडयिन एयरलाइंस के कब्जे में हैं या उस के द्वारा पट्टे पर दे दिए गए हैं और जो इण्डियन एयरलाइन्स, मुम्बई क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।
(ii) प्रबंधक कार्मिक सेवाएं, कलकत्ता क्षेत्र, इण्डियन एयरलाइन्स, कलकत्ता ।	इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे ऐसे परिसर इंडियन एयरलाइंस के कब्जे में हैं या उसके द्वारा पट्टे पर दे दिए गए हैं और जो इण्डियन एयरलाइन्स कलकत्ता क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं ।
(iii) प्रबन्धक कार्मिक सेवाएं, दिल्ली क्षेत्र, इण्डियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली ।	इंडियन एयरलाइन्स के परिसर चाहे ऐसे परिसर इंडियन एयरलाइन्स के कब्जे में हैं या उसके द्वारा पट्टे पर दे दिए गए हैं और जो इण्डियन एयरलाइन्स, दिल्ली क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं ।
(iv) प्रबन्धक कार्मिक सेवाएं, मद्रास क्षेत्र, इंडियन एयरलाइन्स, मद्रास ।	इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे ऐसे परिसर, इण्डियन एयरलाइन्स के कब्जे में हैं या उसके द्वारा पट्टे पर दे दिए गए हैं और जो इंडियन एयरलाइन्स मद्रास क्षेत्र के प्रणासनिक नियंत्रण के अधीन हैं ।
(v) मुख्य प्रशासन अधिकारी, इंडियन एयरलाइन्स नई दिल्ली ।	इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे ऐसे परिसर इण्डियन इयरलाइन्स के कब्जे में हैं या उसके द्वारा पट्टे पर दे दिए गए हैं और जो इण्डियन एयरलाइन्स मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं ।

[सं० ए० वी० 18012/13/75-ए० सी०]

एस० बी० भट्टाचार्य, अवर सचिव ।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th February, 1976

S. O. 1051.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 299 dated the 23rd January, 1973, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd February, 1973, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of Gazetted officers of Government , to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
(i) Manager Personnel Services, Bombay Region, Indian Airlines, Bombay.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of Indian Airlines in its Bombay Region.
(ii) Manager Personnel Services, Calcutta Region, Indian Airlines, Calcutta.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of Indian Airlines in its Calcutta Region.
(iii) Manager Personnel Services, Delhi Region, Indian Airlines, New Delhi.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of Indian Airlines in its Delhi Region.
(iv) Manager Personnel Services, Madras, Region, Indian Airlines, Madras.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the Administrative control of Indian Airlines in its Madras Region.
(v) Chief Administrative Officer, Indian Airlines, New Delhi.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of the Headquarters of Indian Airlines at New Delhi.

[No. AV.18012/13/75-AC]

S.B. BHATTACHARYA, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976

का० आ० 1052.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971 के नियम 6 के अनुसरण में निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित राजपत्रित अधिकारी को उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में सम्पदा

अधिकारी के समक्ष लम्बित किन्हीं कार्यवाहियों को किसी अन्य सम्पदा अधिकारी को जो उनके निपटान के लिए सक्षम है, अन्तरित करने और उनका निपटान करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

सारणी

राजपत्रित अधिकारी	सरकारी स्थान
(1)	(2)
श्री आर० एम० वत्स, आयुक्त (भूमि तथा आवास), दिल्ली विकास प्राधिकरण।	दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित स्थान और केन्द्रीय सरकार से संबंधित ऐसे अन्य स्थान जिनका नियंत्रण और प्रबन्ध उक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाता है ।

[सं० के०-11011(1)/74-यू० डी० 1]
के० बिस्वास, उप सचिव

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 20th February, 1976

S. O. 1052. In pursuance of rule 6 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1971 the Central Government hereby authorises the Gazetted officer mentioned in Column 1 of the Table below to transfer any proceedings pending before an Estate Officer and pertaining to public premises specified in column 2 of the said Table, for disposal to any other Estate Officer competent to dispose of the same.

TABLE

Gazetted Officer	Public Premises
1	2
Shri R.M. Vats, Commissioner (Land & Housing), Delhi Development Authority.	Premises belonging to the Delhi Development Authority and such other premises belonging to the Central Government as are controlled or managed by the said Authority.

[No. K-11011/(1)/74-UD/IB.]
K. BISWAS, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1976

का० आ० 1053.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों के बेदखली), अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह भी निदेश करती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों के सम्बन्ध में अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अभिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्गों और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
1. प्रबन्धक, भारत सहकार मुद्रणालय, नासिक	प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं ।
2. प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी	प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं ।
3. प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय नीलोखेड़ी ।	प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं ।
4. प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, संत्रागाची ।	प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, संत्रागाची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं ।
5. प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद ।	प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं ।
6. कर्मशाला प्रबन्धक, (फोटोलिथो), भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, भुवनेश्वर ।	कर्मशाला प्रबन्धक (फोटोलिथो), भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, भुवनेश्वर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं ।
7. सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक	सहायक प्रबन्धक (तकनीकी), भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं ।
8. महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।	महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं ।

[सं० डी०-11031/5/75-मुद्रण]
धन राज, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 1976

S.O.1053—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints

the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of Gazetted Officers of the Government to be estates officers for the purposes of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers, by or under, the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
1. Manager, Government of India Press, Nasik.	Public promises including land and buildings under the administrative control of the Manager, Government of India Press, Nasik, situated within the Press Colony.
2. Manager, Government of India Press, Koratty.	Public premises including land and buildings under the administrative control of the Manager, Government of India Press, Koratty, situated within the Press Colony.
3. Manager, Government of India Press, Nilokheri.	Public premises including land and buildings under the administrative control of the Manager, Government of India Pres , Nilokheri, situated within the Press Colony.
4. Manager, Government of India Press, Santragachi.	Public premises including land and buildings under the administrative control of the Manager, Government of India Press, Santragachi, situated within the Press Colony.
5. Manager, Government of India Press, Faridabad.	Public premises including land and buildings under the administrative control of the Manager, Government of India Press, Faridabad, situated within the Press Colony.
6. Works Manager (Photo-Litho), Government of India Text Books Press, Bhubneshwar.	Public premises including land and buildings under the administrative control of the Works Manager (Photo-Litho), Government of India Text Books Press, Bhubneshshwar, situated within the Press Colony.
7. Assistant Manager (Technical), Government of India Press Gangtok.	Public premises including land and buildings under the administrative control of the Assistant Manager (Technical), Government of India Press, Gangtok, situated within the Press Colony.
8. General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.	Public premises including land and buildings under the administrative control of the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi, situated within the Press Colony.

[F. No. D-11031/5/75-Ptg.]
DHAN RAJ, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

का० आ० 1054:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इंडियन कापर काम्पलेक्स की मोसाबोनी खान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 3), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इंडियन कापर काम्पलेक्स की मोसाबोनी खान, डाकघर मोसाबोनी खान, जिला सिंहभूम के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री दिरजामान नूर, गुलाबशुक्ल, जनकधारी सिंह, राजनारायण सिंह, पद्मबहादुर और चन्द्रशेश्वर प्रसाद को पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल-29011/21/75-डी० प्रो० 3(ख)/डी-(4ख)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1975

S.O. 1054.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the mangement of Mosaboni Mines of Indian Cooper Complex of Messrs Hindustan Cooper Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Cooper Limited, Post Office Mosaboni Mines, District Singhbhum in dismissing Sarva-Shri Dirjaman Neor, Gulab Shukla, Jankdhar Singh, Raj Narain Singh, Padam Bahadur and Chandreshwar Prasad was justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?

[No. L-29011/21/75-D.O. 3(B)/D. IV (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1976

का० आ० 1055.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की जादूगुडा यूरेनियम खान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 3), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स यूरेनियम कार्पोरेशन आँफ इंडिया लिमिटेड की जादूगुडा यूरेनियम खान के प्रबन्धतंत्र की श्री राम अनूपसिंह, भूतपूर्व—भारी यान चालक, आँटो सैक्शन (मिल डिविजन) को 3-8-1974 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल०-43012(7)/75-डी-4(ख)]

ORDER

New Delhi, the 3rd January, 1976

S.O. 1055.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaduguda Uranium Mines of Messrs Uranium Corporation of India, Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jaduguda Uranium Mines of Messrs Uranium Corporation of India, Limited in dismissing Shri Ram Anup Singh Ex-Heavy Vehicle Driver, Auto Section (Mill Division) with effect from 3-8-1974 was justified? if not. to what relief is the said workman entitled?

[No. L-43012(7)/75-D-IV (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1976

का० आ० 1056.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स माइनिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, ठेकेदार, डाकघर बार्बिल के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी डा० बी० एन० मिश्रा होंगे, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स माइनिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, ठेकेदार, डाकघर बार्बिल के प्रबन्धतंत्र की, निम्नलिखित कर्मकारों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों को स्थानांतरित करने और बाद में उनकी सेवाओं को समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी?

नाम	तारीख
(1)	(2)
1. फूलचंद हरिजन	26-2-75
2. इन्द्रासन दुसाद	24-2-75
3. इन्द्रामोनी तान्ति	—वही—
4. सोचा हरिजन	28-2-75
5. सकलदीप हरिजन	—वही—
6. मिश्रि ठाकुर	—वही—
7. भिगुनाथ हरिजन	—वही—
8. भगवत हरिजन	—वही—
9. बुधाश सांगा	—वही—
10. झाल्लु सोरेन	—वही—

यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल-26012(1)/76-डी-4 (बी)]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 21st January, 1976

S.O. 1056.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Mining and Transporting Company, Contractors. Post Office Barbil and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Dr. B. N. Misra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Mining and Transporting Company, Contractors, Post Office Barbil in transferring the following workmen on the dates shown against each and subsequently terminating their services, was justified?

Name	Date
1. Fulchand Harijan	26-2-75
2. Indrasan Dusad	24-2-75
3. Indramony Tanti	—do—
4. Socha Harijan	28-2-75

1	2
5. Sakaldip Harijan	28-2-75
6. Mishri Thakur . .	—do—
7. Bhirgunath Harijan . .	—do—
8. Bhagwat Harijan . .	—do—
9. Buash Sanga . .	—do—
10. Jhallu Soren . .	—do—

If not, to what relief are the concerned workmen entitled?

[No. L-26012(1)/76-D-IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1976

का० आ० 1057.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स मैटकाफ एण्ड हाड्गकिनसन प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स मेटकाफ एण्ड हाड्गकिनसन प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र की श्री ए० एन० डी० सिलवा, ज्येष्ठ सर्वेक्षक को 1 अगस्त 1975 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-31012/5/75-डी-4ए]

ORDER

New Delhi, the 5th January, 1976

S.O. 1057.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Metcalfe and Hodgkinson Private Limited, Bombay and their workmen in respect of the matters, specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Metcalfe and Hodgkinson Private Limited, Bombay in having dismissed Shri A. N. D. Silva, Senior Surveyer, from service with effect from 1st August, 1975, is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L-31012/5/75/DIV/A]

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1976

का० आ० 1058.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सीताराम वेयरहाउस क्लीयरिंग, फार्वर्डिंग एण्ड शिपिंग एजेन्ट्स, कोचीन-3 के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालानियापन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स सीताराम वेयरहाउस, क्लीयरिंग फार्वर्डिंग एण्ड शिपिंग एजेंट्स कोचीन-3 के प्रबंधतंत्र द्वारा अपने लिपिक, श्री वी० भास्करन पर अधिरोपित पदच्युति का दण्ड न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल-35012(4)/75-डी-4/ए]

ORDER

New Delhi, the 6th January, 1976

S.O. 1058.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Sitaram Warehouse, Clearing, Forwarding and Shipping Agents, Cochin-3 and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the punishment of dismissal imposed by the management of Messrs Sitaram Warehouse, Clearing, forwarding and Shipping Agents, Cochin-3 on Shri V. Bhaskaran, their clerk, is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L-35012(4)/75-D-IVA]

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1976

का० आ० 1059.—मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई ने 15 जुलाई, 1975 को एक पंचाट दिया;

और केन्द्रीय सरकार की राय में, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट, प्रश्न पर उक्त पंचाट के निर्वचन के बारे में एक शंका उत्पन्न हो गई है और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न को, निर्वचन के लिए, निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 6 सितम्बर, 1975 में, पृष्ठ 3257 से 3263 पर प्रकाशित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई का पंचाट, तारीख 15 जुलाई 1975, इस प्रश्न का भी अवधारण करता है कि क्या गतिशील क्रेन पर्यवेक्षक (कर्मी) के पदों का सृजन अपेक्षित था या नहीं ?

[संख्या एल-31016(3)/75-डी-4(ए)]
नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1976

S.O. 1059.—Whereas in an industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay, and their workmen, the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, gave an award on the 15th July, 1975;

And, whereas, in the opinion of the Central Government a doubt has arisen as to the interpretation of the said award on the question specified in the Schedule hereto annexed, and the Central Government considers it desirable to refer the question for interpretation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, dated the 15th July, 1975, and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 6th September, 1975 at pages 3257 to 3263, also determines the question, whether creation of posts of Mobile Crane Supervisor (Operative) was required or not.

[No. L-31016(3)/75-D. IV(A)]
NAND LAL, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1976

का० आ० 1060 :—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र की श्री युधिष्ठिर को सहायक खंजाची के रूप में न खपाने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या 23/124/69/एल० आर० 3]
आर० कुंजिथापदम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 20th January, 1976

S.O. 1060.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (I) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Central Bank of India in not absorbing Shri Yudhisthir, as Assistant Cashier is justified? If not to what relief is the said workman entitled?"

[No. 23/124/69-LR. III]

New Delhi, the 4th March, 1976

S.O. 1061.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th February, 1976.

BEFORE SHRI H. R. SODHI, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) CHANDIGARH

Reference No. 1/C of 1974

BETWEEN

the workman and the management of Central Bank of India.

APPEARANCES :

Shri R. K. Joshi—for the workmen.

Shri C. L. Chawla—for the respondent Bank.

AWARD

Shri Dev Dutt Sharma was appointed as an Assistant Cashier-cum-Godown Keeper by the respondent Bank under its Batala Branch initially for a period of one month with effect from 16-10-1968 and his services were later extended from time to time and ultimately terminated on 3-5-1972. He worked for a total period of 350 days as alleged by the workmen but the management admits that he worked only for 343 days.

It is the case of both the parties that there were intermittent breaks. The details of the exact periods for which the workman worked are stated as under :—

From	To	Number of days
16-10-1968	15-1-1969	91 days
29-1-1969	16-4-1969	78 days
27-4-1969	8-5-1969	18 days
12-5-1969	19-5-1969	8 days
21-7-1969	27-7-1969	7 days
1-10-1969	17-10-1969	17 days
2-2-1970	13-3-1970	40 days
2-2-1970	2-5-1972	91 days
		350 days

The management as already observed does not admit employment for 7 days from 21-7-1969 to 27-7-1969. The concerned workman felt aggrieved on the termination of his service and through the Central Bank of India Employees' Union, of which he was presumably a member, served a demand notice raising an industrial dispute in challenging the same. The dispute could not be resolved amicably through conciliation proceedings and the Central Government in exercise of the powers conferred on it by section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred as per Notification No. L. 12012/102/73/IRIII, dated 2-1-1974, published in the Gazette of India, the following matter to this Tribunal for adjudication:—

'Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Shri Dev Dutt Sharma, Assistant Cashier-cum-Godown-Keeper at the Batala Branch of the Bank with effect from the 3rd May, 1972 was justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. Notices were issued to the parties, who filed their respective pleadings leading to the following issues :—

"(1) Whether Shri Dev Dutt Sharma, the concerned workman was in the permanent staff of the respondent bank or could his services be not regarded as permanent in the circumstances of the present case?

(2) Whether the action of the respondent bank in terminating the services of the aforesaid workman with effect from 3rd May, 1972 is justified and if not to what relief is the workman entitled?"

3. I shall now proceed to dispose of issues in the light of evidence produced in the case.

Issue No. 1

By no process of reasoning, Shri Dev Dutt Sharma can be said to have ever been a member of the permanent staff. The workmen admit in the claim statement that he was employed for different periods from time to time and that breaks in service were intended only to destroy the continuity of service. Whatever be the motive with the management, the fact remains that the workman was initially appointed as a temporary Godown-Keeper to work at Gurdaspur out-station and it was specifically stipulated in the letter of his appointment that his appointment would cease on the expiry of the period of one month. Shri R. P. Malhotra, R.W.1, Assistant Zonal Manager, Chandigarh, was posted at Amritsar as Chief Agent from May, 1970 to January, 1972 and he was then controlling 25 branches including Gurdaspur branch under an overall control. It is deposed by him that appointments were generally made by the Chief Agent, Amritsar, even in respect of employees required in other branches, though at times to meet a temporary need, the local Agent could also made an appointment. Shri D. N. Puri, R.W.2 was the Agent posted at Batala from September, 1966 to sometime in early June, 1970 and latter he joined Patiala branch in the same position in June, 1970 where he continued till 24-3-1972. It was this officer, who had mainly issued appointment letters from time to time in regard to the appointment of the workman. These letters Exts. R/5, R/6 and R/7 have been duly proved. The period of service as specified in the said letters has been varying. It is admitted by Shri D. N. Puri, who appears to have had a soft corner for the workman that the work at Gurdaspur outstation of the Godown-Keeper had later increased and it was for that purpose that a regular employee was afterwards posted there. The case of the management is that the out-station to which Shri Dev Dutt was posted was originally intended to meet seasonal needs of the business community and in particular of M/s. Gurdaspur Rice Mills. As a matter of fact, M/s. Gurdaspur Rice Mills were told by letter dated 30-10-1968, Ext. R/2, that a temporary Godown-Keeper was being posted in their factory and they could pay the emoluments to him as mentioned in the appointment letter. There is, in my opinion, no substance in the plea of the workman that he should be deemed to have been permanently employed and to say the least, the plea is frivolous.

It has now to be seen that having been appointed as a temporary Godown-Keeper, could he be said to have acquired any right to be selected for permanent service in view of Shastry and Desai Awards or Bipartite Settlement which beyond dispute regulate relations of the employers with their employees and the respondent bank is one of them. The grievance of the workman is that despite the fact that twice from 16-10-1968 to 15-1-1969 and 2-2-1972 to 2-5-1975, he had continuously worked for more than 90 days and for a total of 350 days in a period of 3-1/2 years, he was not selected for permanent appointment, though others not qualified, were appointed in regular vacancies. There is no manner of doubt that the recruitment policy of the respondent bank has been haphazard. It has, of course, been made a condition precedent that a candidate in order to be recruited in a regular vacany should pass a written test and also qualify in an interview but there is no dearth of instances where the bank authorities employed persons, who had either failed in a test or were otherwise ineligible and I have indeed so held in an Award in Reference No. 15/C of 1974 where the services of one Ram Paul had been terminated. I cannot gain resist from observing that the bank miserably failed to adhereto its recruitment policy as laid down from time to time and that it was so not in a few cases only. Be that as it may and howsoever flagrant be the misuse of discretion in oher cases by the bank authorities, the present workman does not get any enforcible right to be selected for a permanent vacancy, though it would have been more proper if he were given a chance for regular service when his record was satisfactory as desposed by Shri Puri, W.W.2.

The workman produced a number of witnesses such as Sarvshri Vinod Kumar Nagrath, W.W.1, Gurinder Pal Singh, W.W.2, Venkateshwaran, W.W.3, H. L. Shorey, W.W.4, Satish Gaind Stenographer, W.W.5. Tara Chand Gupta, W.W.6, K. L. Gupta, Assistant Zonal Manager, W.W.7, O. P. Saxena, Assistant Labour Commissioner (Central) W.W.8 and himself went into the witness box as W.W. 9 The statement of Shri Vinod Kumar Nagrath does not help the workman. All that the witness says is that he is a graduate and fulfills the qualification. Shri Gurinder Pal Singh, W.W.2 is a third class Matriculate but beyond that the testimony of this witness is of no assistance to the workman. Shri Venkateshwaran, W.W.3 is the Superintendent of the respondent Bank in its Zonal office at Delhi. He has orally disposed with regard to the recruitment policy of the bank and the qualifications required of the candidates to make them eligible for appointment. The witness has given some instances where the candidates, though not qualified, were taken in serivce. Shri H. L. Shorey, Agent, Central Bank of India, W.W.4, produced a prepared statement Ext. A/4 giving the names of Godown-Keepers posted at Gurdaspur out-station branch from time to time. We have in his statement that the out-station branch used o be closed occasionally during the off-season of Rice shelling and that originally it was intended to be a seasonal branch but now the branch has been made regular. Shri Satish Gaind, W.W.5, produced statements Exts. A/6 and A/7 giving the lists of candidates who were called for interview and those who were selected. The object of such evidence as produced by the workman seems to be to impress upon the Tribunal that even un-qualified persons had been recruited and that similarly the workman could also have been made regular. Shri Tara Chand, W.W.7 has given from memory the names of some workmen, who, according to him, were not qualified but had still been recruited by Delhi office. Shri K. L. Gupta, W.W.7, appeared before the Assistant Labour Commissioner, Shri Saxena, W.W.8 in the course of conciliation proceedings and it was admitted there that irregular appointments had been made by the bank. Shri Dev Dutt Sharma, appearing as his own witness, states that he took the test in 1970 and was declared successful. He, however, deposed that he was called for interview but no opportunity of service was given to him. I

have already said that the bank has not been following any uniform policy in the matter of recruitment and may be that candidates were recruited for extraneous reasons even though they did not fulfil the qualifications as laid down in the recruitment policies. It has also to be remembered that the concerned workman in this case also did not qualify and the mere fact that he worked intermittently for 350 days and at times for 90 days at a time, does not give him a right to be taken in regular service unless it could be shown that he is being victimized in regard to which there is not an iota of evidence.

There is no violation of the Awards or of the Bipartite Settlement either. It is conceded on behalf of the workman that before the termination of services of the concerned workman, he was entitled to 14 days' notice as envisaged in para 522(iv) of Shastry Award. No question of any notice arises when at times the appointment was even for 7/8 or 17 days. Even if it be assumed that the workman fell in the category of temporary employees as envisaged in para 27 of the Bipartite Settlement, it cannot be said that he has been discriminated within the meaning of para 20.12 of the same settlement which gives a right to the temporary workmen other than Godown-keepers to be given preference for filling up permanent vacancies. The workman, in the instant case, was a temporary Godown-keeper and moreover there is no evidence to show as to how his inability was at par with others who had been selected. There can be candidates all of whom may be qualified but some of them may be inefficient. The workmen have not been able to establish the circumstances on which any finding could be given that other things were equal so as to entitle the workman to a preference in the matter of selection in a permanent post. At any rate, I have, no doubt, in my mind that the breaks in serevice were not honestly created as the anxiety of the management seems to have been not to let the workman have continuity of service which might have entitled him to claim regularization of his service. Even if the workman does not have an enforceable, right and I am not quashing the order of the termination of his services, I direct that he should be given one of the next five vacancies in the same grade that might arise in future so that justice is done to him. There is no gain saying the fact that the record of the workman was good and the working of the management in the matter of employments does permit the recruitments of such candidates.

The reference stands answered accordingly. There is no order as to costs.

9-1-1976

H. R. SODHI, Presiding Officer,

[F. No. L-12012/102/73/LR III]

S.O. 1062.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th February 1976.

BEFORE SHRI H. R. SODHI, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) CHANDIGARH.

Reference No. 15/C of 1974

BETWEEN

the workmen and the management of Central Bank of India.

PRESENT :

Shri R. K. Joshi—for the workmen.

Sarvashri C. L. Chawla & H. L. Chhiber—for the respondent Bank.

AWARD

Shri Ram Paul was appointed as a temporary Assistant Cashier on his application, Ext. M/1, dated 20-12-72. The exact date of appointment is not known as M.W.1, Shri H. L. Maini, Agent, Central Bank of India, Civil Lines, Ludhiana, who made the appointment and is the only witness for the mangement, could not produce the original letter of appointment. The services of the workman were, however, terminated on 13-3-73 and he raised an industrial dispute. Shri O. P. Saxena, Assistant Labour Commissioner (Central), Chandigarh conducted the conciliation proceedings, but the attitude of the management was unhelpful and he had, therefore, to close the case as is indicated from Ext. A/1, the record note of the proceedings before him. The Central Government, in exercise of the powers conferred on it by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred as per Notification No. L. 12012/55/74/LRIII, dated 11th December, 1974, published in the Gazette of India, the following matter for adjudication to this Tribunal :—

> "Whether the action of the management of the Central Bank of India in terminating the services of Sh. Ram Paul, Ex-Assistant Cashier, Civil Lines, Ludhiana, with effect from the 13th March, 1973 is legal and justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. On the pleadings of the parties the following issues were framed :—

(1) Whether the management was justified in terminating the services of Shri Ram Paul, ex-Assistant Cashier, Civil Lines Ludhiana, respondent Bank, with effect from 13-3-73?

(2) If issue No. (1) is found against the management and for the workman, to what relief, if any, is the workman entitled?

3. The statement of claim was filed by the Central Bank of India Employees Union (Haryana) which is a party to the reference.

The workmen have pleaded that the concerned workman Shri Ram Paul, was appointed temporarily, but in a permanent vacancy and the intention was to let him continue in service so as to be ultimately absorbed as a permanent hand. The services of Shri Ram Paul are said to have been terminated abruptly on 13th March, 1973, and the date of joining in the claim statement is given as "12-12-72".

A further averment is that the termination of services of the workman offended against Shastry Award, as 14 days' notice was not given, and that there has also been a violation of the provisions of a Bipartite Settlement. According to the workmen, the management adopted unfair labour practice because of the workman being a member of the allegdly minority union, which was not in good books of the Bank authorities. No doubt the workman failed by one mark in the written qualifying test, but it is pleaded by the union that a large number of employees who were not eligible for appointment were recruited either under the pressure of the majority union or because of their relationship with some people who mattered with the management. There annextures, later marked in the course of evidence as Exts. A/3, A/4 and A/5 were filed with the claim statement.

4. The management, in their written statement, have not controverted the averments that the appointments of 44 persons, as referred to in Ext. A/5, were irregular or that there is any wrong statement of fact in the other annexures. Exts. A/3 & A/4. The stand of the Bank, however, is that every case referred to in these documents, was decided on individual merits, and that there was no discrimination nor any similarity of circumstances existed between the case of Shri Ram Paul and those other workmen whose appointments are alleged to be irregular.

It was for the management to justify termination of services and the burden of Issue No. (1) lay on them. The solitary statement of Shri H. L. Maini, M.W. 1, is of no help in disposing of the issues involved in this case and in the examination of this witness, there is not the least assertion that there was no unfair labour practice or that there was no discrimination.

In view of there being no oral evidence worth the name produced by the management, I have to decide the case on the documents the contents of which stand un-controverted.

5. Before I discuss the relevant documents on the record, it is necessary to make a mention that there are in existence Shastry Award, Desai Award and a Bipartite Settlement in

regard to industrial disputes between certain Banking Companies and employees thereof, who have formed different Associations and it is common ground that these awards contain guide-lines for the respondent Bank as well.

6. In regard to the procedure for termination of employment, it is provided in para 522 (iv) of the Shastry Award that :

> "The services of any employee other than a permanent employee or probationer may be terminated, and he may leave service, after 14 days' notice. If such employee leaves service without giving such notice he shall be liable for a week's pay (including all allowances)".

The Desai Award defines a "temporary employee" in paras 21.20 and 23.15, but this definition has been superseded in the Bipartite Settlement, in para 27 whereof a "temporary employee" has been defined to mean :

> "a workman who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman."

Para 20.12 enjoins that "other things being equal, temporary workman (other than godown-keeper) will be given preference for filling permanent vacancies and if selected they may have to undergo probation".

Beyond dispute, Shri Ram Paul, concerned workman, was a temporary employee, other than a godown keeper and the matter of termination of his service or absorption in a permanent vacancy was to be regulated in the interest of Industrial peace by the aforesaid Awards. He was not given 14 days notice as required by para 522 (iv) of Shastry Award, nor was any effort made to absorb him permanently. The management has not shown as to why it became necessary to terminate his services abruptly on 13th March, 1973. What appears to have been is that he took a written test in which he secured one mark less than the minimum required to make him eligible to appear before the Interview Committee, set up by the respondent Bank for appointment of clerical staff. The case of the workman is that there were many other employees, who had not qualified in accordance with Bank's recruitment policy, But were still taken in service on the permanent staff yet equal and similar treatment has been denied to him as an unfair labour practice because of the father of the employee who is also an employee of the Bank and a member of the minority union, which is not in the good books of the management. The management has not contradicted the contents of any of the documents filed by the workman as annexures to the claim statement.

The workman examined Shri R. P. Sharma, Divisional Manager of the respondent Bank at Amritsar and he produced a prepared statement, Ext. A/1, based on original records. There are names of five candidates given in the said statement, and according to this witness, they were not eligible for appointment but were appointed. There was another group of four candidates, who qualified in the written test but failed in the interview, and the Personnel Manager again interviewed those candidates and declared them fit for appointment. The second interview shows either lack of confidence in the first Interview Committee or that the second interview was held in order to accommodate those four candidates, who were not selected by the Interview Committee. No doubt, it is a right of the management to recruit any one they like, but when they have formulated a recruitment policy and there are Awards binding on them and there is nothing on record against Shri Ram Paul, who had been employed as a temporary clerk, the latter was entitled to be considered for selection in a permanent vacancy in terms of para 12(2) of the Bipartite settlement unless other things were not equal. The only inequality alleged by the management is that he had failed in the written test by one mark, but there are others who have been absorbed in permanent vacancies, even when they failed for much more marks and were not eligible. I doubt, if in such circumstances any other inference is possible except that the candidate has been punished for the sins of his father who, though an employee of the Bank, is a member of the minority union. At any rate, the concerned workman was entitled as a temporary employee, to 14 days notice before his services were terminated and even that was not done.

The recruitment policy, Awards and the Bipartite Settlement are menat to be followed honestly and every action of the management of any industry, much more of the respondent bank, must inspire confidence amongst its employees and not given an impression of naked nepotism or arbitrariness. I am afraid that the action of the respondent Bank in terminating services of Shri Ram Paul does not seem to be bona-fide and, in my opinion, it is actuated by extraneous reasons. I must, therefore, hold that the termination of services of Shri Ram Paul was not justified. Be that as it may, I equally feel that he should not be reinstated from the date his services came to an end as a temporary hand. The only just course in the present circumstances appears to be to direct the respondent Bank to give Shri Ram Paul first vacancy of a Clerk in the same grade that arises in future whether temporary or permanent and for the past period the Bank should pay Rs. 2,000/- as compensation for the wrongful termination of his services.

9-1-1976

H. R. SODHI, Presiding Officer.

[F. No. L-12012(55)/74-LR III]

New Delhi, the 5th March, 1976

S.O. 1063.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th February, 1976.

BEFORE SHRI H. R. SODHI, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, PUNJAB (CENTRAL), CHANDIGARH

Reference No. 18/C of 1975

BETWEEN

the workmen and the management of State Bank of India, Jullundur Branch, Jullundur.

APPEARANCES :

Sarvshri J. N. Kapoor and R. L. Malhotra—for the workmen.

Shri A. Seshan—for the respondent bank.

AWARD

Sarvshri S. L. Batra, Clerk and R. K. Magon, Head Clerk, are employees of the State Bank of India and posted in its Jullundur Civil Lines branch. Shri Batra was initially employed as a clerk with the respondent bank at Jullundur in 1946. He was promoted as Head Clerk and ordered to be transferred to Pathankot, but he declined to accept promotion as per letter of 13th May, 1965, Ext. W/4 obviously because he did not want to leave Jullundur. The request of Shri Batra that he be not transferred was accepted and by letter dated 25th May, 1965, Ext. W/1, he was informed that not only his promotion as Head Clerk at Pathankot branch to which he was intended to be transferred on promotion stood cancelled but his case for appointment/promotion to higher clerical grades/Sub-Accountant's grade, whether permanent or in leave arrangement, would not be considered by the bank in future. Shri Batra, thus, continued as a clerk in Jullundur since his original appointment.

The history of service of the other workman Shri R. K. Magon is that he joined the bank in 1953 at its Hathras branch in U.P. and was transferred to Jullundur city branch

in 1954, as a clerk. He was transferred to Chandigarh somewhere in 1967 but again within a few months transferred back to Jullundur on his own request. He was promoted as Head Clerk in 1970 in the same branch at Jullundur. In the same year, he was called upon to appear in a test for the higher post of Sub-Accountant but he declined to take the test and accept any promotion as per letter dated 14-3-1970, Ext. W/4 since he thought that it would or might have entailed his transfer from Jullundur.

The plea of both the workmen was that their personal circumstances did not permit them to go out of Jullundur. It is not disputed that the record of service of both of them is good and that they could have risen high in service if they had not chosen to stick to Jullundur.

Somewhere in May, 1974, after Shri R. D. Kriplani, M.W. 1, Regional Manager, New Delhi, took over the present assignment, he passed transfer orders of the two workmen. Shri Magon was transferred to Ajnala whereas Shri Batra to Pathankot to which place the workman had been earlier transferred but the transfer was later cancelled. The impugned transfer orders were communicated to Shri P. N. Bidani, M.W. 2, Branch Manager, Jullundur, on telephone with a direction that the workmen be required to hand over charge at once. It is alleged that the workmen presumably having become aware of the transfer orders proceeded on sick leave to avoid being served with the said orders. For the purposes of this reference, it is, however, not necessary to positively decide whether they were really sick or not when they proceeded on leave after receipt of the transfer orders by Shri P. N. Bidani from the Regional Office, Delhi.

The workmen claim to be active members of a trade union and they raised a dispute with the Bank authorities about their transfer by serving a demand notice. Conciliation proceedings conducted by the Assistant Labour Commissioner (Central) failed to resolve the dispute amicably and the Central Government, being of an opinion that an industrial dispute existed between the employer and the workmen, acted in exercise of the powers conferred on it by section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act described hereinafter as the 'Act' and referred as per Notification No. L. 12012/149/74/LRIII, dated 15-4-1975, published in the Government of India Gazette, the following matter to this Tribunal for adjudication :—

> "Whether the action of the management of State Bank of India in transferring Sarvshri S. L. Batra, Clerk, and R. K. Magon, Head Clerk, from Jullundur Branch to Pathankot and Ajnala branches respectively is an act of victimisation ? If so, to what relief are the said workmen entitled ?"

Notices were issued to the parties, who filed their respective pleadings which led to the following issues :—

Preliminary issue :—

> "Whether the instant reference is bad in law and without jurisdiction for the reasons stated in paras 1 to 5 of the preliminary objections taken in the two written statements, wherein it is pleaded inter alia that the matter of transfer cannot be subject-matter of adjudication by this Tribunal, and that the management alone is the judge of the exigency or propriety of the transfer, more so, in view of the undertakings given by the employees which constitute conditions of their service ?"

On Merits :—

> "(1) Whether the impugned transfers of Sarvshri S. L. Batra and R. K. Magon from Jullundur to Pathankot and Ajnala branches respectively is an act of victimisation ?
>
> (2) If issue No. (1) is found in favour of the workmen and against the management, to what relief, if any, are they entitled ?

The authorised representative of the management did not lead any separate evidence to substantiate preliminary objections and it was agreed between the parties that all the issues be decided together. A number of documents were filed by both of them. The workmen examined Sarvshri J. N. Kapur, W.W. 1, Head Cleark, State Bank of India, New Delhi and General Secretary of the Delhi Circle State Bank Staff Association, J. P. Sharma, W.W. 4 Head Clerk, State Bank of India, Ambala Cantt, Jai Gopal Verma, W.W.5, Clerk, State Bank of India, Sector 17, Chandigarh, Shori Lal Mehandiratta, W.W. 6, Head Clerk, Respondent Bank, Chandigarh, Roshan Lal Malhotra, W.W. 7, Head Clerk, Respondent Bank Jullundur City Branch, Madan Lal, W.W. 8, Clerk, Respondent Bank, Jullundur. The concerned workmen, namely, Sarvshri S. L. Batra and R. K. Magon also went to the witness-box. The management produced two witnesses Sarvshri R. D. Kriplani, M.W. 1, who is Regional Manager, Region 4 of the Respondent Bank and P. N. Bidani, Branch Manager, Respondent Bank, Jullundur City under whom the concerned workmen were working at the relevant time.

I shall dispose of the preliminary objection first. There is no manner of doubt that an Industrial Tribunal should not normally interfere with the transfer orders passed by a management in the discharge of their managerial functions since it is the management which is the best judge of the exigencies of service and distribution of its employees amongst different branches. It is, however, an equally well-settled proposition that the management in effecting transfers of its employees must act bona fide in the interest of its work and be not led by extraneous considerations or act as a result of unfair labour practice so as to victimise its employees by transfers. The instant reference itself requires me to decide whether the Respondent Bank in effecting transfers of the two employees intended to victimise them. I am not oblivious to the requirement of law that a finding by the Tribunal in this regard must not be based on mere suspicious. I have, keeping in view the aforesaid guide-lines, assessed the evidence oral and documentary as produced before me and reluctantly come to the conclusion that the transfers were not effected bona fide in the exigencies of service and that there is some thing deeper than that in regard to which the management of the Respondent Bank has not taken the Tribunal into confidence. The preliminary issue, has, therefore, no merit and cannot be dealt with divorced from the issue on merits which I shall now decide.

The unrebutted statements of the workmen supported by other witnesses establish that till the year 1972, all the employees had formed a federation registered under the Trade Unions Act, of which the concerned workmen and also Sarvshri J. N. Kapur, W.W. 1, J. P. Sharma, W.W. 4, Jai Gopal, W.W. 5, Shori Lal Mehandiratta, W.W. 6, Roshan Lal Malhotra, W.W. 7 and Madan Lal, W.W. 8, were the members. This federation was bifurcated in the year 1972 when a new union under the name and style of Delhi Circle State Bank Staff Association described hereinafter as the 'Association' was formed and this union, too, was got registered under the Trade Unions Act. Shri Batra, W.W. 2 was an active member of the Federation before bifurcation and had been for some time a Secretary and then Chairman of Jullundur Branch. Shri R. K. Magon, the other concerned workman, was equally an active member of the Federation till 1972. Shri Batra is still the District Secretary of the Association at Jullundur whereas Shri Magon is Chairman of Jullundur unit of the Association. The evidence reveals beyond dispute that both the workmen have been throughout active trade unionists whether they were members of the Federation or they are now members of the Association. Both the workmen claim to be protected workmen and this assertion is not controverted by the management. A protected workman is given some special protections and rule 61 of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 requires every registered trade union to communicate to the employer before 30th April every year the names and addresses of such of the officers of the union, who in the opinion of latter, should be recognised as "protected workmen". The case of the concerned workmen is that they have been supplying such lists which included their names as protected workmen. Rule 61(2) enjoins upon the employer to recognize such workmen as protected workmen, whose names have been so supplied by the union but the recognition has to be conveyed to the union in regard to which there is no evidence in this case. It is urged that the workmen did their part in supplying the necessary information as contemplated in the said Rules.

Reference to protected workmen becomes necessary as in the matter of transfers they have been accorded special treatment in what is described as Shastri award, as well. It is in the statement of Shri R. D. Kriplani, M.W. 1 that in the matter of transfer policy, the bank generally follows the provisions of Desai and Shastri awards. We have also in his evidence that there are two unions of employees of the bank but it is only All India State Bank Staff Association (described as federation) which is recognized as representative of the workmen. He deposed that notice of transfer in terms of Shastri award was issued in the case of the two concerned workmen, though such notice was not necessary. He was not in a position to deny if the workmen represented against the transfers and when asked as to why reply to the representation was not sent, the answer of the witness is that such a reply could be necessary only if the workmen were President or General Secretary of the entire association but they were office bearers of a local unit. A very astounding fact to be discovered in the statement of the witness is that it is the policy of the bank not to reply to non-recognized union or to enter into negotiations with them, though he conceded that so far as Shastri award is concerned, the provisions thereof are being applied equally to the office-bearers of both the recognised and the non-recognized unions. Shri J. N. Kapur, W.W. 1, who is General Secretary of the Association and was formerly an active member of the federation, has deposed that the association is being discriminately treated and those employees, who are members of their union are being victimized by way of suspension, transfers and by being charge-sheeted on flimsy grounds. He, too, is under suspension. According to this witness the management witness Shri R. D. Kriplani, M.W. 1 stated as well that the head office has issued a circular letter to all branches that if the dispute is raised by the association, the management should not represent itself in conciliation proceedings nor the management should negotiate with the union or even talk to them when they make any demand. The witness further goes on to say that all promotions, transfers and even appointments are made on the recommendations of the recognized union. Special leave, as stated by this witness, is granted to the office-bearers of the recognised union for their trade union activities including appearance before the authorities constituted under the Industrial Disputes Act but no such concession is available to members of the association. Shri Kriplani, M.W. 1, obliquely lends support to the version of the witness M.W. 1 in this regard also. Shri Kriplani had been superintendent of Bombay Circle from 1969 to 1972 and it is stated by him that during that period the General Secretary of the recognized union was not doing any bank work. Instructions, as deposed by Shri Kriplani, have now been issued after the Emergency was declared that the office-bearers of the recognized union should also be allotted duties. In the statements of the witnesses for the workmen, it is further averred that the association has in some units their number more than the recognised union. It is an uncontroverted fact that deductions are made from the salaries of the employees towards subscription for membership of the recognized union and almost all the employees appearing against the management in this case have deposed that they are being forced to have deductions made from their salaries for membership fee of the recognized union, though they have formed a union of their own. The workmen even go to the extent of asserting in the course of their evidence that even members of the welfare committee are not allowed to be elected by the employees but they are virtually the nominees of the recognised union nor any other facilities or amenities made available to them. It may not be possible to accept on its face value all the grievances as made by the concerned workmen or their confederates who have appeared as witnesses, but the management has made no attempt to contradict their testimony in this regard. Shri Kriplani's statement, on the other hand, supports the broad proposition that unhappy discriminatory treament is undoubtedly being given to the association of which the two concerned workmen are members. I cannot visualise that if a dispute is properly raised and is an industrial one within the meaning of section 2(e) of the Act, the management in the absence of any legislation to that effect should refuse to participate in conciliation proceedings or even consider the demands howsoever reasonable. We have no legislation yet in this country whereby a right can be claimed by a management to consider the demands raised only by a union recognized by it and refuse to negotiate or talk to a non-recognized union no matter that the dispute is an industrial dispute and has been espoused by a substantial number of the workmen of the said industry.

In the back-ground of what has been stated above, I shall now examine the circumstances in which the instant transfers were made. The policy of the bank is that usually when in the exigencies of service a transfer becomes necessary, it is the junior-most who will be transferred unless the employees consent to a mutual transfer. Admittedly, the wives of these two workmen are partners in a Rubber Industry carried on in Industrial Area, Jullundur, under the name of M/s. Friends Rubber Industries. The other partners are Sarvshri R. K. Aggarwal, B.A., L.L.B. and Chaman Lal. It is in the statement of Shri Batra, concerned workman, W.W. 2, that his wife is educated and sufficiently qualified to carry on business and that as a matter of fact she operates on the accounts. This business is being carried on since 1960. M/s. Rubber Industries had accounts with Jullundur branch of the respondent bank and a cash credit limit had also been sanctioned by the head office but these accounts were closed by the firm some time in 1973. Shri Magon, the concerned workman, W.W 3, is, as stated above, working as head clerk. He passed first part of Indian Institute of Bankers' examination in the year 1960 and in 1970 when he was promoted as head clerk, he was asked to appear in a test for the post of Sub-Accountant as per letter dated 10-7-1970, Ext. W/5, but the workman declined the offer as he wanted to remain in Jullundur. It was stated by him that his circumstances did not allow him to leave Jullundur. Same is true of Shri Batra, W.W. 2. He, too, declined to go out of Jullundur on promotion and was informed by letter Ext. W/1 that since the workman had cancelled his transfer to other place on promotion, "his case for appointment/promotion to higher clerical grade including Sub-Accountant grade whether permanent or in leave arrangement will not be considered by the bank in future" It was, thus, at the cost of having lost all their future promotion that the workmen continued to serve in Jullundur. The record of service of both the workmen as it appears from the statements of the witnesses is unblemished. Shri Kriplani, M.W 1, states that there was no complaint "that the two workmen had ever allowed access to the papers of the bank or bank books by any stranger or by any one else" and there was no complaint that the workmen had violated the provisions regarding secrecy. The statement of Shri Kriplani is corroborated by Shri P. N. Bidani, M.W. 2, who is Branch Manager at Jullundur and under whom the workmen are directly working. Shri Bidani has, however, deposed that there were some verbal complaints off and on that their business secrets got leaked out. Shri Bidani does not remember the name of the persons, who made complaints nor of any employee against whom the complaints were insinuated. According to the witness, it was just a casual talk and he assured the complaints that he would take steps that secrecy was maintained. He does not tell us what steps he took. I am constrained to say that such a responsible officer has apparently introduced a version which is far from truth and it seems to have been so done only to support the transfers. It was his duty to have taken proper action and made an enquiry when such a serious matter came to his notice, but he admits that it was a default on his part. The belated attempt on his part in the course of a statement before this Tribunal to insinuate that might be that these workmen were concerned in the complaints, to say the least, is highly improper. There was an enquiry held somewhere in 1973 by Shri R. R. Chopra, Chief Vigilance Officer-cum-officer Incharge Circle of the respondent bank under orders of the Regional Manager. It appears that there were complaints against Shri Magon and Batra to the effect that the workmen took advantage of their position in the bank in relation to the business of their wives, that they had amassed huge wealth, that they did not attend to their seats properly and devoted most of their time in their business. It was also suggested that they used to come to bank late and sometime leave after lunch break. There were other allegations as well. The enquiry visited Jullundur, interrogated the workmen and held his own fact-finding enquiry. He came to the conclusion that the wives of these two employees were running their factory but no undue facilities were available to them. From the report Ext. M/9, there is no room left for doubt in my mind that the findings of the enquiry officer were in favour of the workmen and some of the allegations were indeed found to be completely baseless. It was found that they were coming to bank in time and left bank daily after finishing their work, though the enquiry officer recommended that Shri Batra did not have full day's work and that he should be given more of it but that is a matter for which the responsibility was of the Branch Manager than any misconduct on the part of the workmen. The enquiry officer

also found no fault with the D.Ds. purchase limit having been allowed to exceed which, in his opinion, was due to increase in the business of the Rubber Industry in which the wives of the employees were partners. In 1956, and also in 1973, a complaint was made that the Accountant of the branch allowed to be remitted at par some amounts but in the opinion of the enquiry officer, the practice to remit funds at par on behalf of bank's constituents is not uncommon especially when funds were to be invested in Bank's own fixed deposits.

A persual of the file Ext. W/19, relating to Conciliation proceedings before the Assistant Labour Commissioner (Central) Chandigarh, is a pointer to show that the transfers had been effected on the basis of some anonymous complaint which according to the version of the workmen had been got engineered and sent to the management by the rival union. The workmen asked the Conciliation Officer to get produced before him the same anonymous letters, their personal files and a statement showing the number of transfers during the previous two years in similar circumstances, that is, where the employees had refused promotions and they were still transferred. The management through their authorised representative, produced the anonymous letters supposed to have led to the transfers but those letters after persual were returned by the Conciliation Officer. In his statement before this Tribunal, the Regional Manager Shri Kriplani, was not prepared to admit that there were any such anonymous letters, and to my mind, it is a matter of regret. In the course of conciliation proceedings, the Regional Manager, M.W. 1 communicated to the Conciliation Officer that their authorised representatives had instructions not to participate in the proceedings but only to meet the Conciliation Officer separately and convey the point of view of the bank. At one time, the management refused to produce the documents asked for by the workmen but ultimately they were made available, though the anonymous letters were taken back. The stand of the management before the Conciliation Officer was that they were not bound to negotiate or talk to the union which they have not recognised and in this respect they relied upon the Code of Discipline. The terms of the alleged Code of Discipline are contained in a document placed on the file of the Conciliation Officer. The Code of Discipline does not help the management nor has any legal validity. In the statement of Roshan Lal Malhorta, W.W. 7, who is working as a head clerk in the same city branch at Jullundur since 1957/1978, we find the names of 32 employees, who are continuing at Jullundur, some even for more than 2/3 decades and some joined service at the same place and retired from there. The management had ample opportunity in the course of proceedings to contradict the averments of the workmen in regard to both these matters but it failed to do so. The management instead relied upon some journal captioned as "Trade Observer" Ext. M/1, wherein the photograph of Shri Magon appeared. It was urged that Shri Magon and the other workmen are openly participating in the functions of the business house obviously as main hosts. The workmen plead that when their wives are partners they attend with them all social functions and there was nothing wrong if they with the chief guest posed for a photograph. I feel that it canot be inferred that they are doing irregularities so far as their work in the bank is concerned or that their transfers become necessary. Undisputably the workmen are interested in the business with their wives but it is admitted by Shri Kriplani, M.W. 1, that there is no clear cut policy of the bank that an employee cannot be posted at a place where his near relations carry on business. The workmen filed a list, marked 'A', of 26 employees posted at Jullundur branch whose parents, brothers or other near relations are carrying on business in the same town but none of them has been transferred. On a consideration of the entire material, on the record and after giving my careful thought, I am satisfied that in the absence of any special circumstances or any finding by the bank authorities that the retention of the workmen at Jullundur is not in the interest of the bank, the transfers of these two employees mainly on a anonymous complaint when there are two rival unions at logger-head with each other, was not justified. There was no occasion to order the transfer when the business of Rubber Industry was being carried on by the wives of the employees since 1960 and the authorities were fully aware of it. The plea of the management before this Tribunal that the transfers were effected in the exigencies of service in the ordinary course cannot, therefore, be accepted as correct. There is no doubt in my mind that the concerned workmen are active leaders of the trade union which is not in the good books of the authorities and, in fact, they were amongst those actively responsible for bifurcation of the federation. The evidence of the workmen is to the effect that the newly formed association has gathered strength in numbers at several local stations and particularly at Jullundur, but I have no material except their statements to finally pronounce upon this factual position. Be that as it may, the transfers cannot be said to have been made bona fide and are beyond any shadow of doubt actuated by extraneous reasons.

In the result, the transfer orders cannot be sustained and must be quashed. The management is directed to let the workmen continue to work in Jullundur branch unless they wish to be transferred to some other place or there are some fresh circumstances which justify their transfer in the exigencies of service.

January 9, 1976.

H. R. SODHI, Presiding Officer,

[F. No. L-12012/149/74/LR III]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

154 GI 75—6

आदेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1976

का० आ० 1064.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोयला खान प्राधिकरण, लिमिटेड की उमरेर प्रायोजना, डाकघर उमरेर प्रायोजना, जिला नागपुर के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कोयला खान प्राधिकरण, लिमिटेड की उमरेर प्रायोजना, डाकघर उमरेर, प्रायोजना, जिला नागपुर, महाराष्ट्र के प्रबन्धतन्त्र की, इसके उपाबन्ध में उल्लिखित कर्मकारों को स्थाई नियोजन देने से इन्कार करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

उपाबन्ध

1. श्री जनार्दन पांडे,	एम० एम० का कार्यालय	
2. श्री नियाज अहमद अंसारी	—वही—	
3. श्री सुबोध कुमार	—एक्स—	कैट० सेक्शन
4. श्री बलणी सिंह	—वही—	
5. श्री राधा कृष्ण दुबे	—वही—	
6. श्री रामपत राम	—वही—	

7.	श्री केशव प्रसाद वर्मा	एक्स-कैव सैक्शन
8.	श्री एस० पी० सिंह	खनन
9.	श्री बादल दास	भंडार
10.	श्री बीरेन्द्र शर्मा	ई० एंड एम० अनुभाग
11.	श्री जोगा सिंह	—वही—
12.	श्री अरविन्द कुमार	डब्ल्यू० और डब्ल्यू० अनुभाग

[संख्या एल० 22012/16/75-डी० 3 बी०]

ORDER

New Delhi, the 23rd January, 1976

S.O. 1064.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Umrer Project of the Coal Mines Authority, Limited, Post Office Umrer Project, District Nagpur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Umrer Project of the Coal Mines Authority Limited, Post Office Umrer Project, District Nagpur, Maharashtra, in refusing permanent employment to the workmen mentioned in the annexure hereto, is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

ANNEXURE

1.	Shri Janardhan Pandey	SAMs office
2.	Shri Niyaz Ahmed Ansari	—do—
3.	Shri Subodh Kumar	Exev. Section
4.	Shri Bakshi Singh	—do—
5.	Shri Radha Krishan Dubey	—do—
6.	Shri Rampat Ram	—do—
7.	Shri Keshav Prassad Verma	—do—
8.	Shri S. P. Singh	Mining
9.	Shri Badal Das	Store
10.	Shri Birendra Sharma	E & M Section
11.	Shri Joga Singh	—do—
12.	Shri Arabinda Kumar	W & W Section

[No. L-22012/16/75-D. IIIB]

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1975

का० आ० 1065:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री पीर मोहम्मद पुत्र श्री इलामबक्स, खान स्वामी, गांव और डाकघर दाबी, जिला बंदू की, बून्दी जिला (राजस्थान) में लम्बाखों सेंड स्टोन माइन्स के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री पीर मोहम्मद पुत्र श्री इलामबक्श, खान स्वामी, गांव और डाकघर दाबी, जिला बून्दी की बून्दी जिला (राजस्थान) में लम्बाखों बलुआ पत्थर खानों में नियोजित श्रमिक किसी राष्ट्रीय और त्यौहारी अवकाश दिनों की मंजूरी के हकदार है यदि हां, तो किन अवकाश दिनांक के और किस वर्ष से

[सं० एल० 29011/131/75-डी० 3 (बी०)]

एस० एच० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 1975

S.O. 1065.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Lambakho Sand Stone Mines in the District of Bundi (Rajasthan) of Shri Pir Mohammad Son of Shri Ilam Bux, Mine owner, village and Post Dabi District Bundi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the workmen employed in Lambakho Sand Stone Mines in the District of Bundi (Rajasthan) of Shri Pir Mohammad Son of Shri Ilam Bux, Mine Owner, Village and Post Dabi, District Bundi are entitled for grant of any paid national and festival holidays? If so, to what holidays and from which year?

S. H. IYER, Section Officer (Spl.)
[No. L-29011/131/75-S. III(B)]

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का० आ० 1066:—केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 27 के अनुसरण में, 22 फरवरी, 1975 को जिला गिरिडीह, बिहार राज्य में मेसर्स कोलियरी के सामने कोयला खनन करते समय हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिये, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ०

2397, तारीख 11 जुलाई, 1975 द्वारा उक्त धारा के अधीन नियुक्त जांच न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपा-धारा (4) के अधीन उसे प्रस्तुत रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

22 फरवरी, 1975 को जिला गिरिडीह, बिहार राज्य में मेसर्स कोलियरी के सामने कोयला खनन करते समय हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों के बारे में जांच न्यायालय की रिपोर्ट।

दुर्घटना जो कि इस जांच का विचारार्थ विषय है, दामोदर नदी के उत्तरी किनारे पर 22-2-1975 को हुई। यह नदी के किनारे पर स्थित भारत कोयला खान प्राधिकरण लि० की माएल कोयला खान और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम* (इसके बाद सी० एम० ए० एल०/एन० सी० डी० सी० के नाम से निर्दिष्ट) के सम्मुख है। दुर्घटना स्थल ग्राम धावैया, थाना गोमिआ, जि० गिरिडीह, बिहार राज्य में है। माएल कोयला खान जिला हजारीबाग में आती है। इस स्थान पर दामोदर दोनों जिलों के बीच की सीमा निर्धारित करती है।

2. दुर्घटना कोयला दृश्यांश में हुई। इस प्रकार के दृश्यांश दामोदर और अन्य नदियों के साथ-साथ कई स्थानों पर और पास के स्थानों में भी उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र एन० सी० डी० सी० के तथा कथित रामगढ़ प्रोजेक्ट के भाग में आता है जिसमें चार खंड सम्मिलित हैं। इनकी संख्या खंड 1 से है। धावैया ग्राम खंड 2 में आता है जबकि माएल कोयला खान खंड 4 में है। क्षेत्र की भौगोलिक दशायें धीरे-धीरे दामोदर, जोकि कोयला-क्षेत्र के लिये मुख्य जल-निकास है, के साथ-साथ असमतल है। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय खान केन्द्र और एन० सी० डी० सी० द्वारा विस्तृत अन्वेषण किया गया है। खान-खुदाई के लिये कई कोयला सीइस का पता लगाया गया है, जिनमें मध्यम कोककर कोयला है जो कि धोने के पश्चात् धवन भट्टी में प्रयोग करने के लिये उपयुक्त है।

3. न्यायालय ने चार बैठकें कीं। पहली बैठक, जो कि 5-8-1975 को धनबाद में हुई, कार्य-पद्धति बनाने के लिये एक प्रारम्भिक बैठक थी। अगले दिन न्यायालय ने दुर्घटना के क्षेत्र का दौरा किया किन्तु नदी की स्थिति को देखते हुये घटना स्थल तक पहुंचने में असमर्थ रहा। दूसरी और तीसरी बैठकें रांची (16 से 18 सितम्बर), तथा धनबाद (24 अक्तूबर) में साक्ष्य रिकार्ड करने के लिये हुई। अन्त में, न्यायालय ने दुर्घटना स्थल का 13 नवम्बर को दौरा किया और अगले दिन धनबाद के पक्षों की ओर से तर्क सुने।

4. सरकारी नोटिस के प्रत्युत्तर में तीन पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुये और लिखित स्टेटमैन्टस दर्ज कराई तथा गवाहों से पूछ-ताछ की गई। ये (1) सी० एम० ए० एल०/एन० सी० डी० सी०, (2) जिला प्रशासन, गिरिडीह और (3) यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन, भूरकुंडा हैं। पहले पक्ष ने तीन गवाहों, दूसरे पक्ष ने पांच गवाहों और तीसरे पक्ष ने चार गवाहों से पूछ-ताछ की। इसके अतिरिक्त, न्यायालय द्वारा बुलाये गये तीन गवाहों से पूछ-ताछ की गई और खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से एक गवाह से पूछ-ताछ की गई। परीक्षित गवाहों और दर्ज किये गये दस्तावेजों की सूची क्रमशः इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 और 2 में दी गई है।

5. कोयला वाली भूमिका लगभग 15,000 एकड़ का क्षेत्र, जिसमें रामगढ़ प्रोजेक्ट के खंड 1-4 आते हैं केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना दिनांक 13-4-1961 द्वारा कोयला धारण क्षेत्र (अभिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4 के अधीन अधिसूचित किया गया। इसमें से केवल 2,510 एकड़ का एक क्षेत्र 22-12-1962 की धारा 7 के अधीन अधिसूचित किया गया और इसके लिये एक और अधिसूचना अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी की गई। इन अधिसूचनाओं के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने 1963 में 2,510 एकड़ के अभिगृहीत क्षेत्र का कब्जा प्राप्त किया इसके पश्चात्, केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र को अधिनियम की धारा 12 के अधीन जारी किये गये एक आदेश दिनांक 18-2-63 द्वारा एन० सी० डी० सी० को सुपुर्द कर दिया। यह क्षेत्र रामगढ़ प्रोजेक्ट का ब्लाक-1 है। परियोजनाओं के खंड 2 और 3 बनाने वाले क्षेत्रों, यद्यपि ऊपर निर्दिष्ट धारा 4 और धारा 9 के अधीन अधिसूचनाओं में सम्मिलित है, का कब्जा केन्द्रीय सरकार ने धारा 12 के अधीन केवल 30-5-1975 को (अर्थात् दुर्घटना के तीन महीनों से अधिक के पश्चात्) लिया। खंड 4 में क्षेत्र जिसमें नदी के दक्षिणी किनारे पर माएल कोयला खान सम्मिलित है, यद्यपि धारा-4 के अधीन अधिसूचना में सम्मिलित है, वास्तव में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक और अधिनियम, नामतः कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन अभिगृहीत किया गया था।

6. मैं यथासमय उपरिनिर्दिष्ट विभिन्न अधिसूचनाओं के कुछ कानूनी पहलुओं और प्रभावों की व्याख्या करूंगा। मैं सर्वप्रथम 22-2-1975 को उत्तरी किनारे पर हुई दुर्घटना तथा इसके शीघ्र पश्चात् घटनाओं के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगा। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, पहला रिकार्ड छक्षपुरग्राम के विदेशी दुशाद नाम के चौकीदार द्वारा गोमिया थाने में तारीख 23-2-1975 को दर्ज कराई रिपोर्ट के रूप में है। इसके अनुसार दुर्घटना 22 तारीख को 9 पूर्वाह्न पर हुई। इसके समानान्तर रिकार्ड एन० सी० डी० सी० के क्षेत्रीय महाप्रबन्धक (ए० जी० एम०) द्वारा 22 तारीख को रामगढ़, थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट है। ए० जी० एम० उसी अपराह्न को एन० सी० डी० सी० की माएल कोयला खान के दौरे पर थे और उन्होंने सामने के किनारे पर गैर-कानूनी तरीके से कोयला निकालने में छत के गिर जाने के कारण एक दुर्घटना के बारे में सुना। टेलीफोन खराब होने के कारण, ए० जी० एम० शीघ्र ही हजारीबाग गये और उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया और इनकी सलाह पर, रामगढ़ थाने के सब-इन्सपैक्टर के पास औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई (एन० सी० डी० सी० द्वारा दर्ज कराई गई लिखित स्टेटमेंट का अनुलग्नक 3)।

7. अगले दिन अर्थात् 23-2-1975 को, संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा, रांची और पुलिस सहित राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह ने 27-2-1975 को दौरा किया। बचाने/बाहर निकालने की कार्यवाहियां 23-2-1975 को आरम्भ की गई और 28 तारीख तक जारी रहीं जिसके दौरान विस्फोटन करना पड़ा। बहुत सा मलबा हटाया और घटनास्थल से दो शव एक 27 तारीख और एक 28 तारीख को बाहर निकाले गये। इस बीच 26 तारीख को, प्रवाह के विरुद्ध नदी के किनारे एक किलोमीटर दूरी पर रेत में दबे हुये महिलाओं के गले-सड़े तीन शव मिलने की रपोर्ट प्राप्त हुई। सभी पांच शवों को पुलिस ने ले लिया और इन्हें हजारीबाग में सरकारी अस्पताल में भेज दिया। शव परीक्षा (पोस्ट-मार्टम) के पश्चात्, इनका दाह-संस्कार कर दिया गया। इनका कोई दावेदार नहीं था और कोई भी शव शनाखत नहीं किया जा सका।

8. मुझे इस स्टेज पर इस क्षेत्र में गैर-कानूनी तरीके से कोयला निकालने के उद्यम और विकास के बारे में कुछ अवश्य करना चाहिये संभवतः यह ऐसे क्षेत्रों पर लागू होगा जहां इस व्यवसाय का सहसा उद्यम हुआ है। इस प्रकार का खनन (माइनिंग), अधिकतर कोयले के उद्गम (आउट-क्रापस), विशेषकर इस दृष्टांत में दामोदर जैसी नदियों के किनारों पर और अन्य क्षेत्रों में, जहां एक पतले अधिभार के नीचे

*जब जांच की जा रही थी, तब सी० एम० ए० एल० और एन० सी० डी० सी० को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक नया संगठन नामतः कोल इंडिया लि० में मिला दिया गया। तथापि, इस रिपोर्ट में, मैंने पहले के नाम रखने को प्राथमिकता दी है।

सीमायें पाई जाती हैं, सीमित प्रतीत होता है। हाल ही के वर्षों में, और विशेषकर, 1973 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इस व्यवसाय के उद्यागम के लिये कई अवयव उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयला-खान करने के लिये गैरसरकारी पार्टियों द्वारा संभाव्य असमर्थता से जहां संभव हो सका कोयले का चोरी-छुपे खनन हुआ, यह विशेषकर ऐसे दुर्गम स्थानों पर था, जहां गैर-कानूनी खनन का आसानी से पता लगाना कठिन था और जब पता लगा लिया जाये तो इसे आसानी से रोका नहीं जा सकता। उदाहरण स्वरूप, इस विशिष्ट मामले में, धावैया ग्राम तक सभी प्रयोजनों के लिये, दामोदर की उत्तरी ओर से पहुंचना कठिन है। यहां केवल दक्षिणी किनारे से पहुंचा जा सकता है, किन्तु वर्ष के केवल ऐसे दिनों में जब परिस्थितियां माएल कोयला खान के पास से नदी को पार करना संभव बना देती हैं। जैसा कि हमने स्थान तक पहुंचने की यात्रा के दौरान महसूस किया, भूखंड की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये, माएल कोयला खान तक पहुंचने का मार्ग भी कठिन है।

9. एक और अवयव, जिसने व्यवसाय की वृद्धि में अवश्य योगदान दिया, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि था। कोयला खान वस्तुतः राज्य एकाधिपत्य हो जाने के कारण, कामगार जो राज्य कोयला खानों में रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, लाइसेंस न रखने वाले स्थानों में खनन के लिये बड़े आराम से परावर्तित हो गये। सिद्धान्त विरुद्ध और कानून तोड़ने वाले तत्व निस्सन्देह स्थिति का लाभ उठाने में तेज थे। जहां भी संभव हुआ, इन्होंने सरल खनन का रास्ता अपनाया— खान का अर्थ है कि इसमें बहुत ही थोड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है किन्तु यह राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही अपव्ययपूर्ण तथा संकटपूर्ण भी होता है। बेरोजगारी का सामना करने से, श्रमिकों को थोड़ा वेतन देने के बावजूद इस प्रकार गैर-कानूनी व्यवसाय में भाग लेने के लिये तैयार किया गया। मेरे पास कई गवाह उपस्थित हुये और इन्होंने दामोदर तथा इसकी सहायक बैरा के किनारों के साथ-साथ हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में बहुत से स्थानों पर फैले हुये गैर-कानूनी खनन को प्रमाणित किया। इन्होंने बताया कि सैकड़ों श्रमिक भाग ले रहे हैं, संख्या में अतिशयोक्ति हो सकती है किन्तु इसमें कोई शक नहीं है कि व्यवसाय बहुत से स्थानों में फैल गया है। कोयला खनन सम्बन्धी विभिन्न कानूनों के अधीन अपेक्षित खान खुलाई लाइसेंस या खनन लीज या अन्य प्राधिकार या अनुमति प्राप्त करने के बिना लोगों ने अपने आपको कोयला-उद्यागमों के मालिक बना दिया और इन स्थानों में आसपास के गांवों से बेरोजगार श्रमिक काम करने लगे। मुझे पेश किये गये साक्ष्यों से प्रतीत होगा कि श्रमिक कोयले, जोकि वे काटते और बाहर निकालते हैं, की प्रत्येक बाल्टी के लिये 2 आने से 4 आने तक की रायल्टी देते हैं। वे इस कोयले को बेचने के लिये पास के स्थानों में भेज देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीयकृत खानों में कोयले के मूल्यों में तीव्र वृद्धि ने इस कोयले के लिये बाजार ढूंढना संभव बना दिया होगा क्योंकि यह कोयला बहुत कम मूल्यों पर बेचा जाता था।

10. मेरे पास सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में कोयले का बिना लाइसेंस का खनन राष्ट्रीयकरण के शीघ्र पश्चात् आरम्भ हुआ। एन० सी० डी० सी० के० अधिकारियों द्वारा नवम्बर, 1973 तक के कई पत्र हैं जिनमें ऐसे मामलों को उद्धृत किया गया है। ऐसे कोयले को अनाधिकृत रूप से ले जाने के भी हवाले दिये गये हैं। ये पत्र हजारीबाग और गिरिडीह के जिला प्राधिकारियों को और रामगढ़, गोमिया और अन्य स्थानों के थानों के प्रभारी अधिकारियों को संबोधित थे। यह महत्वपूर्ण है कि 10 नवम्बर, 1973 को लिखे गये पत्र में, एन० सी० डी० सी० के माएल कोयला खान के प्रबन्धक, ने जिला खनन अधिकारी, हजारीबाग को सूचित किया कि माएल कोयला खान के सामने नदी-तल खदान में कोयला निकालने के लिये कार्य किया जा रहा है। पत्र में यह उल्लेख है "ओवर-हैंगिंग के कारण ये स्थान बहुत ही खतरनाक बन चुके हैं और दुर्घटना की किसी समय भी आशंका है," तथा इसे ऐसे व्यवसाय को समाप्त करने के लिये समय पर निवारक कार्यवाही हेतु अनुरोध के साथ समाप्त किया गया है। 24 मार्च, 1974 को माएल कोयला खान के प्रबन्धक ने क्षेत्र में गैर-कानूनी रूप से कोयला ले जाने के बारे में रामगढ़ थाने के प्रभारी अधिकारी को लिखा। 18 अप्रल, 1974 को इन्होंने दक्षिणी किनारे पर माएल कोयला खान के सामने और दामोदर के उत्तरी किनारे पर मौजा धावैया में गैर-कानूनी रूप से कोयला निकालने के बारे में जिला खनन अधिकारी, हजारीबाग को फिर लिखा। माएल कोयला खान और सिरका कोयला खान के अधिकारियों द्वारा लिखे गये कई अन्य पत्रों में और क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, एन० सी० डी० सी० तथा उपक्षेत्रीय प्रबन्धक सिरका ग्रुप द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग को संबोधित पत्रों में अनधिकृत खनन और कोयले के परिवहन का उल्लेख है।

11. जिला खनन अधिकारी, गिरिडीह द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य ने क्षेत्र में चल रहे गैर-कानूनी खनन व्यवसाय की अधिकतर पुष्टि की है। इनके अनुसार, इनको प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों के बारे में पुलिस प्राधिकारियों तथा इनके द्वारा शीघ्र छानबीन की गई और फौजदारी अभियोजन चलाये गये, जिनमें से इन्होंने दो उदाहरण दिये हैं। इस प्रकार हमें स्थितियों और परिस्थितियों की भूमिका के बारे में कुछ मालूम होता है जिसमें नदी के किनारे पर एक कोयला उद्यागम में 22 फरवरी, 1975 को धावैया ग्राम में एक दुर्घटना हुई।

12. इस व्यवसाय की जानकारी से जिला प्राधिकारियों और एन० सी० डी० सी० के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही करनी पड़ी। हमारे पास यह दिखाने के लिये साक्ष्य है कि खनन और व्यवसाय बनाये रखने के प्रशासन से संबंधित जिला अधिकारियों ने व्यवसाय को रोकने के लिये प्रयत्न किये हैं। हजारीबाग प्रभाग के आयुक्त ने कम से कम दो महत्व-पूर्ण बैठकें, एक 26 जून, 1974 और दूसरी 24 दिसम्बर, 1974 को कीं। इन बैठकों में कई उपचारी और रोकथाम की कार्यवाही के बारे में विचार विमर्श किया गया। कोयले को बाहर ले जाने पर रोकथाम लगाने के लिये क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर चैकपोस्टों की स्थापना सम्बन्धी कार्यवाहियों पर भी विचार किया गया। अवैध खनन अर्थात् विभिन्न कानूनों के अधीन अपेक्षित किसी खनन लीज या अन्य अनुमति प्राप्त किये बिना खनन को समाप्त करने के लिये शासकीय और पुलिस प्राधि-कारियों तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों एवं जिला खनन अधिकारियों के नेतृत्व में आकस्मिक छापे मारने के लिये सिफारिश की गई थी। इस धमकी का सामना करने के लिये दीर्घकालिक उपाय करने हेतु फौजदारी अभियोजन दायर करके और विभिन्न प्रशासनिक उपायों को लागू करके कोयला खनन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों को दृढ़ता से लागू करने के लिये सुझाव दिये गये। जिला खनन अधिकारी गिरिडीह के सम्बन्ध में यह कहना है कि कई मामलों में पुलिस तथा इनके द्वारा की गई कार्यवाही प्रभावशाली साबित हुई और इस व्यवसाय को समाप्त कर दिया गया।

13. दुर्घटना के लिए सी० एम० ए० एल०/एन० सी० डी० सी० की जिम्मेदारी और दायित्व के बारे में मेरे पास बहुत से तर्क हैं। इसको पूर्णरूप से स्वीकार करते हुए मैं सर्व प्रथम कोयला क्षेत्र (अभिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 से सम्बन्धित उपबन्धों का हवाला दूंगा जिनका उल्लेख मैंने पहले ही उपर्युक्त पैरा-5 में किया है। अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेख है कि अधिनियम का उद्देश्य "भारत के आर्थिक हितों में कोयला खनन उद्योग पर अधिकतर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना

है और ऐसी जमीन जिस में कोयला है या जिसमें कोयला हो जाने की और जिससे अभी कोयला नही निकाला गया है, पर राज्य द्वारा अभिग्रहण करा कर अथवा करारनामा, लीज, लाइसेन्स या अन्य तरीके से प्राप्त ऐसे अधिकारों में संशोधन करके और इन्हें समाप्त करके ऐसी भूमि पर अधिकार देकर इनका विकास करना है ।" अधिनियम की धारा 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि में कोयला की खान खोदने के अपने इरादे का नोटिस दे सकती है जहां कोयला मिलने की संभावना है । खुदाई के पश्चात्, यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट है कि कोयला उपलब्ध हो सकता है तो यह धारा 7 के अधीन अधिसूचना द्वारा भूमि का भाग या सारी भूमि को अधिगृहीत करने के अपने इरादे का नोटिस दे सकती है । धारा 8 के अधीन आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार, धारा 9 के अधीन अभिग्रहण की घोषणा जारी कर सकती है । ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर, भूमि, धारा-10 के अधीन, पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन आ जाएगी । धारा 11 के अधीन, केन्द्रीय सरकार निर्देश दे सकती है कि भूमि, धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहने के स्थान पर, सरकारी कम्पनी के अधीन रहेंगी । और अन्त में, धारा 12 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किसी भूमि का कब्जा लेने के लिए किसी व्यक्ति से भूमि का कब्जा लेने या समर्पण करवाने की आवश्यकता पड़े, और यदि वह व्यक्ति इन्कार करता है तो सक्षम प्राधिकारी कार्यवाही आरंभ करे और भूमि का कब्जा ग्रहण करे तथा इस उद्देश्य के लिए उतने बल, जितना कि आवश्यक हो, का भी प्रयोग करे।

14. अब सी० एम० ए० एल०/एन० सी० डी० सी० का मामला यह है । स्वीकृत रूप से 2,510 एकड़ भूमि का क्षेत्र, जो कि ब्लाक-1 में आता है, और जिसे धारा 4 के अधीन पहले अधिसूचित किया गया था, 29-12-1962 को धारा 9 के अधीन अभिग्रहीत किया गया था, 1963 के आरंभ में केन्द्रीय सरकार ने इसका कब्जा लिया था, 18-12-1963 को, धारा 11 के अधीन एक आदेश द्वारा, यह क्षेत्र एन० सी० डी० सी० के अधिकार में कर दिया गया तथापि, जहां तक ब्लाक-2 और 3 का संबंध है, इन क्षेत्रों का कब्जा केन्द्रीय सरकार द्वारा एन० सी० डी० सी० को नहीं दिया गया । जैसा कि उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लेख है, केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों का कब्जा केवल 30-5-1975 को लिया था और यह कब्जा धारा 11 के अधीन आदेश द्वारा एन० सी० डी० सी० के अधिकार में अभी भी नहीं दिया गया । अतः, एन० सी० डी० सी० का ब्लाक-2 और 3 से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था, और क्योंकि जिला गिरिडिह का ग्राम धाबैया ब्लाक-2 में आता है, यह किसी भी प्रकार से तर्क नहीं दिया जा सकता कि एन० सी० डी० सी० का उस स्थान, जहाँ दुर्घटना हुई है, पर चाहे वस्तुतः या विधितः, किसी प्रकार का अधिकार या दायित्व था । इस मामले में एन० सी० डी० सी० को, इनके अनुसार, केवल रुचि दुर्घटना के स्थल के पड़ोस में होने में है । दुर्घटना की जानकारी रखने और इसकी जिला प्राधिकारियों की रिपोर्ट करने तथा, बाद में बचाव कार्यवाही करने में अपनी क्षमतानुसार सहायता प्रदान करने वाले प्रथम अभिकरणों में से यह एक अभिकरण है ।

15. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की ओर से आगे दृढ़तापूर्वक यह कहा गया कि उत्तरदायी संगठन होने के कारण, जो क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने से संबद्ध है, उन्होंने अपनी पट्टेदारी से बाहर क्षेत्रों में प्रचलित अवैध खनन के बारे में विभिन्न प्राधिकरणों को सूचित किया है और ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए हैं, या कदम उठाने में सहायता दी है ।

16. बिहार सरकार का वाद, जैसा कि गिरिडिह के जिला अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, है कि दुर्घटना का स्थान बिल्कुल अभिग्रहीत (केन्द्रीय सरकार द्वारा) क्षेत्र में पड़ता है और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्राधिकारियों ने इस प्रकार के खनन को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए और, बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के अवैध खनन के बारे में, विशेष रूप से धाबैया गांव में, गिरिडिह के जिला अधिकारियों को कभी भी कोई सूचना नहीं दी या भेजी गई हालांकि यह ज्ञात था कि दामोदर नदी के उत्तर में पड़ने वाला क्षेत्र गिरिडिह जिले में आता है । गिरिडिह जिले में संबराबेरा और कान्देर (गिधानिया) में कुछ अवैध खनन के बारे में सूचना गिरिडिह के जिला प्राधिकारियों को प्राप्त हुई थी और इस प्रकार की सभी खनन सक्रियाओं को तत्काल, दृढ़ता से और प्रभावी रूप से मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा नियंत्रित किया गया और रोका गया । स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्घटना के स्थान से कोयला निकालना आरंभ किया था, यह भाएस कोलियरी में काम करने वाले रा० को० वि० नि० के अधिकारियों, स्टाफ, सुरक्षा गार्डों को ज्ञात था परन्तु रा० को० वि० नि० ने अपने आप उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, न ही, उन्होंने अभिग्रहीत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार के अवैध खनन के बारे में स्थानीय प्राधिकरियों और पुलिस को सूचित किया, जिसके कारण अच्छी तरह उन्हें मालूम होंगे । "उन्होंने अभिग्रहीत क्षेत्रों में स्वयं अपनी खनन संक्रियाओं को भी चालू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की ।" अभिग्रहीत क्षेत्र में, दुर्घटना स्थल सहित, अपनी खनन संक्रियाओं को चालू कर के वर्तमान दुर्घटना से संबंधित सभी अवैध खनन, संक्रियाओं को स्वतः नियंत्रित और प्रभावी रूप से रोका जा सकता था ।

17. इस प्रकार, बिहार सरकार के अनुसार, (1) घटना स्थल रा० को० वि० नि० द्वारा अभिग्रहीत क्षेत्र में पड़ता था ; (2) हालांकि रा० को० वि० नि० का स्टाफ और प्राधिकारी उस स्थान पर अवैध खनन के बारे में जानते थे, उन्होंने इसे गिरिडिह के जिला प्राधिकारियों को सूचित नहीं किया, न ही उन्होंने स्वयं इस प्रकार के खनन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की, और (3) दुर्घटना से बचा जा सकता था । यदि रा० को० वि० नि० ने अभिग्रहीत क्षेत्र में स्वयं अपनी खनन संक्रियाएं चालू कर दी होती ।

18. संभवतः इन कथनों की कोई खास जांच नहीं की गई । प्रथमतः हालांकि धारा 9 के अन्तर्गत ब्लाक–2 (जिसमें धाबैया गांव सम्मिलित है) को अभिग्रहीत करने वाली अधिसूचना 2–12–1966 को जारी की गई थी, केन्द्रीय सरकार ने मई, 1975 तक इन जमीनों का कब्जा अभिग्रहीत नहीं किया था । मैं इस समय उस भेद की बात करूंगा जिसे धारा 10 के अन्तर्गत अभिग्रहण और धारा 12 के अन्तर्गत कब्जा लेने के बीच निकालने की चेष्टा की गई है, परन्तु और आगे जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि किसी भी समय ये जमीनें रा० को० वि० नि० के अधीन धारा 11 के अन्तर्गत हवाले नहीं की गई थीं । इस प्रकार, किसी भी तरह इस बात पर जोर नहीं दिया जा सकता कि धाबैया गांव में वह स्थान रा० को० वि० नि० द्वारा अभिग्रहीत क्षेत्र में पड़ता है । 1966 में बिहार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई समझौता संबंधी एक याचिका (जिसमें रा० को० वि० नि० और केन्द्रीय सरकार पक्षकार थे) और रा० को० वि० नि० द्वारा जिला प्राधिकारियों को यह दिखाने के लिए लिखे गए पत्रों, कि रा० को० वि० नि० के कब्जे में धाबैया की जमीनें दुर्घटना से काफी पहले थीं ; का आश्रय लेने की कोशिश की गई है । मेरे विचार में इस प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । किसी भी तरह रा० को० वि० नि० पर उत्तरदायित्व या देयता नहीं आती ।

19. इसी प्रकार रा० को० वि० नि० के खिलाफ बताए गए दूसरे प्वाइंट को सिद्ध करना कठिन है । जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, रा० को० वि० नि० ने, रा० को० वि० नि० के क्षेत्र के समीप में चल रहे अवैध खनन के संबंध में प्राधिकारियों को अवगत कराने के कई प्रयास किए । वास्तव में, रा० को० वि० निगम की माएल कोलियरी के प्रबन्धक द्वारा गिरिडिह के जिला प्राधिकारियों को लिखे गए कम से कम दो पत्रों में माएल कोलियरी के सासने के स्थान का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह बात खास महत्वपूर्ण नहीं कि एक पत्र, दिनांक 10 नवम्बर, 1973 गिरिडिह के बजाए हजारी-बाग के जिला खनन अधिकारी को संबोधित था । गिरिडिह का खनन जिला केवल नवम्बर, 1972 में सृजित किया गया था, और उस तारीख तक धावैया का क्षेत्र हजारीबाग के जिला खनन अधिकारी के क्षेत्राधिकार में पड़ता था ; यह भी साक्ष्य में है कि नये जिले का कार्यालय लगभग 1973 के अन्त तक हजारीबाग में ही स्थित रहा । सामान्यतः और उचित रूप से यह आशा की जाती है कि हजारीबाग के अधिकारी को लिखा गया पत्र, नये रूप से सृजित गिरिडिह के खनन जिले के प्रभारी अधिकारी को भेज दिया गया होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस प्रकार का पत्र नवम्बर, 1973 में माएल कोलियरी के प्रबन्धक द्वारा लिखा गया था । इस प्वाइंट के संबंध में कि रा० को० वि० नि० ने अवैध खनन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, यह पूछा जाए कि क्या उनको ऐसा करने का कोई हक, या कर्त्तव्य या शक्ति थी, क्योंकि यह क्षेत्र उनकी पट्टेदारी के बाहर था । उत्तरदायी सरकारी कम्पनी होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे अधिकारियों को यह सूचित करें कि माएल कोलियरी के सामने दूसरे किनारे पर क्या हो रहा है, और उन्होंने ऐसा किया था । यह कहा जा सकता है कि वह इस मामले की और प्रबलता से पैरवी कर सकते थे, क्योंकि उनको यह अच्छी तरह पता था कि यह जमीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिग्रहीत की गई है और एक सरकारी कम्पनी होने के नाते (जिस में कभी न कभी जमीन के निहित होने की अधिक संभावना है) उनका यह कर्त्तव्य था कि सरकारी हितों की सुरक्षा करें ।

20. रा०को०वि०नि० के खिलाफ उठाए गए तीसरे प्वाईण्ट में वास्तविकता की कमी है। यह कहना प्रत्यक्षतया अयाथार्थिक होगा कि रा० को०वि०नि० को उसके द्वारा अभिग्रहीत किए गए सभी क्षेत्रों पर तत्काल खनन क्रियाएं आरम्भ करनी चाहिएं। खनन कार्य, जैसे कि रा०को०वि०नि० की तरह के संगठन द्वारा अनुसरण किया जा रहा है, में पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के रूप में काफी योजना बनाई जाती है। परियोजना के संगठन के व्यापक खनन संक्रियाओं में सुसम्बद्ध किया जाना होता है तथा इसे सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय सरकार के कोयले के उत्पादन और वितरण की योजना के भी अनुरूप होना चाहिए। धावैया गांव में घटनास्थल के अतिरिक्त कई अन्य ऐसे स्थान होंगे जिन कोयला निकालने के कार्य को हाथ में लिए जाने की आवश्यकता होगी, परन्तु अनिवार्यतया अग्रता की एक शृंखला होगी, आयोजित खनन की आवश्यकता और स्रोतों और प्रशिक्षित जन-शक्ति की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अभिग्रहीत क्षेत्रों में एक साथ खनन कार्य आरम्भ करना असंभव होगा।

21. रा०को०वि०नि० और बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए वादों से उत्पन्न होने वाले एक रोचक और महत्वपूर्ण प्वाइण्ट को मैं पहले निपटाना चाहूंगा। अधिनियम की धारा 10(1) निर्धारित करती है कि धारा 9 के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन से, जमीन सभी प्रतिबन्धों से मुक्त बिलकुल केन्द्रीय सरकार में निहित होगी। धारा 12 में इस प्रकार से अभिग्रहीत की गई जमीन का कब्जा लेने की व्यवस्था है। धारा 10(1) के अन्तर्गत अभिग्रहण और धारा 12 के अन्तर्गत कब्जा लेने के बीच के अन्तराल के दौरान जमीन पर अधिकार के सम्बन्ध में स्थिति क्या होगी? अन्तराल के लम्बे होने की स्थिति में इस प्रश्न का महत्वपूर्ण व्यावहारिक महत्व है, जैसा कि इस मामले में अन्तराल कई वर्षों का है। इस अवधि के दौरान, अभिग्रहीत क्षेत्र को गैर-लाइसेंस और अवैध खनन से मुक्त रखने का उत्तरदायित्व किसका होगा? निःसन्देह, मौलिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार के कानून प्रवर्तन संबंधी एजेंसी का है, परन्तु प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? स्पष्टतः, यह राज्य सरकार का नहीं है, क्योंकि इसके अधिकार केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिग्रहीत किए गए हैं। इस मामले में, यह दायित्व रा०को०वि०नि० का नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 11(1) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह किसी अन्य व्यक्ति का भी नहीं, जिसको राज्य सरकार द्वारा खनन का पट्टा स्वीकृत किया गया होगा, क्योंकि धारा 10(2) के अन्तर्गत इस प्रकार का खनन स्वतः रद्द हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास केवल केन्द्रीय सरकार रह जाती है, और मेरे विचार में, धाराओं 10(1) और 12 को इकट्ठे पढ़ कर उनको दिए जाने वाले भावार्थों के बावजूद उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर आता है। वास्तव में, अगर ऐसे पठन को तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो यह वैधानिक शून्यता उत्पन्न कर सकता है, ऐसी स्थिति जिसमें अभिग्रहीत क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने की दृष्टि से उस पर चौकस निगाह रखने का किसी का दायित्व नहीं रह जाता। आदर्श रूप से, धारा 9 के अन्तर्गत घोषणा के साथ-साथ कब्जा लिया जाए या उसके तुरन्त बाद; इसी प्रकार धारा 11(1) के अन्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी को जमीन के अधिकार अन्तरित करने में समयान्तर नहीं होना चाहिए, यदि किसी विशेष मामले में केन्द्रीय सरकार का वास्तव में यही इरादा है। यदि ये अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकतीं, तो अधिनियम में संबंधित धाराओं का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और उनको आवश्यक सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए और मैं यह सुझाव केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाऊंगा। मेरे विचार में, धावैया गांव में अभिग्रहीत जमीन के टुकड़े पर अधिकारों और उस पर अवैध खनन को रोकने के लिए उत्तरदायी पक्ष या एजेंसी के सम्बन्ध में किन्तु अस्पष्ट स्थिति उस क्षेत्र में अवैध खनन को फैलाने के लिए अंशतः उत्तरदायी रही है।

22. हमने माएल कोलियरी के नजदीक दामोदर नदी को दक्षिणी किनारे से पार करके दुर्घटना स्थल का 13-11-75 को निरीक्षण किया। यहां पर रामगढ़ ब्लाक की 7 टाप सीम नदी के उत्तरी किनारे पर लगभग 150 मीटर दूरी तक अनाच्छादित है। उत्तर दिशा की ओर यह सीम डिपिंग लगभग 9 मी० मोटी है और यह सामान्य टाप माएल कैपिंग सहित 4-5 मी० की मोटाई के रेतीले पत्थर से आच्छादित है। रेतीले पत्थर अंशतः विदीर्ण, गठीले और बड़े माप के खंडों में टूटे पड़े हैं (कुछ 6 मी० × 2 मी० × 1.5 मी० तक के माप तक) जो किनारे के ऊपर कुछ स्थानों पर प्रलम्बी स्थिति पर है। किनारे का उपरी भाग जिसमें कोयले की सीमा का ऊपरी भाग और रेतीले पत्थर की कैपिंग सम्मिलित है, लगभग समतल है। निचले भाग में कोल सीमा के शेष भाग और रेतीले पत्थर का गिरा हुआ मलबा सम्मिलित है जिनमें विभिन्न मापों के भारी टुकड़े हैं जो नीचे जलस्तर की ढलान की ओर जा रहे हैं। मलबे में नदी द्वारा वृद्धि की गई रेत के भाग भी सम्मिलित हैं। किनारे पर कोयले की सीम किस सीमा तक अनाच्छादित है, यह नदी में पानी के स्तर और किस ऊंचाई तक मलबे ने सीम को ढका है; इस बात पर निर्भर करता है।

23. हम ने घटनास्थल को रेतीले पत्थर के खंडों और नदी के बालू की कुछ मात्रा से लगभग पूर्णतया ढका पाया। 7 टाप सीम से खोदा गया कुछ कोयला घटनास्थल पर पाया गया था; ऐसा लगता है कि यह हाल की मानसून के बाढ़ के पानी कम होने के बाद खोदा गया होगा।

24. न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य से यह प्रतीत होगा कि जो कोयला दुर्घटना एक सुरंग जो कोशने के उद्गम लगभग 6 मी० ढकेली गई थी, के प्रवेश पर अधिभार के गिराव से हुई। दोनों के बीच अन्तः सम्बन्ध सहित एक संलग्न सुरंग थी, रिब पिलर अत्यन्त तंग लगता था।

25. बचाव कार्मिकों, जो शवों के पाए जाने के बाद सुरंगों में घुसे, ने बताया है कि सुरंग और अन्तः संबंध पर छत का कोई गिराव नहीं हुआ; गिराव प्रवेश पर हुआ था। घटना स्थल से प्राप्त दो शव सुरंग के प्रवेश द्वारा के बाहर लगभग आधे मीटर पर गिरे हुए मलबे के नीचे दबे हुए पाए गए बताए गए थे।

26. जब हमने सुरंग का मुआयना किया तो सुरंग के प्रवेश के ऊपरी भाग पर केवल लगभग 150—200 मी०मी० × 1.5 मी० चौड़ा भाग खुला था। शेष भाग कोयले और रेतीले पत्थर के खण्डों के मलबे से ढका था। प्रवेश पर सुरंग की छत अक्षत थी।

27. यह प्रतीत होगा कि जिन दो व्यक्तियों के शव पाए गए थे, वे शायद प्रवेश के निकट कोयला काटने में रत थे और गिरते हुए पत्थर के नीचे दब गए थे। सुरक्षित खनन पद्धति में यह अपेक्षित है कि किनारे ढलवें और पैड़ी वार होने चाहिएं ताकि अधिभार के गिराव को रोका जा सके; यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह पूर्वोपाय यहां कभी भी नहीं किया गया। रेतीले पत्थर के बड़े उपस्थित अलग्न खण्डों सहित किनारे के समतल पार्श्व के कारण अवश्य ही अधिभार का गिराव हुआ होगा जिससे श्रमिकों की मौत हुई जो इसके नीचे सीधे कुचले गए और पीसे गए।

28. दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की जानें गईं? खबरें थीं कि 40 व्यक्ति मारे गए थे परन्तु ये अनुमान बहुत ही बढ़े-चढ़े हैं। मेरे समक्ष केवल मात्र विश्वसनीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि 27 और 28 फरवरी को की गई बचाव संक्रियाओं में दुर्घटना स्थल पर दो शव प्राप्त हुए थे और यह कि उनके अतिरिक्त, घटनास्थल के लगभग एक किलोमीटर प्रतिस्रोत पर रेत में दबे तीन महिलाओं के शव भी उसी समय पाए गए थे। ये पांचों शव पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिए और गोमिआ स्टेशन के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर के अनुसार ये शव पहचाने नहीं जा सके और कोई दावेदार भी नहीं थे।

29. कुछ गवाहों ने बताया कि घटनास्थल से चार शव पाए गए थे। मैं कहना चाहूंगा कि बचाव कार्य केवल 23 को आरम्भ किए गए। इस समय यह कहना कठिन है कि क्या इस तारीख से पहले, अर्थात् 22 को ही ग्रामवासियों ने घटना स्थल पर शवों को ढूंढा और कोई शव पाए, शायद सिवाए प्रतिस्रोत पर रेत में पाए गए तीन शवों के और दो अन्यों के जो चितरपुर ले जाए गए बताए जाते हैं। चूंकि सारी संक्रियाएं अवैध थीं, इसलिए ग्रामवासी जो कुछ कहते हैं उसमें उनका अस्पष्ट होना तथा उसमें अरुचि रखना समझने की बात है। यूनाइटिड कोल वर्कर्स यूनियन द्वार प्रस्तुत किए गए एक गवाह ने, और जो समीप के होनेह गांव का था, बताया कि उसके गांव की तीन महिलाएं, जिनके उसने नाम बताए (सुमित्रा कुमारी, गज्जु करमाली की पुत्री, प्राण कुमारी देवी, रती करमाली की स्त्री और पातो कुमारी, गपुर महतो की पुत्री), दुर्घटना में मर गईं, हालांकि उसने आगे बताया कि तीन शव पुनर्गृहीत नहीं हुई और उपलब्ध नहीं हो सके; संभवतः संदर्भ दुर्घटनास्थल के प्रतिस्रोत पर रेत के नीचे दबे तीन शवों की ओर है। धावैया गांव के मुखिया ने दो व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में बयान दिया, जिनके उसने नाम बताए, (चेतो महतो और आन्धा करमाली) दोनों धावैया के निवासी थे। संलग्न चितरपुर गांव के मुखिया ने बताया कि चार शव पाए गए थे, दो शव उसके गांव के व्यक्तियों के थे और दो होनेह गांव के उसने अपने गांव के व्यक्तियों के नाम बताए हैं जो दोनों महिलाएं हैं, (मिलुआ, लाडु चौधरी की पुत्री और निरुआ, महेश चौधरी की स्त्री)। उसने आगे बताया कि चारों शव मृत व्यक्तियों के रिश्तेदार ले गए थे।

30. अनेक गवाहों द्वारा दिए गए विवरणों को ध्यान में रखते हुए मैं केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि संभवतः सात व्यक्तियों, दो पुरुष और पांच महिलाओं की मृत्यु हुई जबकि केवल पांच शव प्राप्त हुए थे। संभवतः (यह केवल अनुमान है) पुरुषों के शव धावैया गांव के थे और महिलाओं के होनेह के। इसके सिवाय कुछ और कहना संभव नहीं है, जो निश्चित हो तथा जिसकी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पुष्टी की जा सके। चूंकि उन व्यक्तियों के नामों का मेरे समक्ष उल्लेख किया गया है जो कि मारे गए बताए जाते हैं, शायद पुलिस और न्यायधिकारीगण सच्चाई या बयानों की यथार्थता का पता लगाने के लिए जांच पड़तालें कर सकते हैं।

31. जैसा कि मैंने ऊपर पैरा 12 में जिक्र किया है, हजारी बाग प्रभाग के आयुक्त द्वारा 26-6-1974 और 24-12-1974 को आयोजित की गई दो बैठकों में इस क्षेत्र में बिना लाइसेंस कोयले के खनन और उसके परिवहन को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया था। पहले की बैठक में जिन मुख्य सुझावों को स्वीकार किया गया था वे औद्योगिक लाइसेंस और काम चालू करने संबंधी अनुमति के बगैर कोयले का उत्पादन करने और उसे भेजने के मामलों में तुरन्त कानूनी, दंडात्मक कार्यवाही करने से संबंधित थे; एक सिफारिश यह भी थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए और यह कि राष्ट्रीयकरण के लम्बित रहने तक निजी पट्टेदारों को औद्योगिक लाइसेंस, काम शुरू करने की अनुमति और ग्रेड प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रदान करके क्षेत्र में काम करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिएं। इस सिफारिश का उद्देश्य यह था कि इससे श्रमिकों और कर्मचारिवर्ग के लिए विनियमित रोजगार सुनिश्चित करने और फलस्वरूप राष्ट्रीयकरण के लिए रास्ता हमवार करने की फौरी समस्या हल हो जाएगी।

32 जिन उपायों की सिफारिश दूसरी बैठक में की गई, उनका सीमा क्षेत्र कुछ ज्यादा व्यापक था। वे (1) कोयले के गैर-कानूनी ट्रक परिवहन को नियंत्रित करने के लिए ऐसी जांच चौकियों, जिनमें समुचित रूप से सी०एम०ए०एल० के कर्मचारी तथा पुलिस वाले तैनात हों, को स्थापित करने, (2) उप-आयुक्त जिनके साथ पुलिस होगी और जिनके साथ महानिदेशक खान सुरक्षा और सी०एम०ए०एल० के अधिकारीगण घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होंगे, के नेतृत्व में अचानक छापे मार कर गैर-कानूनी कोयला खनन को रोकने से संबंधित थे। यह सिफारिश भी की गई कि गैर-कानूनी खनन के लिए दंड देने हेतु कोयला खनन संबंधी सभी कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

33. अपनी वे सिफारिशें करने से पूर्व जोकि कोयले के गैर-कानूनी खनन को रोकने और जहां आवश्यक हो, उसे नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई हैं, मैं कोयला खनन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों से संबद्ध उपबन्धों का सारांश पेश करूंगा। सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति, किसी कोयला खान को खोलने या चलाने से पूर्व, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार से वैध खनन पट्टा प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, वह खान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत खान के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा। धारा 16 के अन्तर्गत खान का मालिक एजेंट या प्रबन्धक, किन्हीं खनन संक्रियाओं के शुरू किए जाने से पूर्व, मुख्य खान निरीक्षक, भारतीय खान ब्यूरो को तथा जिस जिले में खान स्थित हो, उसके जिलाधीश को विहित प्रपत्र में लिखित रूप में नोटिस देगा। इसके अलावा वह कोयला खान (रक्षण और सुरक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 39(1) के

अन्तर्गत नोटिस भी देगा, अनिवार्य जिन्स अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुमति प्राप्त करेगा तथा अन्त में औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत लाइसेंस भी प्राप्त करेगा ।

34. ऊपर उल्लिखित अधिनियम समुचित दंडों की व्यवस्था करते हैं । उदाहरणार्थ, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करने पर एक साल तक की कैद की सजा हो सकती है या 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों ही दंड हो सकते हैं । इसी प्रकार, खान अधिनियम की धारा 16 और 17 के उल्लंघन पर, धारा 73 और 69 के अधीन कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों ही सजाएं हो सकती हैं ।

35. जिन परिस्थितियों में यह दुर्घटना घटी, उन्हें ध्यान में रखते हुए, मैं इसे अपने लिए लाजिम समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के गैर-कानूनी खनन की रोकथाम करने के लिए कुछ सिफारिशें करूं । मैं यह मान कर चलूंगा कि 1973 में (कुछ एक खानों को छोड़ कर) सभी वर्तमान खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार की यह नीति है कि भविष्य में कोयला खनन का कार्य केवल सरकारी क्षेत्र में ही किया जाएगा ।

36. कोयला रखने वाली भूमियों की दो श्रेणियों के बारे में विचार किया जा सकता है । पहली श्रेणी उन जमीनों से संबंधित है, जो कोयला उत्पादन क्षेत्र (अभिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अभिग्रहीत की गई हैं । इस प्रकार के अभिग्रहण के पश्चात् जमीनें, या तो केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द रहती हैं या किसी सरकारी कम्पनी के सुपुर्द जिसे केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत इस प्रकार के अधिकार अंतरित करती है । यदि जमीनें केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द हों तो उस क्षेत्र में गैर-कानूनी खनन की रोक थाम करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर रहती है । न तो धारा 12 के अन्तर्गत कब्जा लेने में होने वाली देरी से न ही धारा 11 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी को जमीन सुपुर्द करने संबंधी आदेशों के जारी किए जाने में इसी प्रकार की देरी से इस प्रकार की जिम्मेदारी के संबंध में अस्पष्टता नहीं आने दी जानी चाहिए । जैसा कि मैं ऊपर पैरा 12 में उल्लेख कर चुका हूं ; यह इस प्रकार की देरी ही है जो एक तरह का कानूनी खोखलापन पैदा कर देती है जिससे बेईमान तत्व अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं । यही कारण है कि पैरा 21 में मैंने यह सिफारिश की है कि अभिग्रहण करने और कब्जा लेने के बीच और वैसे ही भूमि का अभिग्रहण करने और उसे किसी सरकारी कम्पनी के सुपुर्द करने के बीच कम से कम अन्तराल होना चाहिए । केन्द्रीय सरकार, सरकारी कम्पनी जैसे किसी ऐसे संगठन के जरिए, जो कि क्षेत्र में काम करता हो, उस क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण रख सकती है । यह अत्यावश्यक है कि समय की दृष्टि से गैर-कानूनी खनन रोकने संबंधी कम्पनी की जिम्मेदारी यथा समय जल्दी से जल्दी शुरू हो जानी चाहिए ।

37. सरकारी कम्पनी जब एक बार मामले से अवगत हो जाए तो उसे समुचित सीमा पत्थर गाढ़ कर क्षेत्र का स्पष्टतया सीमांकन करने और फिर निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए उचित उपाय आरम्भ करने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए । यह बात दूरस्थ और दुर्गम्य क्षेत्रों में आवश्यक होगी क्योंकि वास्तव में यही वे क्षेत्र हैं जहां गैर-कानूनी खनन का खतरा विद्यमान है । इस प्रकार के प्रहार्य स्थलों की स्थिति के कारण सामान्यतः कोई कठिनाई पेश नहीं आनी चाहिए ; क्षेत्र पर्याप्त खोज के बाद अभिग्रहीत किया गया होगा और अभिग्रहण पूर्ण होने के समय तक केन्द्रीय सरकार और सरकारी कम्पनी को भौगोलिक लक्षणों और खाकों तथा क्षेत्र में से होकर गुजरने वाली सड़कों और अन्य संचार व्यवस्थाओं का पता लग गया होगा । खनन अभियंताओं को उन क्षेत्रों की जानकारी होगी, जिनमें कोयले की परत, भूमिगत या उद्‌गत रूप से, विद्यमान है और सावधिक निरीक्षण की एक प्रणाली के जरिए ऐसे स्थलों पर समीपी तथा कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए और यह काम केवल अधिनस्थ कर्मचारियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए । इन साधनों से गैर-कानूनी खनन का पता समय पर लगाया जा सकता है तथा उसे शुरू में ही समाप्त किया जा सकता है ।

38. दूसरी श्रेणी उन भूमियों से संबंधित है जिनके संबंध में राज्य सरकारें निजी पक्षों को खोज लाइसेंस या खनन पट्टे देती हैं । यदि पैरा 35 में मेरे द्वारा उल्लिखित अनुमान सही है तो मैं यह समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के पट्टे मंजूर नहीं किए जाएंगे । जहां तक पहले से मंजूर किए गए पट्टों का सम्बन्ध है, इस प्रकार की जमीनों पर 1957 के अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कर लिए जाने चाहिएं । तथापि यदि यह वांछनीय अथवा व्यवहार्य नहीं समझा जाता तो कोयला खनन संक्रियाओं से संबंधित सभी प्राधिकारियों को चाहिए कि वे निजी पक्षों की कोयला निकालने संबंधी योजनाओं की प्रगति पर तीखी निगाह रखें । जो विभिन्न कानून इस से संबंधित हैं, उनका उल्लेख मैंने ऊपर पैरा 33 में किया है । संक्षिप्त रूप में प्राधिकारी ये हैं (1) राज्य सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व खान निदेशक या अन्य समान प्राधिकारी करता है, और (2) केन्द्रीय सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व खान सुरक्षा महानिदेशक और कोयला खान (रक्षण और सुरक्षा) नियम, 1954 और अनिवार्य जिन्स अधिनियम और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में निर्दिष्ट प्राधिकारी करते हैं । चूंकि खनन के लिए अनिवार्य पहला कदम खनन पट्टे का मंजूर किया जाना है, इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्य सरकार, जब यह कोई खनन पट्टा मंजूर करे, तो ऊपर उल्लिखित अन्य सभी प्राधिकारियों को सूचित करे ताकि वे अलग-अलग या संयुक्त रूप से पट्टेदार के कार्यकलापों पर निगाह रख सकें और जब कभी किसी कानून के उल्लंघनों का भय हो या उनका पता लगे, उचित कानूनी कार्यवाहियां शुरू करें । जहां खनन पट्टा मंजूर करने के बाद यथोचित अवधि के भीतर खनन शुरू न किया गया हो, वहां राज्य सरकार को चाहिए कि वह पट्टे को रद्द करने के संबंध में विचार करे ।

39. इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए दंड पर्याप्त कठोर हैं और विभिन्न अधिनियमों के तुरन्त और कड़े प्रवर्तन द्वारा उन्हें और अधिक प्रतिरोधक बनाया जा सकता है । मैंने यह पाया कि इस क्षेत्र में गैर-कानूनी खनन की घटनाओं के बारे में जो मामले जिला खनन प्राधिकारियों ने एक वर्ष या इससे अधिक पूर्व चलाए थे, उनके संबंध में प्रभारी अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है । न्यायाधीशों के न्यायालयों में शिकायतें दायर की गई थीं, परन्तु अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करवाने और सुनवाई शुरू करने में गम्भीर विलम्ब हुआ है । कानून के प्रवर्तन में केवल अभियोजन आरम्भ कर देना ही सम्मिलित नहीं होता । कानून का अनुपालन तथा उसका आदर केवल तभी किया जाएगा जब कि उसमें लिखित दंडों को प्रभावी ढंग से प्रवृत्त किया जाए । न्यायालयों से कहना चाहिये कि वे प्रतिरोधक सजाएं दें ।

40. ऐसे सभी प्रहार्य क्षेत्रों में उचित प्रशासनिक कार्यवाहियों के साथ-साथ कानूनी उपाय किए जाने होंगे । वास्तव में ये दोनों घनिष्ठता से आपस में बने हुए हैं और इन्हें घनिष्ठता से समन्वित किया जाना चाहिए । मैं केवल यही सिफारिश कर सकता हूं कि हजारीबाग प्रभाग के आयुक्त द्वारा आयोजित की गई दो बैठकों में लिए गए निर्णयों (और जो उपयुक्त पैराग्राफों 12, 31 और 32 में निर्दिष्ट किए गए हैं) को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए । जहां कहीं अबैध खनन से प्राप्त कोयले का परिवहन हो, वहां नियंत्रण के लिए निरीक्षण चौकियों की पद्धति

होनी चाहिए, और वे स्थल (प्वाइंट) राज्य सरकार के उचित रूप से शक्ति प्रदत्त अधिकारियों द्वारा चलाए जाएं। केवल इसी बात की आम्न-विक्रता कि कोयला एक ऐसे क्षेत्र से प्राप्त किया गया है जो उचित और वैध खनन पट्टे के अधीन है, उस क्रिया को पूर्णतया वैध नहीं बना देती यदि कोयला के खनन से संबंधित अन्य वैध नियमों का पालन न किया गया हो। इसी प्रकार दण्डाधिकारियों, पुलिस, खनन प्राधिकारियों और कोल माइन्स अथारिटी लि०/रा०को०वि०नि० के अधिकारियों द्वारा आयोजित किए गए आकस्मिक छापे गत समय में इस क्षेत्र में अवैध खनन की पद्धतियों को समाप्त करने में सफल हुए हैं, ये प्रस्तुत की गई सामग्री से प्रत्यक्ष है। तथापि यह भी प्रकट होता है कि जब कभी ऐसे पूर्वोपायों और निरोधक उपायों में ढील दी गई थी, यह पद्धति पुनः चालू हो गई थी। यह बात उल्लेखनीय है कि इसी स्थान पर, जहां वर्तमान दुर्घटना फरवरी, 1975 में घटी थी, जिला खनन अधिकारी, हजारीबाग ने मई, 1974 में वहां चल रहे अवैध खनन का पता लगाया था, उनके द्वारा उस स्थान के निरीक्षण और उसके बाद उनके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण ही खनन समाप्त हो गया। इस से केवल लगातार और निरन्तर चौकसी की आवश्यकता प्रकट होती है।

41. मैंने पैरा 9 में अवलोकित किया है कि इस क्षेत्र में अवैध खनन का एक कारण कोल माइन्स अथारिटी लि०/रा०को०वि०नि० द्वारा प्राप्त किए गए कोयले के मूल्यों और ऐसे उद्गमों जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, से प्राप्त कोयले के मूल्यों में व्यापक अन्तर है। इस प्रोत्साहन जैसा कि यह है, को घरेलू प्रयोग और भट्टे जलाने (मुख्य उद्देश्य जिसके लिए अवैध खनन को प्रयोग किया जाता है) के लिए कोयले की कीमतों को उपयुक्त निम्न स्तर पर रखकर बराबर दुर्बल बनाया जाना चाहिए। यह नोट करना रोचक है कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई कोयले की कीमतों में वृद्धि से साफ्ट कोक को छूट दी गई थी।

42. मैं आगे अपने मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश दे रहा हूं।

निष्कर्ष :

(1) घावैया गांव में अभिग्रहीत की गई भूमि पर कब्जे और अधिकारों के सम्बन्ध में किंचित अस्पष्ट और अनिश्चित स्थिति और उसमें अवैद्ध खनन को रोकने के लिये उत्तरदायी पक्ष या अभिकरण अंशतः क्षेत्र में अवैद्ध खानन् के विस्तार के लिये उत्तरदायी था (पैरा 21)

(2) एक अंशदायी घटक 1973 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीकरण के बाद कोयले की कीमतों में विशिष्ट वृद्धि और क्षेत्र में घोर बेरोजगारी की स्थितियां थीं, जिन दोनों के कारण "सहज" खनन होने लगा जिसके कारण श्रमिकों के लिये खतरे उत्पन्न हुए। (पैरा 8 और 9)

(3) ऐसे क्षेत्र में जहां कोयले की सीम और रेतीले पत्थर की कैपिंग रखने वाला नदी का किनारा लगभग शीर्ष स्थानीय था, सुरक्षात्मक खनन पद्धतियों का पालन करने में विफलता, जिससे रेतीले पत्थर के अधिभार का गिराव हुआ जिसमें मलबे के नीचे फसे श्रमिक मारे गये। (पैरा 27)

सिफारिशें :

(1) जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अभिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करती है, धारा 9 के अन्तर्गत घोषणा और धाराओं 11 और 12 के अन्तर्गत कार्यवाही के बीच के समय का अन्तराल यथासंभव कम होना चाहिये, सर्वोत्तम तो यही होना चाहिये कि अभिग्रहण के साथ-साथ ही कब्जा लेने और सरकारी कम्पनी को अन्तरण का कार्य हो (पैरा 21)

(2) सरकारी कम्पनी को, ज्यों ही जमीन उस में निहित हो, स्पष्टतः क्षेत्र का सीमांकन करना चाहिये और अवैध खनन को रोकने के लिये नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिये उपाये आरम्भ करने चाहिये। (पैरा 37)

(3) निजी पक्षों को स्वीकृत किये गये वर्तमान खनन पट्टों के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर अधिकार, 1957 अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाये (पैरा 38)

(4) यदि ऐसे अभिग्रहण को वांछनीय या व्यवहार्य नहीं समझा जाता, तो राज्य सरकारों को ऐसे पट्टों के बारे में केन्द्रीय सरकार के सभी सम्बधित प्राधिकरणों को तत्काल सूचित करना चाहिए। इन प्राधिकरणों द्वारा क्षेत्र में खनन् संक्रियाओं की प्रगति की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जानी चाहिये। (पैरा 38)

(5) कोयला खनन् से संबंधित विभिन्न कानूनों का तत्काल और प्रबल प्रवर्तन होना चाहिये। कानून के उल्लंघन पर तत्काल फौजदारी अभियोजन चलाये जाने चाहिये और न्यायालयों से निवारक दण्ड प्रदान करने की प्रार्थना की जानी चाहिये। (पैरा 39)

(6) कोल माइन्स अथारिटि लि०/रा०को०वि०नि० की सहायता और सहयोग से दण्डाधिकारियों, पुलिस और जिला खनन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संगठित किये गये अचानक छापे प्रहार्य क्षेत्रों में नियमित अन्तरालों पर आयोजित किये जाने चाहिये। (पैरा 40)

(7) अवैध रूप से प्राप्त किये गये कोयले के अनिधिकृत परिवहन को रोकने के लिये उचित स्थानों पर निरीक्षण चौकियां स्थापित की जानी चाहियें (पैरा 40)।

43. **आभार स्वीकृतियां :**

मैं उन चार परामर्शदाताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं जिनके साथ इस जांच में मिल कर कार्य करने का मुझे विशेषाधिकार दिया गया उनका व्यापक ज्ञान और अनुभव मुझे सभी अवसरों पर तुरन्त प्राप्त हुए और मैंने उन की सहायता और सलाह को अत्यधिक महत्व दिया है।

मैं मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि०, रांची और अध्यक्ष भारतीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनसार का भी आभारी हूं जिन्होंने न्यायालय की बैठकों के लिये क्रमशः रांची और धनसार में स्थान देने की कृपा की। मैं रा०को०वि०नि० (अब सेन्ट्रल कोल फील्ड्स नि०) के प्राधिकारियों के प्रति भी उनके द्वारा 13 नवम्बर को घटना स्थल के हमारे दौरे के दौरान दामोदर को पार करने के लिये किये गये अत्युत्तम बन्दोबस्त तथा उस समय दी गई अन्य बहुत सहायता के लिये कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा।

अन्ततः, मैं श्री सोहन लाल, न्यायालय के सहायक सचिव के द्वारा जांच के हर स्तर पर दी गई तत्काल एवं निपुण सेवा के प्रति अपनी सराहना रेकार्ड करना चाहूंगा ।

ह०
(पी० एम० नायक)
जांच न्यायालय

हम उपर्युक्त रिपोर्ट से सहमत हैं ।

ह०
(बी० एन० कारयण्डे)

ह० (जी०बी० मिश्र)

ह०
(दामोदर पाण्डे)

ह०
(शफीक खान)

अनुबन्ध—1

पूछताछ किये गये गवाहों की सूची

1. यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन की ओर से

यू-डब्ल्यू 1 . . श्री बहनि प्रसाद, गांव होनेह, पी०एस० रामगढ़, जिला हजारीबाग ।

यू-डब्ल्यू 2 . . श्री मो० गुलाम घौस, पुत्र, स्वर्गीय मो० गमिरुद्दीन, गांव बिदरपुर, पी०एस० रामगढ़ जिला हजारीबाग ।

यू-डब्ल्यू 3 . . श्री रामफल चौधरी, पुत्र स्वर्गीय नानहु चौधरी, गांव बिलारपुर, जिला हजारीबाग।

यू-डब्ल्यू 4 श्री पुनित राम ओहदार, पुत्र श्री होतु ओहदार, रामगढ़ के उप प्रमुख, कोठर गांव के मुखिया, पी० एस० रामगढ़ ।

2. अभियोग अन्वेषक न्यायालय द्वारा बुलाये गये

सी-डब्ल्यू 1 . . श्री भुवनेश्वर महातो, पुत्र धनाराम महातो, मुखिया चावैया गांव ।

सी०-डब्ल्यू 2 . . श्री प्रभु दयाल महातो, गोमिया ब्लौक के प्रमुख ।

सी०-डब्ल्यू 3 . . श्री एस० जी० प्रसाद, खान सुरक्षा निदेशक, रांची ।

3. एस०सी०डी०सी०/सी०एम०ए० की ओर से

एन-डब्ल्यू 1 . कृष्ण मोहन सिंह, पुत्र स्वर्गीय अनन्द लाल लाल सिंह प्रबन्धक, मेगल कोलियरी ।

एन-डब्ल्यू 2 . . श्री माची दुलाल चन्द्र, क्षेत्र महा प्रबन्धक, अर्गदा क्षेत्र ।

एन-डब्ल्यू 3 . . श्री शीलवन्त सहाय, पुत्र श्री कामेश्वर प्रसाद, वरिष्ठ राजस्व अधिकारी ।

4. जिला प्राधिकरण की ओर से

बी-डब्ल्यू 1 . . श्री राम सुरत सिंह, पुलिस के उप-निरीक्षक, रामगढ़ पी०एस०

बी-डब्ल्यू 2 . . श्री राम कुमार गुप्ता, जिला खनन अधिकारी के मुख्य सहायक, हजारीबाग ।

बी-डब्ल्यू 3 . . श्री चिन्ता रंजन चतुर्वेदी, जिला खनन अधिकारी, गिरिडिह ।

बी-डब्ल्यू 4 . . श्री मो० मन्सूर खान, ए०एस०आई० गोमिण पी०एस० (गिरिडिह)

बी-डब्ल्यू 5 . . श्री के० के० एल० दास, जिला खनन अधिकारी, हजारीबाग (अब खानों के उप निदेशक, भागलपुर)

5. डी०जी०एम०एस० की ओर से

डी-डब्ल्यू 1 . . श्री जे०सी० अग्रवाल, खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक, रांची ।

अनुबन्ध—2

प्रदर्शनीय वस्तुओं की सूची

1. सी०एम०ए०एल०/एन०सी०डी०सी० की ओर से प्रदर्शित किये गये ।

एक्स एन-1 . . भारत सरकार, इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) की की अधिसूचना संख्या का०आ० 881, तारीख 13-4-1961

एक्स एन-2 . . भारत सरकार, खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894, तारीख 22-12-1962

एक्स एन-3 . . अधिसूचनाओं की रसीदें ।

एक्स एन-4 . . खान और ईंधन विभाग प्रबन्ध निदेशक, एन०सी०डी०सी०लि०, रांची की पत्र संख्या सी-2—20 (15)/62, तारीख 18-2-1962

एक्स एन-5 . . खान और धातु मंत्रालय के अनुसूचि पत्र दिनांक 18-2-1962 और अधिसूचना संख्या का०आ० 3998, तारीख 21-12-1966

एक्स एन-6 . . अधिसूचनाओं की रसीदें

एक्स एन-7 . . प्रभारी अधिकारी, रामगढ़ पी०एम०रामगढ़ (हजारीबाग) को सम्बोधित, श्री ब्रिज नन्दन शर्मा, अभिन, एन०सी०डी०सी० लि० रामगढ़ प्रायोजना से पत्र दिनांक 16-4-1973

एक्स एन-8 . . रामगढ़ क्षेत्र को दर्शाने वाला बिहार का आंशिक मास्टर प्लैन ।

एक्स एन-9 . . रामगढ़ ब्लाक II का नक्शा ।

एक्स एन–10 . . प्रबन्धक, मेएल कोलियरी को सम्बोधित, श्री के० के० एल०दास जिला खनन अधिकारी, हजारीबाग से पत्र संख्या 3113-एम, तारीख 19-6-1974

एक्स एन–11 . . प्रबन्धक, मेएल कोलियरी को सम्बोधित, श्री जी० एम० खन्ना, ओ/आई, रामगढ़ से पत्र दिनांक 30-4-1974

एक्स एन–12 . प्रभारी अधिकारी, पी०एस० रामगढ़ को सम्बोधित, श्री कृष्ण मोहन सिंह, प्रबन्धक मेएल कोलियरी से पत्र संख्या प्रबन्धक/मेएल/75/1005, तारीख 3-4-1975

एक्स एन–13 . . (i) अधिसूचना का०आ० 881, तारीख 13 अप्रैल, 1961।

(ii) अधिसूचना का०आ० 3894, तारीख 22-12-1962

(iii) रामगढ़ ब्लाक 1 के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन कब्जा लेने से सम्बन्धित कागज।

(iv) रामगढ़ ब्लाक I के बारे में का० आ० 3894 तारीख 22-12-1962 के बारे में जारी किया गया विधायक आदेश संख्या सी० 2-20(15)/62, तारीख 22-12-1963 देखिए।

(v) अधिसूचना संख्या 3998, तारीख 21-12-1966

(vi) रामगढ़ ब्लाक ii और iii के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत कब्जा लेने से सम्बन्धित ब्लाक।

(7) श्री बी०एन० शर्मा, अमीन द्वारा प्रभारी अधिकारी, रामगढ़ पी०एस०को एफ० आई०आर० तारीख 14-4-1973 इसकी रसीद के साथ-साथ प्रस्तुत की गई।

एक्स एन–14 दुर्घटना स्थल की रूप-रेखा।

II—यूनाइटिड कोल वर्कर्स यूनियन की ओर से दायर किये गये

एक्स-यू 1 . . उप आयुक्त, हजारीबाग को संबोधित, श्री दुनित राम मोहदार उर्फ गोविन्द महतो, मुखिया, ग्राम पंचायत, कोठर से पत्र तारीख 28-2-1975

एक्स यू–2 श्री पुरन राम साहु, मंत्री भारत का साम्यवादी दल, स्थानीय समिति पत्रात् द्वारा जारी की गई पत्रिका दिनांक 1-3-75

III—खान सुरक्षा महा निदेशक की ओर से दायर किये गये।

एक्स डी–1 . . प्रभारी अधिकारी, रामगढ़ पुलिस चौकी/गोमिया पुलिस चौकी को सम्बोधित, श्री इन्द्रजीत खोसला, खान सुरक्षा उप निदेशक, रामगढ़ उप-क्षेत्र, नई सराय, जिला रामगढ़, छावनी हजारीबाग से पत्र संख्या आर०एस०आर०/566, तारीख 26-2-1975

IV—जिला प्राधिकरण की ओर से दायर किये गये।

एक्स बी–1 . . गांव दाहावैया पी० एस० गोमिया को शामिल करते हुए रामगढ़ कोयला क्षेत्र खंड 1, खण्ड II और खण्ड III को समाविष्ट करने वाली भूमि के बारे में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना तारीख 14-3-1961 की प्रतिलिपि।

एक्स बी–2 . . संलग्न सूची में वर्णित 2,230 एकड़ और 821.50 एकड़ माप की भूमि के अर्जन की और दो कागजों के नक्शों सहित रामगढ़ खण्ड I और खण्ड II में 1505 एकड़ और 3222.50 एकड़ माप की भूमि में खान, खतवान, सुराख करने खोदने और खोजने के अधिकार को घोषित करते हुए, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(i) के अधीन अधिसूचना तारीख 21-12-1966, का० आ० 3998 और अधिसूचनाओं में कुछ संशोधन करते हुए का०आ० 634 तारीख 18-2-1957 अधिसूचना 23 कागजों और नक्शा 2 कागजों में।

एक्स बी–3 . . समरबेरा, कान्देर और सारैया गांवों में रामगढ़ खण्ड II में विस्तरण के रूप में 121 एकड़ भूमि के बारे में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(i) के अधीन अधिसूचना का आ० 3400 तारीख 27-11-1973 की प्रति।

एक्स बी–4 . . पूर्व बोकारो, पश्चिम बोकारो, रामगढ़ और करणपुरी कोयले क्षेत्र में सेंट्रल डिविजन सी०एम०ए० लि० की कोयला खानें और कोयले के क्षेत्रों को दर्शाने वाली मास्टर रूपरेखा। नक्शा तारीख 6-3-1974 आलेखन संख्या पी०एल०/8485

एक्स बी–5 . . धारा 9(i) के अधीन अर्जित की कोयला अधिनियम की धारा 4 और 7 के अधीन अधिसूचित और राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय-कृत कोयला खानों और कोयला क्षेत्रों और गिरिडिह जिले में उनके रेखीले क्षेत्रों को दर्शाने वाली मास्टर रूप रेखा।

एक्स बी–6 जिला खनन अधिकारी, हजारी बाग को सम्बोधित, प्रबन्धक मेएल कोयला खान से प्राप्त पत्र संख्या प्रबन्धक/मेएल/74/1186-96, तारीख 18-4-1974 की प्रतिलिपि।

एक्स बी–7 . . जिला खनन अधिकारी हजारी बाग द्वारा 25-5-1974 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हजारीबाग के समक्ष दायर किये गये दो प्रार्थना पत्रों और शिकायतों की प्रतियां।

एक्स बी–8 . . 1963 के मुकदमें संख्या 63 के मूल पक्षों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दायर की गई समझौता विविध अपील संख्या 9/65 की याचिका सहित राज वल्लभ सिंह और यूनियन आफ इंडिया, मैसर्स एन०सी०डी०सी० लि० और अन्य के बीच हुए 1963 की मुकदमें संख्या 51 में हुई समझौता डिगरी की प्रति।

एक्स बी–9 . . गिरिडिह जिले में अवैध कोयला खनन को रोकने के लिये जिला प्राधिकरणों, गिरिडिह और हजारीबाग द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले चार्ट।

एक्स बी–10 . . मेएल कोलियरी की इंकलाइन संख्या 11क/11ख के दुर्घटना स्थल और उसकी स्थिति को दर्शाने वाली रूपरेखा।

एक्स बी–11 . . जिला खनन अधिकारी हजारीबाग को संबोधित श्री एस० सी० कुमार, प्रशासन निदेशक, मैसर्स एन०सी०डी०सी०लि० से पत्र तारीख 31-1-1964 की संलग्नकों सहित प्रति।

एक्स बी–12 . . जिला खनन अधिकारी, हजारीबाग संबोधित, श्री एच० एन० जोशी, उप-मुख्य राजस्व, मैसर्स एन०सी०डी०सी० लि० से पत्र तारीख 4-9-1965 की संलग्नक सहित प्रति।

एक्स बी–13 . . उप आयुक्त, हजारीबाग को संबोधित, श्री एस० टी० राजा, प्रबन्ध निदेशक, एन० सी०डी०सी०लि० से पत्र अ० सं० एल० ए/जी-XXXII/7/64-615, तारीख 15/20 मार्च, 1965 की प्रति।

एक्स बी–14 . . खान खोजने संबंधी शुल्क के कारण रु० 2,94,460.43 के निक्षेप को दर्शाने वाले कोषागार चालान संख्या 123, तारीख 24-3-1965 की प्रति।

एक्स बी–15 . . उप-आयुक्त के कक्ष, गिरिडिह में 2-4-1975 को हुई बैठक के कार्यवृत्त।

एक्स बी–16 . . एन०सी०डी०सी०लि० के कार्यालय में 27-2-1975 को रांची में हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति।

एक्स बी–17 . . गोमिया पी०एस० में एफ० आई० आर० की प्रति मामला तारीख 23-2-1975

एक्स बी–18 . . श्री आर० एस० सिंह, प्रभारी अधिकारी रामगढ़ पी० एस० द्वारा मेएल कोयला खान क्षेत्र, पी०एस० रामगढ़ में 23-2-1975 को 02.00 घंटों पर रेकार्ड किया गया चितरपुर गांव, पी०एस०रामगढ़, जि० हजारीबाग के विदेशी बुशाद चौकीदार का बयान।

एक्स बी–19 . . गत किराये के भुगतान और अन्य कागजों के बारे में उप मुख्य राजस्व, मैसर्स एन० सी०डी०सी०लि० दरभंगा हाउस, रांची को संबोधित, श्री सी०चतुर्वेदी, जिला खनन अधिकारी से पत्र संख्या 709/एन०, तारीख 6-6-1975।

एक्स बी–20 . . 1963 के 51 के मूल मुकदमें, अर्थात् 1963 के 51 के पक्षों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दायर की गई 1965 की अपील संख्या 9 में समझौते की याचिका के साथ संलग्न नक्शे की प्रति।

एक्स बी–21 . . मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग के न्यायालय के 1974 मामला संख्या 9 के आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति।

[सं० एन० 11015/8/75-एम०]

New Delhi, the 23rd February, 1976

S.O. 1066.—In pursuance of section 27 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby publishes the report submitted to it under sub-section (4) of section 24 of the said Act by the Court of Inquiry appointed under that section by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2397 dated the 11th July, 1975, to hold an inquiry into the causes of, and circumstances attending, the accident which occurred on 22nd February, 1975 while mining coal opposite Mael Colliery in District Giridih, State of Bihar.

Report of the Court of inquiry into the causes and circumstances attending the accident which occurred while mining coal opposite Mael Colliery in District Giridih, State of Bihar on the 22nd February, 1975.

The accident which is the subject matter of this inquiry took place on 22-2-1975 on the northern bank of the river Damodar opposite the Mael Colliery of the Coal Mines Authority of India Ltd., and the National Coal Development Corporation (referred to hereafter as C.M.A.L./N.C.D.C.) lying on the southern bank* The site of the accident falls in village Dhawaiya, P. S. Gomia, in district Giridih, Bihar State. The Mael Colliery lies in district Hazaribagh, the Damodar at this point forming the boundary between the two districts.

2. The accident occurred in an out-crop of coal. Such out-crops occur at many points along the Damodar and other rivers and also in nearby places. The area forms

*When the inquiry was in progress, the C.M.A.L. and N.C.D.C. got merged into a new Organisation set up by the Central Government, namely, the Coal India Ltd. In this report, however, I have preferred to retain the earlier names.

part of the sol-called Ramgarh Project of the N.C.D.C. which comprises four blocks numbered as Blocks I to IV. Dhawaiya village falls in Block II while Mael Colliery is in Block IV. The topography of the area is gently undulating with the Damodar being the main drainage for the coal-field. Detailed prospecting has been carried out by the Geological Survey of India, the Indian Bureau of Mines and N.C.D.C. A number of coal seems for mining have been identified, containing medium coking coal, suitable, after washing, for use in the blast furnace.

3. The Court held four meetings. The first one, held at Dhanbad on 5-8-1975 was a preliminary meeting designed to settle procedures. The Court visited the area of the accident the next day but was unable to reach the spot because of the conditions in the river. The second and third meetings were held at Ranchi (16th to 18th September) and Dhanbad (24th October) to record evidence. Finally, the Court visited the site of the accident on the 13th November and heard arguments on behalf of the parties the next day at Dhanbad.

4. Three parties appeared before the Court in response to the public notice issued and filed written statements, and examined witnesses. These are (1) C.M.A.I./N.C.D.C., (2) the District Administration, Giridih, and (3) the United Coal Workers' Union, Bhurkunda. The first party examined, three witnesses, the second five and the third four. In addition, three witnesses summoned by the Court were examined, as also one on behalf of the Directorate-General of Mines Safety. A list of the witnesses examined and of the exhibits filed is shown in Annexures I and II respectively of this Report.

5. An area of nearly 15,000 acres of coal-bearing land forming Blocks I—IV of the Ramgarh Project, was notified under section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 by a Notification dated 13-4-1961 of the Central Government. Of this, an area of only 2,510 acres was notified under section 7, followed by further Notification under section 9 of the Act, on 22-12-1962. Pursuant to these Notifications, the Central Government obtained possession of the acquired area of 2,510 acres in 1963. Thereafter, the Central Government vested this area in the N.C.D.C. by an Order dated 18-2-1963 issued under section 12 of the Act. This area forms Block I of of the Ramgarh Project. Areas forming Blocks II and III of the Project, although included in the Notifications under section 4 and section 9 referred to above, were taken possession of by the Central Government under section 12 only on 30-5-1975 (i.e. over three months after the accident). The area in Block IV which includes the Mael Colliery on the southern bank of the river, although included in the Notification under section 4, was actually acquired by the Central Government under another Act, namely, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973.

6. I shall in due course go into some of the legal aspects and effects of the various Notifications referred to above. I shall first make a brief mention of the accident on the northern bank on 22-2-1975 and of subsequent developments immediately thereafter. So far as the Police are concerned, the first record is dated 23-2-1975 in the shape of a report given to Gomia P.S. by a Chowkidar named Bideshi Dushad of Chitarpur village; according to this, the accident took place at 9 A.M. on the 22nd. The parallel record is the report made by the Area General Manager (A.G.M.) of the N.C.D.C. to the Ramgarh P.S. on the 22nd. The A.G.M. was on a visit to the Mael Colliery of the N.C.D.C. that very afternoon and had then heard of an accident caused by roof-collapse in an illegal working of coal on the opposite bank. The telephone lines being out of order the A.G.M. proceeded immediately to Hazaribagh and informed the Deputy Commissioner in person and, as advised by the latter, lodged a formal report with the Sub-Inspector of Ramgarh P.S. (Annexure III of the Written Statement filed by the N.C.D.C.).

7. The next day i.e. 23-2-1975, the Joint Director of Mines Safety, Ranchi and various officers of the State Government including the Police, visited the area. The Deputy Commissioner and Superintendent of Police, Giridih paid a visit on 27-2-1975. Rescue/recovery operations were started on 23-2-1975 and continued till the 28th in the course of which blasting had to be resorted to; a lot of debris was removed and two dead bodies were recovered at the site of the accident, one each on the 27th and 28th. Meanwhile, on the 26th, a report was received of the recovery of three decomposed bodies of women buried in the sand on the river bank a kilometer upstream. All the live dead bodies were taken over by the Police and sent to the Government Hospital at Hazaribagh. After post-morten, they were disposed of; there were no claimants and none of the bodies could be identified.

8. I must at this stage say something about the origin and growth of illegal coal mining in this area; possibly the same would apply to other areas where this practice has cropped up. Such mining appears to be largely confined to out-crops of coal, especially on the river banks of rivers like the Damodar in this instance, and to other areas where seams occur under a thin over-burden. Several factors appear to be responsible for the origin of this practice in recent years and, in particular, after the nationalisation of the coal industry in 1973. The virtual inability of any private parties to take up coal-mining after nationalisation of the industry led to surreptitious mining of coal wherever possible. This was particularly so in out-of-the-way, inaccessible places where illegal mining was not easily detected and, when detected, could not be easily stopped. In this particular case, for instance, the village Dhawaiya is, for all purposes, difficult of access from the northern side of the Damodar; it can be reached only from the southern bank, but only in those parts of the year when the conditions make it possible to cross the river near Mael Colliery. Even the passage to the Mael Colliery is rather difficult, having regard to the nature of the terrain, as we found during our journey to the place.

9. Another factor which must have contributed to the growth of the practice was the considerable increase in coal prices following nationalisation. Coal mining having become virtually a State monopoly, workers who could not obtain employment in the State coal mines reverted very easily to mining in unlicensed places. Unscrupulous and law-breaking elements were undoubtedly quick to take advantage of the situation. Wherever possible, they had recourse to easy mining—easy in the sense that very little capital investment is required, but from the national point of view, very wasteful and dangerous mining also. Faced with unemployment, workers were driven to take part in such illegal practices in spite of the low wages paid. A number of witnesses appeared before me and testified to the spread of illegal mining at many places in Hazaribagh and Giridih districts along the banks of Damodar and its tributary Vera. They have spoken of hundreds of workers taking part; the number may contain an element of exaggeration but there seems little doubt that the practice spread to many places. Without obtaining a prospecting license or a mining lease or other authorisation or permission required under the various laws on coal mining, persons set themselves up as owners of out-crops of coal and these places attracted the unemployed labour from the surrounding villages. From the evidence tendered before me it would appear that workers paid a royalty of 2 annas to 4 annas per basket of coal which they cut and removed; this coal they transported to nearby places for sale. The sharp increase in the prices of coal in the nationalised mines would no doubt have made it possible to find a market for this coal which was sold at much lower prices.

10. From the material before me it is clear that unlicensed mining of coal in this area started soon after nationalisation. There are a number of letters written by officials of N.C.D.C. going back to November 1973 in which such cases have been cited; there are also references to unauthorised transport of such coal. These letters were addressed to the District Authorities of Hazaribagh and Giridih and to the officers incharge of the Police Stations at Ramgarh, Gomia and other places. It is interesting and significant that in a letter written on the 10th November, 1973, the Manager of the Mael Colliery of the N.C.D.C. informed the District Mining Officer, Hazaribagh, that the river-bed quarry opposite the Mael Colliery was being worked for coal. The letter added "These places have become very dangerous due to over-handing and accident is apprehended any time", and concluded with a request for timely preventive action to stop such practices. On the 24th March, 1974, the Manager of the Mael Colliery addressed the officer incharge of the Ramgarh Police Station about illegal transport of coal in the area. On the 18th April 1974 he wrote again to the

District Mining Officer, Hazaribagh about illegal extraction of coal in Mouza Dhawaiya on the northern bank of the Damodar and opposite the Mael Colliery workings on the southern bank. Unauthorised mining and transport of coal figures in several other letters written by officers of Mael Colliery and the Sirka Colliery, in letters addressed to the Deputy Commissioner, Hazaribagh by the Area General Manager of the N.C.D.C. and the Sub-Area Manager of the Sirka Group.

11. The evidence tendered by the District Mining Officer, Giridih largely confirms the prevalence of illegal mining practice in the Area. According to him, such complaints received by him were promptly investigated by him as well as by the Police Authorities and criminal prosecutions have been launched to which he has cited two instances. We thus know something of the background of the conditions and circumstances in which an accident occurred in Dhawaiya village on the 22nd February, 1975, in an out-crop of coal on the bank of the river.

12. Knowledge of this practice led to action on the part of the District Authorities and by N.C.D.C.'s staff as well. We have before us evidence to show that the District Authorities connected with mining and with the administration of law and order bestirred themselves to stop the practice; there were at least two important meetings held by the Commissioner of the Hazaribagh Division, one on the 26th June 1974 and the other on the 24th December, 1974. Several remedial and preventive steps were considered in these meetings; among them those centering on the establishment of check posts at crucial points in the area to put a curb on transport of coal. In order to suppress illegal mining i.e. mining without obtaining any mining lease or other permission required under the various laws, surprise raids were recommended under the leadership of the Magisterial and Police authorities as well as officers of the Directorate General of Mines Safety and the District Mining Officers. As a long-term measure to meet this menace, suggestions were made for the stricter enforcement of the various laws bearing on coal mining through more rigorous recourse to criminal prosecution and various administrative measures. It is the case of the District Mining Officer, Giridih that the action taken by him and the Police in several cases proved effective and put a stop to the practice.

13. There has been a good deal of argument before me about the responsibility and liability of the C.M.A.L. N.C.D.C. for the accident. To appreciate this fully I shall first refer to the relevant provisions of the Coal-bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 of which I have already made a mention in para 5 above. The preamble of the Act describes the Act as intended "to establish in the economic interest of India greater public control over the coal mining industry and its development by providing for the acquisition by the State of unworked land containing or likely to contain coal deposits or of rights in or over such land, for the extinguishment and modification of such rights accruing by virtue of any agreement, lease, license or otherwise". Under section 4 of the Act, the Central Government may, by notification in the official gazette, give notice of its intention to prospect for coal in land where coal is likely to be obtained. If the Central Government is satisfied, after prospecting, that coal is obtainable, it may, by notification under section 7, give notice of its intention to acquire the whole or part of the land. After considering objections under section 8, the Central Government may, under section 9, issue a declaration of acquisition. On the publication of such declaration, the land shall, under section 10, vest absolutely in the Central Government. Under section 11, the Central Government may direct that the land, instead of vesting in the Central Government under section 10, shall vest in a Government company. And finally, under section 12, the Competent Authority may require any person in possession of any land acquired under the Act to surrender or deliver possession of the land, and if such person refuses, the Competent Authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary.

14. Now the case of the C.M.A.L./N.C.D.C. is this. Admittedly, an area of 2,510 acres falling in Block I which had been notified earlier under section 4 was acquired under section 9 on 29-12-1962; possession of this was taken over by the Central Government in early 1963; on 18-12-1963, by virtue of Order under section 11, the area was vested in the N.C.D.C. However, so far as Blocks II and III are concerned, the N.C.D.C. was not put in possession of the areas by the Central Government. As mentioned in para 5 above, the Central Government acquired possession of these areas only on 30-5-1975 and such possession has not yet been vested in the N.C.D.C. by an Order under section 11. Thus, the N.C.D.C. was in no way concerned with Blocks II and III, and since Dhawaiya village of District Giridih falls in Block II, it can in no sense be argued that the N.C.D.C. had any sort of right or liability, whether de facto or de jure, over the place where the accident took place. N.C.D.C.'s only interest in this matter, according to them, lay in their being neighbours to the site of the accident, of being one of the first agencies to become aware of the accident and reporting it to the District Authorities and, thereafter, or rendering such assistance as lay in their capacity in carrying out the rescue operations.

15. It is further urged on behalf of the N.C.D.C. that being a responsible organisation concerned with the prevention of illegal mining in the area, they had no several occasions reported to the various authorities on the prevalance of illegal mining in areas outside their lease-hold and had consistently taken or assisted in the taking of steps to prevent such practices.

16. The case of the Bihar Government, as presented by the District Authorities of Giridih, is that the place of accident fell very much within the area acquired (by the Central Government) and the authorities of the N.C.D.C. did not take any effective steps to stop such illegal mining and, strangely enough, no information about such illegal mining, particularly in village Dhawaiya, was ever given or sent to the District Authorities of Giridih though it was known that the area falling north of the Damodar river falls within the District of Giridih. Information about some illegal mining in Sambrabera and Kander (Gidhania) within district Giridih was received by the District Authorities, Giridih and all such mining operations were promptly, firmly and effectively checked and stopped by the magistracy and the Police. Local villagers had started extraction of coal from the place of accident; this was known to the officials, staff and security guards of N.C.D.C. working in the Mael Colliery, but the N.C.D.C. did not take any steps to stop the same themselves, nor did they inform the local authorities and the Police of such illegal mining within the acquired area for reasons best known to them. They did not also take any action to start their own mining operations within the acquired areas. "By starting their mining operations within the acquired area including the place of accident, all illegal mining operations relating to the present accident could have been automatically checked and stopped effectively".

17. Thus, according to the Bihar Government, (1) the site of accident fell within the area acquired by the N.C.D.C. (2) although aware of illegal mining at the site, the N.C.D.C. staff and authorities did not report it to the District Authorities of Giridih; neither did they take any action themselves to stop such mining, and (3) the accident could have been avoided if the N.C.D.C. had started their own mining operations within the acquired area.

18. These propositions do not seem to bear much scrutiny. In the first place, although the Notification under section 9 acquiring the lands in Block II (in which Dhawaiya village is included) had been issued on 2-12-1966, the Central Government had not acquired possession of these lands till May 1975. I shall presently come to the distinction sought to be drawn between acquisition under section 10 and taking possession under section 12, but the further point to note is that at no time had the lands been vested in the N.C.D.C. under section 11. Thus, in so sense can it be urged that the site in Dhawaiya village fell in the area acquired by the N.C.D.C. Reliance is sought to be placed on a compromise petition filed before the Bihar High Court in 1966 (in which the N.C.D.C. and the Central Government were parties) and certain letters written by the N.C.D.C. to the District Authorities to show that the N.C.D.C. was in possession of the Dhawaiya lands long before the accident took place. In my opinion, no such inference follows. The responsibility or liability of the N.C.D.C. is not in any way attracted.

19. It is equally difficult to sustain the second point urged against the N.C.D.C. As I have already mentioned, the N.C.D.C. made several attempts to keep the authorities informed of illegal mining going on in the vicinity of the

N.C.D.C. area. As a matter of fact, the site opposite the Mael Colliery has been specifically mentioned in at least two of the letters which the Manager of Mael Colliery of N.C.D.C. wrote to the District Authorities of Giridih. That one of the letters, the one dated the 10th November, 1973, was addressed to the District Mining Officer of Hazaribagh, rather than of Giridih, is not a matter of much significance. The mining district of Giridih was created only in November 1972 and till that date the area of Dhawaiya fell within the Jurisdiction of the District Mining Officer of Hazaribagh; it is also in evidence that the office of the new district continued to be located at Hazaribagh till about the end of 1973. One would normally and reasonably expect a letter written to the Hazaribagh Officer to have been passed on to the officer in charge of the newly created mining district of Giridih. That such a letter was written by the Manager of Mael Colliery in November 1973 admits of no dobut. As regards the point that the N.C.D.C. made no attempt to stop the illegal mining, it may be asked whether they had any title, or duty or power to do so; the area fell outside their lease-hold. As a responsible Government Company one would expect them to inform the authorities of what was going on the other bank opposite the Mael Colliery, and this they did. All that can be said is that they could have pursued the matter more energetically, knowing full well that the land had been acquired by the Central Government and that as a Government Company (in whom it was most likely the land would be sooner or later vested) it was up to them to safeguard the Government interest.

20. The third point urged against the N.C.D.C. lacks substance. It is patently unrealistic to say that the N.C.D.C. should lose no time in starting mining operations in *all* the areas acquired by them. Mining, as practised by an organisation like the N.C.D.C., is preceded by a great deal of planning in the shape of feasibility reports and detailed project reports. The project has to be integrated into the comprehensive mining operations of the organisation and should also fit into the over-all plan of the Central Government for the production and distribution of coal in the country as a whole. There may be many other places besides the site of accident in Dhawaiya village which would need to be taken up for coal raising, but inevitably there will be an order of priority; it would be impossible, having regard to the imperatives of planned mining and the limitations and resources and trained man-power, to undertaking mining simultaneously in all areas acquired.

21. There is an interesting and important point which I should like to dispose of arising out of the submissions made by the N.C.D.C. and the Bihar Government. Section 10(1) of the Act lays down that on the publication of the declaration under section 9, the land shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. Section 12 provides for taking over possession of the land so acquired. What would be the position with regard to rights over the land during the interval between acquisition under section 10(1) and taking possession under section 12? The question has an important practical import in the event of the interval being a long one, as in this case, extending over several years. During this period, who would be responsible for keeping the acquired area free from unlicensed and illegal mining The ultimate responsibility rests, no doubt on the law enforcement agency of the State Government, but whose is the primary responsibility? Clearly, it is not that of the State Government since its rights have been acquired by the Central Government. It is not, in this case, that of the N.C.D.C., as no action under section 11(1) has been taken by the Central Government. It is not that of any person to whom a mining lease may have been granted by the State Government, since under section 10(2) such mining lease stands automatically cancelled. We are thus left with only the Central Government and, in my opinion, the responsibility rests with the Central Government notwithstanding the interpretations that may be put on sections 10(1) and 12 read together. Indeed, such a reading, carried to its logical conclusion, can create a legal vacuum, the kind of situation in which it becomes no one's responsibility to keep a watchful eye on the acquired land with a view to prevent illegal mining. Ideally, taking over possession should be simultaneous with, or should follow very soon after, the declaration under section 9; similarly there should be no time-lag in transferring the rights over the land to a Government Company under section 11(1) if such indeed is the intention of the Central Government in a particular case. If these requirements cannot be fulfilled, the respective sections in the Act should be reviewed and amended to the extent necessary and I would bring this suggestion to the notice of the Central Government. In my opinion, the somewhat nebulous position regarding the rights over the piece of land acquired in Dhawaiya village and of the party or agency responsible for preventing illegal mining therein have been partly responsible for the spread of illegal mining in the area.

22. We visited the site of the accident on 13-11-1975, crossing the Damodar from the southern bank near the Mael Colliery. The VII top seam of Ramgarh block is exposed along the north bank of the river here for a distance of about 150 m. This seam dipping north-wards is about 9 m. thick and is covered by sandstone, 4-5 m. in thickness with the usual top-soil capping. The sandstone is partly weathered, jointed and broken up into large-sized blocks (some even upto 6m × 2m × 1.5m in size) which lie on top of the bank in any overhanging position at some places. The upper part of the bank comprising the top part of the coal seam and the sandstone capping is almost vertical. The lower part consists of the rest of the coal seam and fallen debris of sandstone containing blocks of various sizes sloping down to the water level. The debris also have intercalated portions of sand deposited by the river. The extent to which the coal seam is exposed on the bank depends on the water level in the river and the height to which the debris has covered the seam.

23. We found the site of the accident almost fully covered up by debris of sandstone blocks and some quantity of river sand. Some coal excavated from the VII top seam was found at the site of the accident; this appears to have been excavated after the flood waters of the recent monsoon had receded.

24. From the evidence tendered before the court, it would appear that the accident was caused by fall of overburden at the entrance of a gallery driven about 6 m. into coal outcrop. There was an adjoining gallery with an interconnection between the two; the rib pillar appears to have been quite narrow.

25. The rescue personnel who entered the galleries after the recovery of the dead bodies have reported that there was no fall of roof in the gallery and the inter-connection; the fall had occurred at the entrance. The two dead bodies recovered from the site were reported to be found buried under the fallen debris about half a meter outside the entrance to the gallery.

26. When we examined the gallery only about 150-200 mm × 1.5 m width of the top part of the gallery at the entrance was open. The rest was covered with debris of coal and sandstone blocks. The roof of the gallery at the entrance was intact.

27. It would appear that the two persons whose bodies were recovered were perhaps engaged in cutting coal near the entrance and were trapped under the falling stone. Safe mining practice requires the bank to be sloped and stepped, to prevent fall of overburden; this precaution, needless to say, was never taken here. The vertical face of the bank together with overlying large loose blocks of sandstone must have led to the fall of overburden causing the death of workers who were directly caught and crushed underneath it.

28. How many persons lost their lives in the accident ? There were reports that as many as 40 persons were killed but these estimates are wildly exaggerated. The only reliable evidence before me shows that two dead bodies were recovered at the site of the accident in the rescue operations undertaken on the 27th and 28th February and that in addition, the bodies of three women, buried in the sand about one kilometre upstream of the site were also found at the same time. All these five bodies were taken over by the Police and according to the Sub-Inspector incharge of Gomia Station, the bodies could not be identified and there were no claimants.

29. Some of the witnesses speak of four dead bodies having been recovered at the site of the accident. I would remark that rescue operations were undertaken only on the

23rd, It is difficult to say now whether before this date, that is, on the 22nd itself, villagers had searched for dead bodies at the site and recovered any, except perhaps the three dead bodies found in the sands upstream, and two others reportedly taken to Chitarpur. As the whole operation was illegal there is an understandable reluctance on the part of the villagers to be anything more than vague in what they say. A witness produced by the United Coal Workers' Union and belonging to nearby Honeh village says that three women of his village, whom he has named (Sumitra Kumari, daughter of Gajju Karmali, Pran Kumari Devi, wife of Rati Karmali and Pato Kumari, daughter of Gafur Mahato), were killed in the accident, although he adds that the three dead bodies were not recovered and did not become available; possibly the reference is to the three bodies buried in the sand upstream of the site of accident. The Mukhiya of Dhawaiya village has deposed to the death of two persons, whom he has named, (Chaito Mahato and Andha Karmali) both coming from Dhawaiya. The Mukhiya of adjoining Chitarpur village has spoken of 4 dead bodies having been recovered two belonging to persons of his village and two to Honeh village. He has named the persons of his village, both women (Milua, daughter of Ladu Chaudhury and Nirua, wife of Mahesh Chaudhury). He has added that all the four dead bodies were taken away by the relatives of the deceased.

30. Taking into account the statements made by many of the witnesses I can only conclude that probably seven persons lost their lives, two men and five women, although only five dead bodies were recovered. Probably, (this is only a surmise) the bodies of the men belong to Dhawaiya village and of the women to Honeh. Beyond this it is not possible to say anything which is definite or is substantiated by reliable evidence. As names of persons who are alleged to have been killed have been mentioned before me, the Police and the Magistracy could perhaps make enquiries to ascertain the truth or correctness of the statements.

31. As I have mentioned in para 12 above, measures to check the unlicensed mining and transport of coal in this area were discussed at two meetings held by the Commissioner of Hazaribagh Division on 26-6-1974 and 24-12-1974. The main suggestions agreed to at the former meeting related to the prompt taking of legal, penal action in cases of raising and despatch of coal without industrial license and opening permission; there was also a recommendation that such collieries should be nationalised by the Central Government and that pending nationalisation the private lesses should be given facilities for working the area by expeditious grant of industrial licence, opening permission and grade certificates. The point of the recommendation was that it would solve the immediate problem of ensuring regular employment to labourer and staff and smoothen the way to eventual nationalisation.

32. The measures recommended at the second meeting were somewhat more comprehensive in scope. They related to (1) setting up of check-posts, suitably manned by C.M.A.L. staff and the police, to curb illegal truck transport of coal, (2) stopping of illegal coal mining by carrying out surprise raids under the leadership of the Deputy Commissioner, accompanied by the Police and with the officers of the D.G.M.S. and the C.M.A.L. closely associated. It was also recommended that all laws bearing on coal mining should be strictly enforced with a view to punish illegal mining.

33. Before making my recommendations designed to prevent and, where necessary, curb illegal mining of coal, I shall summarise the relevant provisions in the various Acts bearing on coal mining. In the first place, before a person opens or work a coal mine, he shall obtain a valid mining lease from the State Government under section 4 of the Mines & Minerals (Regulations & Development) Act, 1957. He shall in addition, appoint a manager for the mine under section 17 of the Mines Act, 1952. Under section 16, the owner, agent or manager of a mine shall, before the commencement of any mining operations, give to the Chief Insnector of Mines, Indian Bureau of Mines and the District Magistrate of the district in which the mine is situated, notice in writing in the prescribed form. He shall further give notice of opening under Rule 39(1) of the Coal Mines (Conservation and Safety) Rules, 1954, obtain permission as required under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 and finally, obtain a licence under section 11 of the Industrial (Development and Regulation) Act.

34. The above-mentioned Acts provide for appropriate penalties. For instance, contravention of section 4 of the Mines & Minerals (Regulation & Development) Act is punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine upto Rs. 5,000 or with both. Contravention of sections 16 and 17 of the Mines Act, is similarly punishable, under sections 73 and 69, with imprisonment or fine or with both.

35. Having regard to the circumstances in which the accident took place, I consider it incumbent on me to make some recommendations for preventing such illegal mining taking place in future. I will assume that after the nationalisation of all existing coal mines in 1973 (but for a few exceptions) it is Government's policy that in future coal mining will be undertaken only the public sector.

36. Two categories of coal-bearing lands could be considered. The first one relates to lands acquired under the Coal Bearing Areas cquisition & Development) Act of 1957. After such acquisition the lands vest either in the Central Government or in a Government Company to whom the Central Government transfers such rights under section 11 of the Act. If the lands vest in the Central Government, the primary responsibility for preventing illegal mining in the area rests with the Central Government. Such responsibility should not be allowed to be obscured by delay in taking over possession under section 12, nor by similar delay in issuing orders under section 11 vesting the land in a Government Company. It is such delay, as I have mentioned in para 21 above, which creates a kind of legal vacuum which is exploited by unscrupulous elements. That is why I have made the recommendation in para 21 that there should be a minimum of time-lag between acquisition and taking over possession and similarly between acquisition and vesting of land in a Government Company. The Central Government can exercise effective control over the area only through an organisation, like the Government Company, which operates in the area. It is essential that the Company's responsibility for preventing illegal mining should commence at the earliest possible point of time.

37. Once the Government Company is seized of the matter it should lose no time in clearly demarcating the area, by planting of suitable boundary stones, and then instituting suitable measures for inspection and supervision. This will be necessary in remote and inaccessible areas, since it is precisely here that the danger of illegal mining exists. The location of such vulnerable points should not ordinarily present difficulty; the area would have been acquired after adequate prospecting and the geographical features and contours, as also the roads and other communications running through the area would have come within the konwledge of the Central Government and the Government Company by the time acquisition is completed. Mining Engineers would be aware of the areas where the coal seam occurs, either underground or as out-crop, and such points should be subjected to close and rigorous watch, through a system of periodical inspection which is not left wholly to the subordinate staff. By these means attempts at illegal mining could be discovered in time and nipped in the bud.

38. The second category relates to lands over which State Governments grant prospecting licences or mining leases to private parties. If the assumption mentioned by me in para 35 is correct, I take it that there will be no such leases granted in future. In regard to leases already granted rights over such lands should be acquired under the Act of 1957. However, if this is not considered desirable or feasible, all the authorities concerned with coal mining operations should keep an alert eye on the progress of the private party's plans for coal-raising. The various pieces of legislation bearing on this have been indicated by me in para 33 above. Briefly, the authorities are (1) the State Government, as represented by the Director or Mines or other comparable authority, and (2) Central Government, as represented by the Director-General of Mines Safety and the authorities specified under the Coal Mines (Conservation & Safety) Rules, 1954, the Essential Commodities Act and the Industries (Development & Regulation) Act. Since the essential first step to mining is the grant of a mining lease, it seems necessary that the State Government, when it grants a mining lease, informs all the other authorities mentioned above, so that they can, severally or jointly, keep an eye on the activities of the lessee and initiate suitable legal measures whenever infractions of

any of the laws are feared or are discovered. Where no mining has been undertaken within a reasonable period after the grant of mining lease, the cancellation of the lease should be considered by the State Government.

39. The penalties for such infractions are fairly stringent and can be made more deterrent by prompt and rigorous enforcement of the various Acts. I found that in regard to instances of illegal mining in this area cases which had been instituted by the District Mining authorities over an year or more ago had not been effectively followed up. Complaints had been filed in the Courts of Magistrates, but there has been serious delay in securing the appearance of the accused in Court and in commencing the hearing. Enforcement of the law does not consist in merely launching a prosecution. The law will be observed and respected only if the penalties written into it are effectively enforced. Courts should be moved to award deterrent penalties.

40. In all such vulnerable areas, legal measures will have to go hand in hand with suitable administrative seps. The two are indeed closely inter-twined and should be closely co-ordinated. I can only recommend that the decisions reached at the two meetings held by the Commissioner of Hazaribagh Division (and referred to in paras 12, 31 and 32 above) should be effectively implemented. Wherever there is transport of coal obtained from illegal workings, there should be a system of check-posts for control, the points being manned by suitably empowered officers of the State Government. The mere fact that coal has been obtained from an area under a proper and valid mining lease does not make the operation fully legal if other legal enactments bearing on coal mining have not been fulfilled. Similarly, surprise raids jointly organised by the Magistracy, the Police, the Mining authorities and the officers of the C.M.A.L./N.C.D.C. have succeeded in putting an end to illegal mining practices in this area in the past; this much is in evidence in the material produced before. However, it also appears that as soon as such precautions and preventive measures were relaxed, there was a revival of the practice. It is significant that at the very spot where the present accident took place in February 1975, the District Mining Officer, Hazaribagh had discovered illegal mining going on in May 1974; his visit to the place and the steps he took thereafter had led to a cessation of mining. This only brings out the need for continuous and constant vigil.

41. I have observed in para 9 that one of the reasons for illegal mining of coal in the area is the wide difference between the prices of coal mined by the C.M.A.L./N.C.D.C. and that obtained from illegally mined out-crops. This incentive, such as it is, should be steadily undermined by keeping the prices of coal for domestic consumption and brick-burning (the main purposes for which illegally-mined coal is used) at a reasonably low level. It is interesting to note that prices of soft coke were exempted from the increase in coal prices recently announced by the Government.

42. I proceed to summarise my main findings and recommendations :

Findings :

(1) The somewhat nebulous and uncertain position regarding possession and rights over the land acquired in Dhawaya village and of the party or agency responsible for preventing illegal mining therein was partly responsible for the spread of illegal mining to the area. (Para 21)

(2) A contributory factor was the marked increase in coal prices following nationalisation of the Coal Industry in 1973 and the conditions of serious unemployment in the area, both of which led to "easy" mining with consequent hazards to the workers. (Paras 8 and 9).

(3) Failure to observe safe mining practices in an area where the river bank containing the coal seam and the sandstone capping was almost vertical, led to the fall of the sandstone overburden, killing the workers trapped underneath the debris. (Para 27).

Recommendations :

(1) Where the Central Government proceeds under the Coal-Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957, the time-lag between the delcaration under section 9 and action under sections 11 and 12 should be as short as possible; ideally, acquisition should be simultaneous with taking over possession and transfer to a Government Company. (Para 21).

(2) The Government Company, as soon as the land is vested in it, should clearly demarcate the area and institute measures for regular inspection and supervision in order to prevent illegal mining. (Para 37).

(3) Rights over lands covered by existing mining leases granted to private parties may be acquired under the 1957 Act. (Para 38).

(4) If such acquisition is not considered desirable or feasible, the State Government should immediately inform all the concerned authorities of the Central Government about such leases. The progress of mining operations in the areas should be periodically reviewed by these authorities. (Para 38).

(5) There should be prompt and vigorous enforcement of the various laws bearing on coal-mining. Contravention of the law should be visited with prompt criminal prosecution and Courts should be moved to award deterrent penalties. (Para 39).

(6) Surprise raids organised jointly by the Magistracy, the Police and the District Mining Authorities and with the assistance and co-operation of the C.M.A.L./N.C.D.C. should be carried out in vulnerable areas at regular intervals. (Para 40).

(7) Check-posts at suitable points should be set up to prevent unauthorised transport of illegally mined coal. (Para 40).

43. *Acknowledgements* :

I wish to express my thanks to the four Assessors with whom I was privileged to be associated in this Inquiry. Their wide knowledge and experience were readily made available to me on all occasions and I have greatly valued their assistance and advice.

I am also thankful to Messrs. Hindustan Steel Ltd., Ranchi and the President of the Indian Coal Mines Rescue Stations Committee, Dhansar for kindly sparing accommodation at Ranchi and Dhansar respectively for sittings of the Court. I should also mention my gratitude to the authorities of the N.C.D.C. (now the Central Coalfields Ltd.) for the excellent arrangements made by them for crossing the Damodar during our visit to the site of the accident on the 13th November and for much other help at the time.

Finally, I would like to record my appreciation of the prompt and efficient service rendered by Shri Sohan Lall, Assistant Secretary of the Court, at all stages of the Inquiry.

Sd/-
(P. M. Nayak)
Court of Inquiry

We agree with the above Report.

Sd/-
(V. L. Karwande)

Sd/-
(G. B. Misra)

Sd/-
(Damodar Pandey)

Sd/-
(Shaffique Khan)

ANNEXURE I

LIST OF WITNESSES EXAMINED

I. On behalf of United Coal Workers' Union

U-WI Shri Barhan Prasad, Village Honeh, P. S. Ramgarh, District Hazaribagh.

U-W2 Shri Mohd. Gulam Ghouse, S/O Late Mohd. Gamiruddin, Village Chitarpur, P. S. Ramgarh, Distt. Hazaribagh.

U-W3 Shri Ramfal Choudhury, S/o Late Nanu Choudhury Village Chitarpur, Distt. Hazaribagh.

U-W4 Shri Punit Ram Ohdar, S/o Shri Hotu Ohdar, Dy. Pramukh of Ramgarh, Mukhiya of Kothar Village, P. S. Ramgarh.

II. Summoned by the Court of Inquiry

C-W1 Shri Bhuneshwar Mahato, S/o Dhanaram Mahato, Mukhiya Dhawaiya Village.

C-W2 Shri Prabhu Dayal Mahato, Pramukh of Gomia Block.

C-W3 Shri S. D. Prasad, Director of Mines Safety, Ranchi.

III. On behalf of N.C.D.C./C.M.A.

N-W1 Shri Krishan Mohan Singh, S/o Late Anand Lal Singh, Manager, Mael Colliery

N-W2 Shri Sachi Dulal Chandra, Area General Manager, Argada Area.

N-W3 Shri Shilwant Sahai, S/o Shri Kameshwar Prasad, Senior Revenue Officer.

IV. On behalf of District Authority

B-W1 Shri Ram Surat Singh, Sub-Inspector of Police, Ramgarh P. S.

B-W2 Shri Ram Kumar Gupta, Head Assistant of Distt. Mining Officer, Hazaribagh.

B-W3 Shri Chitta Ranjan Chaturvedi, Distt. Mining Officer, Giridih.

B-W4 Shri Mohd. Mansoor Khan, A.S.I., Gomia P. S. (Giridih).

B-W5 Shri K. K. L. Das, District Mining Officer, Hazaribagh (Now Deputy Director of Mines, Bhagalpur).

V. On behalf of D.G.M.S.

D-W1 Shri J. C. Agarwal, Joint Director of Mines Safety, Ranchi.

ANNEXURE II

LIST OF EXHIBITS

I. Produced on behalf of C.M.A.L./N.C.D.C.

Ex. N-1 Government of India, Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines & Fuel) Notification No. S.O. 881, dated 13-4-1961.

Ex. N-2 Government of India, Ministry of Mines & Fuel Notification No. S.O. 3894, dated 22-12-1962.

Ex. N-3 Receipts of Notifications.

Ex. N-4 Letter No. C2-20(15)/62, dated 18-2-1963 from the Department of Mines & Fuel to the Managing Director, N.C.D.C. Ltd., Ranchi.

Ex. N-5 Ministry of Mines & Metals Erratum dated 18-2-1967 and Notification No. S.O. 3998 dated 21-12-1966.

Ex. N-6 Receipts of Notifications.

Ex. N-7 Letter dated 16-4-1973 from Shri Brijnandan Sharma, Amin, N.C.D.C. Ltd., Ramgarh Project, to the Officer Incharge, Ramgarh P. S., Ramgarh (Hazaribagh).

Ex. N-8 Part Master Plan of Bihar showing the Ramgarh Area.

Ex. N-9 Map of Ramgarh Block II.

Ex. N-10 Letter No. 3113-M, dated 19-6-1974 from Shri K. K. L. Das, Distt. Mining Officer, Hazaribagh to the Manager, Mael Colliery.

Ex. N-11 Letter dated 30-4-1974, from Shri G. M. Khanna, O/I, Ramgarh, to the Manager, Mael Colliery.

Ex. N-12 Letter No. Manager/Mael/75/1005, dated 3-4-1975, from Shri Krishna Mohan Singh, Manager, Mael Colliery to the Officer-in-charge, P. S. Ramgarh.

Ex N-13 (i) Notification S.O. 881 dated 13th April, 1961.

(ii) Notification S.O. 3894 dated 22-12-1962.

(iii) Papers relating to taking of possession u/s 12 of the said Act in respect of Ramgarh Block I.

(iv) Vesting Order issued vide No. C2-20(15)/62, dated 18-12-1963 in respect of S.O. 3894 dated 22-12-1962 in respect of Ramgarh Block I.

(v) Notification S.O. 3998 dated 21-12-1966.

(vi) Papers relating to taking of possession u/s 12 of the said Act in respect of Ramgarh Block II and III.

(vii) F.I.R. dated 14-4-1973 lodged by Shri B. N. Sharma, Amin, to the Officer Incharge, Ramgarh P. S. along with receipt thereof.

Ex. N-14 Plan of the site of accident.

II. Filed on behalf of the United Coal Workers' Union.

Ex. U-1 Letter dated 28-2-1975 from Shri Punit Ram Ohdar alias Gobind Mahato, Mukhiya, Gram Panchayat, Kothar, to the Deputy Commissioner, Hazaribagh.

Ex. U-2 Pamphlet dated 1-3-1975 issued by Shri Puran Ram Sahu, Mantri, Communist Party of India, Local Committee, Patratoo.

III. Filed on behalf of the D.G.M.S.

Ex. D-1 Letter No. RSR/566, dated 28-2-1975 from Shri Inderjit Khosla, Deputy Director of Mines Safety, Ramgarh Sub-Region, Naisarai, Distt. Ramgarh, Cantt Hazaribagh, to the Officer-in-charge, Ramgarh Police Station/Gomia Police Station.

IV. Filed on behalf of District Authority

Ex.-B-1 Copy of Notification, dated 14-3-1961 u/s 4 of of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 in respect of lands comprising of Ramgarh Coal Field Block I, Block II and Block III including village Dahawaiya, P. S. Gomia.

Ex. B-2 Notification dated 21-2-1966, S.O. 3998 u/s 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 declaring acquisition of land measuring 2,230 acres and 821.50 acres described in the Schedule appended and rights to mine, quarry, bore, dig and search for etc. in the land measuring 1505 acres and 3222.50 acres in Ramgarh Block I and Block II along with maps in two sheets and S.O. 634 dated 18-2-1957 making some corrections in certain notification—notification in 23 sheets and Map 2 sheets.

Ex. B-3 Copy of Notification S.O. No. 3400 dated 27-11-1973 U/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in respect of 121 acres of land as Extension to Ramgarh Block II in villages Samarbera, Kander and Saraiya.

Ex. B-4 Master Plan showing collieries and Coal Areas of Central Division C.M.A. Ltd. in E. Bokaro, W. Bokaro, Ramgarh and Karanpura Coal Field, Map dated 6-3-1974 drawing No. PL/8485.

Ex. B-5 Master Plan showing the Collieries and Coal lands acquired u/s 9(1), notified u/s 4 and 7 of the Coal Act and Nationalised under the Nationalisation Act and their Sand Areas in the distirct Giridih.

Ex. B-6 Copy of letter No. Manager/Mael/74/1186-96, dated 18-4-1974 from the Manager Mael Colliery to the District Mining Officer, Hazaribagh.

Ex. B-7 Copies of two petitions of complaints filed by District Mining Officer, Hazaribagh, before the Chief-Judicial Magistrate, Hazaribagh on 25-5-1974.

Ex. B-8 Copy of the compromise decree in Suit No. 51 of 1963 between Raj Ballabh Singh and Union of India, M/s. N.C.D.C. Ltd., & others along with petition of compromise Misc. appeal No. 9/65 before the Hon'ble High Court, Patna filed by the parties of the original suit No. 51 of 1963.

Ex. B-9 Charts indicating action taken by District Authorities, Giridih and Hazaribagh to check illegal coal mining in Giridih District.

Ex. B-10 Plan showing the site of accident and position of incline No. 11 A/11 B of Mael Colliery.

Ex. B-11 Copy of letter dated 31-1-1964 with enclosures from Shri S. C. Kumar, Director of Administration, M/s. N.C.D.C. Ltd., to the District Mining Officer, Hazaribagh.

Ex. B-12 copy of letter dated 4-9-1965 with enclosure from Shri H. N. Joshi, Deputy Chief Revenue, M/s. N.C.D.C. Ltd., to the District Mining Officer, Hazaribagh.

Ex. B-13 Letter D.O. No. LA/G-XXXII-17/64-615 dated 15/20th March, 1965 from Shri S. T. Raja, Managing Director, N.C.D.C. Ltd., to Deputy Commissioner, Hazaribagh.

Ex. B-14 Copy of Treasury challan No. 123, dated 24-3-1965 showing deposit of Rs. 2,94,460.43 on account of prospecting fee.

Ex. B-15 Minutes of meeting held on 2-4-1975 in the Chamber of Deputy Commissioner, Giridih.

Ex. B-16 Copy of minutes of meeting held on 27-2-1975 at Ranchi in the Office of N.C.D.C. Ltd.

Ex. B-17 Copy of F.I.R. in Gomia P. S. Case dated 23-2-1975.

Ex. B-18 Statement of Chowkidar Bideshi Dushad of village Chitarpur, P. S. Ramgarh, Distt. Hazaribagh recorded on 23-2-1975 at 02.00 hrs. by Shri R. S. Singh, Officer-in-charge Ramgarh P. S. in the Mael Colliery area, P. S. Ramgarh.

Ex. B-19 Letter No. 709/N, dated 6-6-1975 from Shri C. Chaturvedi, Distt. Mining Officer, to the Deputy Chief of Revenue, M/s. N.C.D.C. Ltd., Darbhanga House, Ranchi reg. payment of Dead Rent and other papers.

Ex. B-20-Copy of the map attached with the petition of compromise in Misc. Appeal No. 9 of 1965 before the Hon'ble High Court, Patna filed by the parties to the original suit i.e. 51 of 1963.

Ex. B-21 Certified copy of the order sheet of Case No. 9 of 1974 of the Court of Chief Judical Magistrate, Hazaribagh.

[No. N-11015/8/75-MI]

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976

का० आ० 1067.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम, 16 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना (संख्या का०आ० 3592 तारीख 13 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी, में, अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात

I	II
यू०एस०एस०आर०	खान इंजीनियरी में डिप्लोमा।"
"1. यूनिवर्सिटी, मास्को पैट्रिक लुमुम्बा पिपुल्स फ्रेंडशिप	

[सं० एस० 66025/1/75-एम०आई(i)]

New Delhi, the 24th February, 1976

S.O. 1067.—In pursuance of the provision of regulation 16 of the Coal Mines Regulations, 1957, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 3542 dated the 13th November, 1962, namely :—

In the Table appended to the said notification, the following shall be inserted at the end namely :—

I	II
"1. U.S.S.R. Patric Lumumba Peoples' Friendship University, MOSCOW.	Diploma in Mining Engineering. "

[No. S. 66025/1/75-M. I (i)]

का० आ० 1068.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 17 के परन्तुक के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1599 तारीख 28 जून, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, "विदेश" शीर्षक के नीचे, मद 33 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

I	II
"34 पैट्रिक लुमुम्बा पीपुल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को, (यू०एस० एस०आर०)	खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा"

[सं० एस० 66025/1/75-एम०आई०(ii)]

S.O. 1068.—In pursuance of the proviso to regulation 17 of the Coal Mines Regulations, 1957, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1599, dated the 28th June, 1961, namely :—

In the Table appended to the said notification, under the heading "FOREIGN" after item 33 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:

I	II
"34. Partic Lumumba Peoples' Friendship University, MOSCOW, (U.S.S.R.)	Diploma in Mining Engineering".

[No. S. 66025/1/75-M. I(ii)]

का०आ० 1069.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनयम, 1957 के विनियम 18 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1261 तारीख, 23 अप्रैल, 1963 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

(1)	(2)
यू०एस०एस०आर० "पैट्रिक लुमुम्बा पीपुल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को	खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।"

[सं० एस० 66025/1/75-एम०आई० (iii)]

जे०सी० सक्सेना, अवर सचिव

S.O. 1069.—In pursuance of the provisions of regulation 18 of the Coal Mines Regulations, 1957, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. SO. 1261 dated the 23rd April, 1963, namely :—

In the Table appended to the said notification, the following shall be inserted at the end namely :—

1	2
U.S.S.R. "1. Patric Lumumba Peoples' Friendship University, MOSCOW.	Diploma in Mining Engineering".

]No. S. 66025/1/75-M.I. (iii)]

J. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का०आ० 1070.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1286 तारीख 27 मई, 1961 को अधिक्रान्त करते हुए महाराष्ट्र राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :—

अध्यक्ष

1. सचिव महाराष्ट्र सरकार उद्योग और श्रम विभाग, मुम्बई	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त
2. श्रमायुक्त, मुम्बई 3. उप-सचिव, महाराष्ट्र सरकार, वित्त, विभाग, मुम्बई	राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ।
4. श्री राम एस० तारनेजा, सहायक महाप्रबन्धक, बेनेट कोलमैन एण्ड कं० लि०, टाइम्स आफ इंडिया बिल्डिंग, डा० डी०एन० रोड, मुम्बई 5. श्री वाई०ए० फजलभाई, 532 सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड, मुम्बई-400007 6. श्री एस० हेबले, सैंडहर्स्ट, कार्मिक महाप्रबन्धक, किलिक निक्सन लिमिटेड चरणजीत राय मार्ग, मुम्बई- 400001	राज्य में नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों के तीन प्रतिनिधि।
7. श्री जी०एस० खोडे, उपाध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, महाराष्ट्र शाखा, वार्ड संख्या 28, इतवारी, नागपुर 8. श्री जी०पी० कौटोन्हो, संट पायस को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी भवन, ए-फ्लैट संख्या 8, नाल्हर रोड, मुलुन्द (पूर्वी) मुम्बई 400080. 9. श्री मोहन राय महासचिव नेशनल रेयरन कार्पोरेशन कर्मचारी संघ पी०डी० मैल्लो भवन, पी०डी० मैल्लो रोड, मुम्बई-400001	राज्य में कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधि ।
10. डा० मोहन लाल पीरामल, पीरामल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, सेना और नौसेना भवन महात्मा गांधी रोड मुम्बई 400023 11. श्री वी०आर० होर्णिग, महासचिव, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, मजदूर मंजिल, जे०डी० अम्बेडकर मार्ग, परेल, मुम्बई-400012 12. श्री एच०पी० मर्चेन्ट, शक्ति विला भूखण्ड, लेबर्नम रोड, गामदेवी, मुम्बई-400007	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के अणासकीय सदस्य जो सामान्यतः महाराष्ट्र राज्य के निवासी हों ।

[संख्या डी-20012(3)/72-पी०एफ-2]

New Delhi, the 23rd Feb., 1976

S.O. 1070.—In pursuance of sub-paragraph (1) of Paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment number S.O. 1286 dated the 27th May, 1961 the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Maharashtra consisting of the following persons, namely :—

CHAIRMAN

1. The Secretary to the Government of Maharashtra, Industries and Labour Department, Bombay.	Appointed by the Central Government.

MEMBERS

2. The Commissioner of Labour, Bombay. 3. The Deputy Secretary to the Government of Maharashtra, Department of Finance, Bombay.	Persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government.
4. Shri Ram S. Tarneja, Associate General Manager, Bennett Coleman and Company Limited, Times of India Building, Dr. D.N. Road, Bombay-400001. 5. Shri Y.A. Fazalbhoy, 532, Sardar Vallabhai Patel Road, Sandhurst Bridge, Bombay-400007. 6. Shri S. Heble, Personnel Manager, Killick Nixon Limited, Charanjitrai Marg, Bombay-400001.	Representatives of employers appointed by the Central Government in consultation with the organisations of employers in the State.

7. Shri G.M. Khode, Vice President, Indian National Trade Union Congress, Maharashtra Branch, Ward No. 28, Itwari, Nagpur.	Representative of employees appointed by the Central Government in consultation with the organisations of employees in the State.
8. Shri G.P. Courinho, St. Pius X Cooperative Housing Society, Building, 'A', Flat No. 8, Nathur Road, Mulund (East) Bombay-400080.	
9. Shri Mohan Rao, General Secretary, National Rayon Corporation Employees' Union P.D.' Mello Bhevan, P.D.' Mello Road, Bombay 400001.	
10. Dr. Mohanlal Piramal, Piramal Spinning and Weaving Mills Limited, Army and Navy Building Mahatma Gandhi Road, Bombay-400023.	Non-Official members of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, Ordinarily resident in the State of Maharashtra.
11. Shri V.R. Hoshing, General Secretary Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, Mazdoor Manzil, G.D. Ambekar Marg, Parel, Bombay-400012.	
12. Shri H.P. Merchant, Shakti Villa, Ground Floor, Laburnam Road, Gamdevi, Bombay-400007.	

[No. V. 20012(3)/72-PF.II]

का० आ० 1071.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1703 तारीख 29 जून, 1960 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक प्रादेशिक समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :—

अध्यक्ष

1. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, लखनऊ	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

सदस्य

2. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, लखनऊ	राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ।
3. उप-सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, लखनऊ	
4. श्री बी०एस० अग्रवाल, सचिव, मेसर्स जे०के० संगठन, कमला टावर, कानपुर	केन्द्रीय सरकार, द्वारा राज्य में के नियोजकों के संगठन के परामर्श से, नियुक्त नियोजकों के प्रतिनिधि
5. श्री बी०पी० खेतान, खेतान हाउस, पडरौना, जिला देवरिया	
6. श्री हरीलाल, लेखा अधिकारी (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन	
7. श्री के० दास गुप्ता, 171-जे० आबू लेन, मेरठ छावनी	केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य में कर्मचारियों के संगठन के परामर्श से, नियुक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधि ।
8. श्री जे०आर० त्रिपाठी, गांव बाड़ी गांव मोहगौरा, डाकघर-कोड़ीराम, जिला गोरखपुर ।	
9. श्री वासुदेव पाण्डे, कोषपाल, उत्तर प्रदेश व्यवसाय संघ कांग्रेस, 7-विश्वेश्वरनाथ मार्ग, लखनऊ	
10. श्री बिमल मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा, 25-ख सर्वोदय नगर, कानपुर ।	कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का प्रशासकीय सदस्य जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हो ।

[संख्या वी-20012(11)/72-पी०एफ-2]

S.O. 1071.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment number S.O. 1703 dated the 29th June, 1960, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Uttar Pradesh consisting of the following persons namely :—

CHAIRMAN	
The Secretary to the Government of Uttar Pradesh Department of Labour, Lucknow.	Appointed by the Central Government.
MEMBERS	
2. Joint Secretary to the Government of Utta Pradesh Department of Labour, Lucknow.	Persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government
3. Deputy Secretary to the Government of Uttar Pradesh Department of Finance, Lucknow.	
4. Shri B.S. Agarwal, Secretary, Messrs, J.K. Organisation Kamla Tower, Kanpur.	Reresentatives of employers appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employers in the State.
5. Shri B.P. Khetan, Khetan House, Padrauna Distt. Deoria.	
6. Shri Hari Lal, Accounts Officer Head Quarters Uttar Pradesh State Road, Transport Corporation, Tehri Kothi, Lucknow.	
7. Shri K. Dasgupta, 171, J. Abu Lane, Meerut Cantt.	Representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employees in the State.
8. Shri J.R. Tripathi, Village Bari Gaon, Sonagaura, Post Office Kauri Ram, Distt. Gorakhpur.	
9. Shri Basudeo Pande, Treasurer, Uttar Pradesh Trade Union Congress, 7, Visheshwarnath Road, Lucknow.	
10. Shri Vimal Mehrotra, Vice President, Hind Mazdoor Sabha, 25 B, Sarvodaya Nagar, Kanpur.	Non official member of Central Board of Trustees Employees Provident Fund Ordinarily resident in the State of Uttar Pradesh.

[No. V. 20012(11)/72.PF.II]

का०आ० 1072.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप पैरा (1) के अनुसरण (में तथा भारत सरकार के भतपूर्व श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 1245 तारीख 14 अप्रैल, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, केरल राज्य के लिए एक प्रादेशिक समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :—

अध्यक्ष

1. सचिव, केरल सरकार, श्रम विभाग, त्रिवेन्द्रम ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

2. सदस्य :

उप सचिव, (साधारण) केरल सरकार वित्त विभाग त्रिवेन्द्रम 3. संयुक्त सचिव, केरल सरकार श्रम विभाग, त्रिवेन्द्रम ।	राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति ।
4. श्री एस० करूविला, मैसर्स हैरिसन्स एण्ड क्रासफील्ड लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 502, कोचीन-3 5. श्री ए०बाल कृष्ण मैनन, दी मालाबार टाइल वर्क्स, फरोक (केरल) 6. श्री के० गोपीनाथन नायर, काजू निर्यातकर्ता पोस्ट बाक्स नं० 101, क्विलोन-1 (केरल)	राज्य में के नियोजकों के संगठन के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, नियोजकों के प्रतिनिधि ।
7. श्री ए० संकरन, अधिवक्ता भारतीय राष्ट्रीय व्यवसाय संघ, कांग्रेस, कार्यालय वाई०एम० सी०ए० रोड, कालीकट, 8. श्री पी०के० भास्करन, केरल राज्य व्यवसाय संघ, परिषद नवयुगम भवन, पूर्वी थाम्पनूर, त्रिवेन्द्रम-14 9. श्री टी० एम० प्रभा अश्रमम डाक घर, क्विलोन-691002	राज्य में के कर्मचारी संगठन के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, कर्मचारियों के प्रतिनिधि ।

[सं० वी-20012(2)/73-पी०एफ० II]

S. O. 1972.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employ nent) number S.O. 1245 dated the 14th April, 1966, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Kerala consisting of the following persons, namely :—

CHAIRMAN

1. The Secretory to the Government of Kerala, Labour Department, Trivandrum.	Appointed by the Central Government.

MEMBERS

2. Deputy Secreatry (General) to the Government of Kerala Finance Department, Trivandrum. 3. Joint Secretary to the Government of Kerala Labour Department, Trivandrum.	Persons appointed by the central Government on the recommendation of the State Government.
4. Shri S. Kuruvilla, Messrs. Harrisons and Grossfield Limited, Post Box No. 502, Cochin-3. 5. Shri A. Balakrishna Menon, The Malabar Tile Works, Feroke. (Kerala). 6. Shri K. Gopinathan Nair, Cashew Exporter, Post Box No. 101, Quilon-1, Kerala.	Representatives of employers appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employers in the State.
7. Shri A. Sankaran, Advocate, Indian National Trade Union Congress, Office YMCA Road, Calicut. 8. Shri P.K. Bhaskaran, Kerala State Trade Union Council Navayugom Building, East Thampanoor, Trivandrum-14. 9. Shri T.M. Prabha, Asramam Post office Quilon-691002.	Representatives of employees a pointed by the Central Government in consultation with the Organisation of employees in the State

[No. V 20012(2)/73-PF.II]

का०आ० 1072.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में और भारत के भूतपूर्व श्रम और रोजगार की अधिसूचना सं० का० आ० 3450 तारीख 16 अगस्त, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :—

अध्यक्ष :

1. सचिव (श्रम) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

सदस्य :

2. संयुक्त उद्योग निदेशक, दिल्ली प्रशासन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली 3. श्रम उपायुक्त, 15, राजपुर रोड, दिल्ली	राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति ।
4. श्री हरिकृष्ण गुप्ता, विक्टर केबल्स कारपोरेशन, 802, जोशी रोड, नई दिल्ली 5. श्री बी०पी० गुप्त, औद्योगिक सम्बन्ध सलाहकार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मण्डल, फेल्पस बिल्डिंग, 9 ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली । 6. श्री एस० के० जगतानी, बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, बिड़ला लाइन, दिल्ली-110007	राज्य में के नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, नियोजकों के तीन प्रतिनिधि ।
7. श्री जे०आर० नारंग, बी 19 एच० आई०एल० टाउनशिप, न्यू मोतीनगर, नई दिल्ली-15 8. श्री सुरेन्द्र बाली, होटल मजदूर यूनियन, (रजिस्ट्रीकृत) स्टाल सं० 167, पचकुइयां रोड, नई दिल्ली । 9. श्री सुशील भट्टाचार्य, 780, बल्लीमारान, दिल्ली	राज्य में के कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि ।
10. श्री पी० चेंटसल राव, महा सचिव, अखिल भारतीय कर्मचारी संगठन, नई दिल्ली ।	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकीय सदस्य, जो साधारणतः दिल्ली के निवासी हों ।

[सं० वी-20012(3)/74-पी०एफ 2]

S.O. 1073.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Department of Labour and Employment No. S.O. 3450 dated the 16th August, 1971, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the Union Territory of Delhi, consisting of the following persons, namely :—

CHAIRMAN

1. The Secretary (Labour), Delhi Administration, Delhi.	Appointed by the Central Government.

MEMBERS

2. Joint Director of Industries Delhi Administration, Indra Prastha Estate, New Delhi. 3. Deputy Labour Commissioner, 15, Rajpuar Road, Delhi.	Two persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government.

4. Shri Hari Krishan Gupta, Victor Cables Corporation, 802, Joshi Road, New Delhi. 5. Shri B.P. Gupta, Industrial Relations Adviser, Punjab Haryana and Delhi Chamber of Commerce and Industry Phelps-Building 9A, Connaught Place, New Delhi. 6. Shri S.K. Jagnani, Birla Cotton Spinning and Weaving, Mills Limited, Birla Line, Delhi-110007.	Three representatives of employers appointed by the Central Government in consultation with the Organisations of employers in the State.
7. Shri J.R. Narang, B/9, H.I.L. Township, New Motinagar, New Delhi-15. 8. Shri Surendra Bali, C/o Hotel Mazdoor Union (Registered) Stall number 167, Panchkuin Road, New Delhi. 9. Shri Sushil Bhattacharya, 780, Ballimaran, Delhi-110006.	Three representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with Organisations of employees in the State.
10. Shri P. Chentsal Rao, Secretary General, All India Organisation of Employers, Federation House, New Delhi.	Non official member of Central Board of Trustees, Employees Provident Fund, Ordinarily resident in Delhi.

[No. V. 20012(3)/74-PF.II]

का०आ० 1074—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः मास के अवसान पर या के पश्चात् करने के अपने आशय की सूचना देती है।

अनुसूची

स्थापनों का वर्णन	क्षेत्र जहां स्थापन स्थित है
1	2
निम्नलिखित स्थापन, जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्वगामी बारह महीनों में किसी दिन मजदूरी पर नियोजित किए गए थे अर्थात्:—	
(i) भारतीय पर्यटन विकास निगम, लिमिटेड नई दिल्ली, के होटल	सम्पूर्ण भारत
(ii) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित दिल्ली परिवहन निगम।	दिल्ली

[फा० सं० एस०-38011/2/75-एच० I]
एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

S.O. 1074.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby gives notice of its intention to extend the provisions of the said Act to the establishments specified in the Schedule annexed hereto on or after the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Description of establishments	Areas in which the establishments are situated
1	2
The following establishments wherein twenty or more persons are employed, or were employed, for wages on any day of the preceding twelve months, namely :	
(i) Hotels owned by the India Tourism Development Corporation limited, New Delhi.	Whole of India
(ii) Delhi Transport Corporation set up under section 3 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950).	Delhi

[F. No. S-38011/2/75-HI]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

का०आ० 1075.—केन्द्रीय सरकार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित अधिकारियों को, किसी रेल मार्ग पर (किसी कारखाना में से अन्यथा) नियोजित ऐसे सभी व्यक्तियों की बाबत जिन्हें, उक्त अधिनियम लागू होता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निरीक्षक नियुक्त करती है, अर्थात :—

(1) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय);
(2) सभी उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय);
(3) सभी प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय);
(4) सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय);
(5) सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)

[सं० एस-31025/14/74-एल०आर III (डब्ल्यू सी)]
हंस राज छाबरा, उप सचिव

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1075.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) read with section 24 of that Act and in supersession of all previous notifications, the Central Government hereby appoints the following officers as Inspectors for the purposes of the said Act, in respect of all persons employed upon a railway (otherwise than in a factory) to whom the said Act applies, namely :—

1. The Chief Labour Commissioner (Central);
2. All Dy-Chief Labour Commissioners (Central);
3. All Regional Labour Commissioners (Central);
4. All Assistant Labour Commissioners (Central);
5. All Labour Enforcement Officers (Central).

[No. S-31025/14/74-LRIII(WC)]
HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1076.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial dispute between the employers

in relation to the management of the Cantonment Board, Bareilly and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th February, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER INDUSTRIAL TRIBUNAL (III) U.P. AT KANPUR

Adj. Case No. 8 of 1975 (Central)

PRESENT :

Sri K. N. Srivastava ..Presiding Officer

In the matter of an industrial dispute The Executive Officer, Cantonment Board, Bareilly.

Versus

Their workman through the President Cantonment Labour Union, 99, Sadar Bazar, Bareilly.

APPEARANCES :

For the employers.—(1) Sri P. R. Balakrishna, Executive Officer, Cantonment Board, Bareilly.

(2) Sri Mohbood Hasan, Office Superintendent of the Board.

For the workman.—Sri A. C. Malhotra, President of Cantonment Labour Union, Bareilly.

Industry : Cantonment Board District : Bareilly.

Dated : February 12, 1976

AWARD

By Notification No. L-13012(1)/75-D. IIB dated 14th August, 1975, Government of India, Ministry of Labour, referred the following matter of dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) :

THE SCHEDULE

"Whether the action of the Cantonment Board, Bareilly in reinstating Shri Lalta Prasad as Assistant Sanitary Inspector, instead of as Sanitary Inspector, as justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

The dispute in this case is as to whether Cantonment Board, Bareilly was justified in reinstating Sri Lalta Prasad as Assistant Sanitary Inspector, instead of Sanitary Inspector. If not, to what relief the workman concerned is entitled?

In support of its case the union filed Ex. W-1, a copy of the resolution of the Board dated 25-5-1970, which shows that Sri Lalta Prasad Assistant Sanitary Inspector was promoted as Sanitary Inspector and was entitled to the scale of Sanitary Inspector. Ex. W-2 is the copy of Resolution No. 8 dated 28-10-71 of the Cantonment Board reinstating Sri Lalta Prasad. Ex. W-3 is the dissent note by Mohd. Farid a member of the Board. Ex. W-4 is the order of the Executive Officer, Cantonment Board, Bareilly vacating the suspension order and ordering Sri Lalta Prasad to work on the post of Assistant Sanitary Inspector. Ex. W-6 also show that Sri Lalta Prasad was not guilty of any charge.

The Board contended that Sri Lalta Prasad was appointed as Assistant Sanitary Inspector and he officiated as Sanitary Inspector from 11-9-68 till 1971. According to the Board Sri Lalta Prasad was suspended on 23-1-1971 and when he was reinstated he was posted to his substantive post. He was also ordered to pay Rs. 1,000 from his salary in 24 equal instalments and if he was also ordered that he will not get any salary for the suspension period except the subsistance allowance paid to him. The representative of the employer gave a statement on paper No. 3/C on 19-1-1976 that the Board will not lead any oral evidence. Sri Lalta Prasad examined himself and Mohd. Farid.

The Board also filed number of documents. Ex. E-1 is the copy of Resolution No. 8 dated 28-10-71. Ex. E-2 is the finding of the Committee dated 17-8-71. This resolution was dissented by Mohd. Farid. Ex. E-2 also bears the recommendation of the Committee to revert Sri Lalta Prasad to his substantive post and ordering him to pay Rs. 1000 as compensation in 24 instalments and also recommending that he will not get any salary except the subsistence allowance for the period of suspension. Ex. E-3 is the copy of resolution No. 10 dated 28-10-71 appointing Sri Ashok Kumar Gupta as Sanitary Inspector.

There is no dispute between the parties as to the fact that Sri Lalta Prasad was exonerated of the charge and was reinstated. The only question is whether he should have been reinstated as a Assistant Sanitary Inspector or as a Sanitary Inspector. Ex. W-1 is very relevant document in this connection. It is a copy of Resolution No. 11 dated 25-5-1970. The resolution reads as below :—

"Resolved that officiating promotion of Shri Lalta Prasad, Asstt. Sanitary Inspector be made as Sanitary Inspector (qualified) from the date he is working as Sanitary Inspector and he be paid in the scale of S.I. (Qualified) for the whole period accordingly.

After the Board has passed the above resolution and had confirmed Sri Lalta Prasad as Sanitary Inspector could the board after his reinstatement post him as Assistant Sanitary Inspector particularly when there are number of documents such as Ex. W-6, to show that Sri Lalta Prasad was not guilty of any charge. It is admitted that at the time of suspension Sri Lalta Prasad was working as a permanent Sanitary Inspector. The contention of the Board is that Sri Lalta Prasad did not possess the necessary qualification for appointment as a Sanitary Inspector, i.e. he had not passed intermediate examination or obtained diploma in sanitary side. It is admitted that Sri Lalta Prasad was appointed as Assistant Sanitary Inspector in 1948. The Notification which lays down the minimum qualification of Sanitary Inspector would not apply to Sri Lalta Prasad who was appointed as Assistant Sanitary Inspector in 1948. Besides this vide Resolution No. 11 dated 25-5-70 the Board by unanimous resolution promoted Sri Lalta Prasad as Sanitary Inspector and waive off the qualification bar. By this resolution it was also decided that Sri Lalta Prasad would get the scale of Sanitary Inspector for the period he was officiating as Sanitary Inspector. This paper leaves no room for doubt that the Board by this resolution appointed Sri Lalta Prasad as Sanitary Inspector and it is also clear that at the time of suspension Lalta Prasad was working as Sanitary Inspector. The action of the Board in suspending Lalta Prasad was not justified or legal because Lalta Prasad was not found at fault about the maintenance of the register and as the papers go to show after great scrutiny only some clerical mistakes were found in his register. The Sub-committee was therefore not justified in ordering Sri Lalta Prasad to pay Rs. 1,000 as compensation. The dissent note of Sri Farid was, therefore, correct. No doubt, now the Board has appointed Sri Ashok Kumar Gupta as Sanitary Inspector but this appointment was made the same day on which Sri Lalta Prasad was reinstated. Therefore, it cannot be said that when Sri Lalta Prasad was re-instated there was no vacancy in the Board of the post of Sanitary Inspector. When the Board decided to exonerate Sri Lalta Prasad and to reinstate him the Board was not justified in appointing another person as Sanitary Inspector the same day. On the principle of natural justice Sri Lalta Prasad should not have been demoted on mere conjecture without giving him any chance or without framing any charge and to meet the same. I am, therefore, of the opinion that the action of the Board in re-instating Sri Lalta Prasad as Assistant Sanitary Inspector was not justified.

It is, therefore, awarded that Sri Lalta Prasad is entitled to the post of Sanitary Inspector from the date of his re-instatement. He is also entitled to arrears to pay from the date of his suspension till the date of his re-instatement.

Cost easy.
Dated 12-2-76

K. N. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-13012/1/75/D II(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

New Delhi, the 5th March, 1976

S.O. 1077.— In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management

of West Bokaro Colliery P.O. Ghatotand Distt. Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st February, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri K. K. Sarkar, Judge, Presiding Officer.

Reference No. 6 of 1974

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

ORDER OF REFERENCE

(Ministry's Order No. L-20012/170/73-LR. II dt. 29-1-1974)

PARTIES :

Employers in relation to the management of West Bokaro Colliery, P.O. Ghatotand, Distt. Hazaribagh.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the Employers : Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen : Shri B. Lal, Advocate.

State : Bihar Industry : Coal

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour sent the above Reference to this Tribunal for adjudication of the Industrial Disputes involved with the following issues framed :—

"(1) Whether the management of West Bokaro Colliery, P.O. Ghatotand, Distt. Hazarigabh, was justified in dismissing Shri Naqui Ashraf, Car and Lorry Driver from the 16th July, 1973.

(2) If not, to what relief is the workmen entitled?"

The case of the employers is that it was reported on 22.5.73 at about 11 P.M. that Shri Naqui Ashraf the concerned workmen entered the office compound and unauthorisedly took out the truck No. BRM. 7168 of the Company on the plea that he was going for Police duty. He, however, loaded cement, Iron rods and pipe fitting on the above truck near his quarter and went out of the Check post falsely stating to the watchmen on duty that he was going to Jamadoba. He was apprehended the same night and taken into police custory at Hazaribagh and the truck with the materials as mentioned above was seized by the Police. The concerned workman was chargesheeted for unauthorised use of the Company's truck in the manner stated as above. He replied to the chargesheet denying the charge. An enquiry was fixed on 19.6.73 but it was adjourned to 26.6.73 at the instance of the concerned workmen. The concerned workman did not turn up at the enquiry and it was held ex parte. In departmental enquiry the misconduct as mentioned in the chargesheet was satisfactorily established and the concerned workman was dismissed w.e.f. 16.7.73. The workmen deny the allegations against the concerned workman. According to them the departmental enquiry was held in hot haste. The concerned workmen fell ill and was under the treatment of Civil Assistant Surgeon, Sadar Hospital, Hazaribagh. His application for adjournment of the enquiry to be held on 26.6.73 was not considered and the enquiry was held ex parte in violation of the principle of natural justice. It is alleged that the management illegally dismissed the concerned workman from service and he was not reinstated inspite of the demand made.

Admittedly the concerned workman took out the Truck from the Garage of the Company at about 11 P.M. and admittedly the truck was seized by Hazaribagh Police with some building materials on it and the concerned workman was arrested. The case of the management is that the concerned workman entered the office compound and unauthorisedly took out Truck No. BRM. 6176 on the plea that he was going for police duty. The case of the workman at the time of hearing is that he was building his house at Hazaribagh before the incident. He purchased some building materials which were lying in the open in Chari more. To prevent those materials from getting spoilt in the rains he met Sri Ashok Kumar who is the Junior Automobile Engineer of the Company and requested him to lend him a lorry to transport those materials. Sri Ashok Kumar issued him a permit for the purpose in respect of the Truck No. BRM 7168. He produced the permit to the gateman Ganga Prasad who gave him the key of the vehicle and thereafter he took over the vehicle. His further case is that Sri Ashok Kumar accompanied him upto the gate. The concerned workman has tried to make out a case before me that vehicles can be taken out of the main gate on permits issued by an officer and when no such permit is issued, the gateman has to sign the maingate register. I may state here that the law of pleading applies in industrial adjudication. The parties have to confine their cases within the four corners of the written statement filed by them. No party can be allowed to introduce a new case at the time of hearing and the case which has not been pleaded in the written statement cannot be allowed to be introduced and/or cannot be considered. What is the case pleaded in the written statement of the management. It is that on 22-5-73 at about 11 p.m. Shri Naqui Ashraf entered the office compound and unauthorisedly took out truck No. BRM. 7168 of the Company on the plea that he was going for police duty. He went out of the check post falsely stating to the watchman on duty that he was going to Jamadoba. What case has been pleaded by the workman in their written statement? They have only pleaded that the concerned workman was authorised to take the truck. His main grievance in the written statement is that the enquiry was held ex parte violating the priniciples of natural justice. It has not been pleaded in the written statement that he got a permit from Sri Ashok Kumar (MW. 2) to take out the vehicle for his private purpose. He has not stated that he produced the permit in the gate or that Sri Ashok Kumar accompanied him upto the gate. So this line of the case taken for the first time at the time of hearing and which was not pleaded in the written statement cannot be taken into consideration. Even then let me examine the matter in the light of his new case that he got a chit from Sri Ashok Kumar for taking out the vehicle and that he produced the chit at the gate to the gateman Sri Ganga Prasad and that Sri Ashok Kumar accampanied him upto the gate. Shri Ashok Kumar (M.W. 2) was examined by the Company and he denies that he ever issued any permit to the concerned workman to take out the vehicle or he accompanied him upto the main gate. MW.3 Ganga Prasad was the Security Guard at the main gate. He says that the gave out to him that he was taking out the vehicle for police duty and he allowed it to be taken out after making necessary entry in the register (Ext. M.11). He denies that the driver produced a chit to him for taking out the lorry. Then comes the check post through which the vehicles had to pass. MW.4 Shri Bhim Bahadur was the gateman on duty. His evidence is that the driver on being asked by him gave out that he was going to Jamadoba. He made necessary entry in the registar maintained by him (Ext. M. 12). So the case of the concerned workman upon which he takes his stand before me is not supported by the gateman at the main gate or at the check post. Another point taken before me by the workman is that when no permission chits are issued, the driver has to sign the register at the gate and in this case there is no signature of the concerned workman. This is not the defence taken in this case. So I need not enter into the fact if the driver has to sign the register when no permits chits are issued. The statement of the concerned workman (WW. 1) that when no permit chits are issued, the vehicle is allowed to be taken out after obtaining driver's signature goes to show that vehicles can also be taken out without permit chits. This corroborates the case of the management that vehicles can be taken out without production of permit chits. The learned Advocate for the workman submits that the company has given up their charge that the driver loaded cement etc. on the truck within the check post. I do not think that a party is debarred under the law to give up any part of their case for reasons of their own. It is also submitted that cement was not a controlled article at the relevent time. It is not necessary for me to enter into this question for the purpose of his case. A criminal case is pending for violation of essential Commodities Act and this question may be rele-

vant there. The workmen have not examined any other witness except the concerned workman in support of their case that he got a permit from Sri Ashok Kumar and that he produced the chit at the gate. The management has examined Shri Ashok Kumar (M.W. 2), Sri Sinha, the Security Inspector (M.W. 3), the gateman (M.W. 4) at the main gate and the gateman (M.W. 5) at the check post in support of their case and I see no reason to disbelieve them.

The net result, therefore, comes to this that in the written statement the workmen have not pleaded that he obtained a permit from Sri Ashok Kumar to take out the vehicle for his private purpose and that he produced the chit at the gate. Then again he has not satisfactorily proved by independent evidence that Sri Ashok Kumar issued him a chit and he produced the chit at the gate. The management has proved their case by 4 competent witness. The case of the management has thus been made out and the case of the workman has not been made out. It appears from the service Card that the concerned workman was warned a number of times in the past for his delinquency and I cannot therefore question the adequacy of the punishment meted out to the concerned workmen.

In the result, the management of West Bokaro Colliery, P.O. Ghatotand, Dist. Hazaribagh, was justified in dismissing Shri Naqui Ashraf, Car and Lorry Driver from the 16th July, 1973. He is, therefore, entitled to no relief.

This is my Award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer,

[F. No. L-20012/17/73-D.D. III(A)]

R. P. NARULA, Under Secy.

Dhambad, the 16th February, 1976

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.